RNI No. DELHIN/2022/85477 | पेज - 32

SDGs की जागरूकता के लिए संकल्पबद्ध

विकास की पत्रकारिता का अग्रदूत

ब्लिट्ज इंडिया

BlitzINDIA Media Group
18 संस्करण

अंतरराष्ट्रीय संस्करण (ऑनलाइन)
(संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त भाषाएं)
- ब्लिट्ज इंडिया, अरेबिक
- ब्लिट्ज इंडिया बिजनेस, अरेबिक
- ब्लिट्ज इंडिया, चाइनीज
- ब्लिट्ज इंडिया बिजनेस, चाइनीज
- ब्लिट्ज इंडिया, फ्रेंच
- ब्लिट्ज इंडिया बिजनेस, फ्रेंच
- ब्लिट्ज इंडिया, रशियन
- ब्लिट्ज इंडिया बिजनेस, रशियन
- ब्लिट्ज इंडिया, स्पेनिश
- ब्लिट्ज इंडिया बिजनेस, स्पेनिश

(अंग्रेजी भाषा संस्करण)
- ब्लिट्ज इंडिया यूएस (न्यूयॉर्क)
- ब्लिट्ज इंडिया, यूरोप (लंदन)
- ब्लिट्ज इंडिया, वेस्ट एशिया (दुबई)
- ब्लिट्ज इंडिया, अफ्रीका (तंजानिया)

वर्ष : 4, अंक : 41 नई दिल्ली, 29 जून - 12 जुलाई, 2026 https://hindi.blitzindiamedia.com/ ₹20/-

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर का पतन...

सिर्फ दो साल में ही कैसे गंवा दी इंग्लैंड की सत्ता ?

लंदन से दीपक द्विवेदी

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का इस्तीफा ब्रिटिश राजनीति की बड़ी घटना है। अभी दो साल भी पूरे नहीं हुए हैं जब उन्होंने लेबर पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं।

जिस पार्टी ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया, उसी पार्टी को अब उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। लेबर सांसदों को लगने लगा था कि स्टार्मर अगला चुनाव जिताने के लिए सही चेहरा नहीं हैं। स्टार्मर के इस्तीफे के पीछे कोई बड़ा घोटाला नहीं था। संसद में कोई बड़ी हार भी नहीं हुई थी। असली वजह थी पार्टी के भीतर उनका कमजोर होता नेतृत्व।

लेबर पार्टी की लोकप्रियता लगातार गिर रही थी। दूसरी तरफ रिफॉर्म यूके तेजी से मजबूत हो रही थी। इससे लेबर सांसदों में बेचैनी बढ़ गई। उन्हें डर था कि अगर स्टार्मर प्रधानमंत्री बने रहे तो पार्टी अगला चुनाव हार सकती है।

इसी बीच एंडी बर्नहम की वेस्टमिंस्टर में वापसी ने हालात बदल दिए। मेकरफील्ड उपचुनाव में उनकी जीत के बाद लेबर सांसदों को स्टार्मर का एक मजबूत विकल्प मिल गया। इसके बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर दबाव और बढ़ गया।

स्टार्मर सत्ता में स्थिरता और बदलाव का वादा लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि वे देश को नई दिशा देंगे। कंजर्वेटिव सरकारों के लंबे उतार-चढ़ाव के बाद लोगों को उनसे उम्मीद थी।

शुरुआत में उनका शांत और गंभीर अंदाज लोगों को अच्छा लगा। वे एक अनुशासित और जिम्मेदार नेता के रूप में दिखे लेकिन सरकार चलाने के दौरान यही अंदाज उनकी कमजोरी बन गया।

लोगों को लगा कि स्टार्मर बहुत सावधान हैं। वे जनता से दूर दिखने लगे। उनका नेतृत्व प्रेरणादायक नहीं लग रहा था। जिन लोगों ने बदलाव की उम्मीद में वोट दिया था, उन्हें अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फर्क दिखाई नहीं दिया।

अर्थव्यवस्था ने भी स्टार्मर की मुश्किलें बढ़ाईं। ब्रिटेन किसी बड़े आर्थिक संकट में नहीं था लेकिन आम लोगों की आर्थिक हालत पर दबाव बना हुआ था। - शेष पेज 31 पर

स्टार्मर के जाने से भारत-ब्रिटेन संबंधों पर असर

- कीर स्टार्मर के इस्तीफे से भारत-ब्रिटेन संबंधों पर बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है किंतु लंदन में फैसले लेने की रफ्तार कुछ समय के लिए धीमी हो सकती है।
- दोनों देशों के रिश्तों का सबसे बड़ा आधार भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यह समझौता पहले से मजबूत स्थिति में माना जा रहा है।

- शेष पेज 31 पर

प्रधानमंत्री मोदी के मन में है...

नए भारत का रोडमैप

विनोद शील

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में खुल कर यह बताया कि उनकी सरकार कैसे काम करती है और उनकी सरकार को कार्य करने की प्रेरणा एवं ऊर्जा कहां से मिलती है एवं उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी बताया कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के महासंकल्प को पूर्ण करने में कैसे लोगों से बच कर रहना है।

- ‘राष्ट्र सर्वोपरि’ की भावना हमारी मार्गदर्शक
- दुनिया भी माने, भारत के लिए ‘राष्ट्र प्रथम’

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि 'राष्ट्र सर्वोपरि' की भावना ही पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों और एक भरोसेमंद वैश्विक शक्ति के रूप में इसके उभरने का मुख्य आधार रही है। हाल ही में जी7 समिट में अपनी भागीदारी को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के नेता ‘राष्ट्र प्रथम’ के सिद्धांत के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को मानते हैं। उन्होंने कहा कि यही मार्गदर्शक सोच देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के साथ, देश की नीतियों, प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को आकार देती रहती है।

अपने एक अहम पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, “सेवा के बीते 12 वर्षों की हमारी एक और बड़ी सिद्धि रही है- निराशा से निकलकर आशा और आकांक्षा से भरे भारत का निर्माण! उन्होंने कहा कि आज लिए जा रहे फैसले और उठाए जा रहे कदम आने वाली सदियों के लिए देश के भविष्य की नींव रख रहे हैं। पीएम ने कहा, “देश न केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है बल्कि एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साझेदार के तौर पर भी सामने आया है।” उन्होंने एक और पोस्ट में कहा, “मिडिल क्लास हमेशा हमारी बड़ी प्राथमिकता रहा है। इसकी 'ईज ऑफ लिविंग'' के लिए सरकार ने हर स्तर पर काम किया है। भारत के विकास के इस अहम कालखंड में कुतर्क करने वालों से इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है।

- शेष पेज 31 पर

भ्रष्टतंत्र पर प्रहार जरूरी

प्रधान संपादक की कलम से

दीपक द्विवेदी

2

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बेहद करीब

16-17

'गाड़ियों से ज्यादा फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का हक'

12

भ्रष्टतंत्र पर प्रहार जरूरी

दीपक द्विवेदी
एडीटर-इन-चीफ

प्रधान संपादक की कलम से

आज भारत के लगभग हर शहर में अनियोजित विकास दिखाई देता है। चाहे योजनाबद्ध कालोनियां हों, शहर-गांव हों या तेजी से बढ़ते बाहरी इलाके। ये सभी शहरों को सस्ता आवास, सेवाएं और रोजगार उपलब्ध कराते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब विकास के साथ सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नहीं होता। होता भी है तो अनदेखी अथवा भ्रष्ट कर्मियों की साठगांठ से नियमों में अनदेखी की जाती है जो बाद में हादसों के रूप में सामने आती है। देश में सड़कों, होटलों, सिनेमा घरों, विभिन्न संस्थानों के भवनों या अन्य स्थानों पर लंबे समय से ऐसे हादसे हो रहे हैं और निर्दोष लोग उनमें अपनी जान गंवा रहे हैं जिनको रोका जा सकता था किंतु ऐसा हम कर नहीं पा रहे। कहना गलत नहीं होगा कि ये हादसे अक्षम और भ्रष्ट सरकारी तंत्र का नतीजा होते हैं। हादसों के बाद सरकारें मुआवजा देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती हैं और जांच कमेटियों की रिपोर्टें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं।

कुछ दिन पूर्व दिल्ली के एक होटल में लगी आग ऐसा ही हादसा था जिसने 22 इंसानी जिंदगी लील लीं थीं और अब लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड में भी 15 नौजवानों की जान चली गई। दिल्ली के होटल के लिए केवल छह कमरों की मंजूरी ली गई थी और 25 कमरों के साथ संचालित किया जा रहा था। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में भी अनियमितताओं की लंबी फेहरिस्त पाई गई है। दिल्ली, लखनऊ और देश के दूसरे हिस्सों में हुए ऐसे हादसों की सूची बहुत लंबी है। सभी घटनाओं में एक साझा विलेन सामने आता है, वह है नियमों का अनुपालन न होना। ऐसे में इस बात की पड़ताल प्रासंगिक हो जाती है कि एक लोक कल्याणकारी लोकतंत्र वाले देश भारत में इंसानों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है?

◆

मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इस विषय में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं हो सकती।

◆

इन हादसों के पीछे क्या कारण हैं; इसके बारे में संबंधित विभागों को पहले से ही जानकारी होती है। ऐसे में जिम्मेदार लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए; भले ही वे सेवानिवृत्त ही क्यों न हो चुके हों। केवल ऐसी सख्त कार्रवाई से ही हादसे रोके जा सकते हैं।

दरअसल ऐसा लगने लगा है कि देश में हादसों में मौत सिर्फ एक आंकड़ा मात्र बन गई है जबकि पश्चिम के देशों में अपने एक- एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए सारी एजेंसियां जमीन-आसमान एक कर देती हैं। वहां मानव जीवन इतना अनमोल है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में मानवजनित हादसों की बाढ़ है। भारत में हर एक बड़े हादसे के बाद एक तयशुदा पटकथा चलती है। जांच के आदेश दिए जाते हैं। मुआवजे की घोषणा और कुछ अधिकारियों का हादसे वाली जगह से तबादला, बस। स्थिति जस की तस बनी रहती है।

हाल ही में हुई आग की घटनाएं बेहद दुखद हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल आग लगने की घटना थी? शायद नहीं। आग तो अक्सर आखिरी घटना होती है, जो हमें नजर आती है लेकिन असली त्रासदी तो बहुत पहले ही शुरू हो जाती है, जब नियमों की अनदेखी होती है, बुनियादी सुविधाओं की कमी को नजरअंदाज किया जाता है और अवैध निर्माण धीरे-धीरे सामान्य बन जाता है। यह सब तभी रुक सकेगा जब देश के किसी भी इलाके में हो रहे मानवजनित हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को त्वरित कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐसा होने पर ही लालच में लिप्त और नियम-कानूनों का पालन न कराने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों में भय व्याप्त होगा। ऐसे हादसों के लिए हर विभाग के मौजूदा अथवा सेवानिवृत्त उत्तरदायी कर्मियों को कटघरे में लाना होगा। तभी लोगों की जान को जोखिम में डालने वालों पर लगाम कस सकेगी।

गौर करें तो भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी एक बेहद जटिल और गहरी समस्या है। वर्ष 1995 के डबवाली अग्निकांड ने पूरे विश्व को झकझोर दिया था। उस त्रासदी के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी अनेक नियम, कानून और दिशा-निर्देश बनाए गए। केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा सभी सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा नियमों की नियमित जांच कर उनके प्रभावी पालन को सुनिश्चित किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे हादसों से देश की साख प्रभावित होती है। एक लोकतंत्र के तौर पर अगर हम परिपक्व हो रहे हैं तो यह बात देश को चलाने वाली संस्थाओं में भी दिखनी चाहिए। देश को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इस विषय में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं हो सकती।

हमेशा याद रखें, प्रशासन से जुड़ी हर फाइल के पीछे मानवीय पहलू हो आधार

शासन सहानुभूतिपूर्ण, उत्तरदायी और समावेशी बना रहे

प्रधानमंत्री मोदी ने सहायक सचिव के रूप में नियुक्त 2024 बैच के आईएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं से विचार किए साझा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विगत दिवस नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2024 बैच के उन 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने इन प्रशिक्षु अधिकारियों को सेवा का सही अर्थ समझाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा प्रशिक्षु अधिकारियों ने इस अवसर पर अपने क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण और मंत्रालयों से जोड़े जाने के बाद कामकाज के अनुभव साझा किए।

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विभागों में दो वर्षों के कामकाज के अनुभव और प्रशासनिक प्रशिक्षण के बाद वे अब एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं जहां उनके निर्णय न केवल उनके अपने करियर बल्कि करोड़ों नागरिकों के भविष्य को भी आकार देंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि लोक सेवा की असली परीक्षा वास्तविक परिस्थितियों से ईमानदारी, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ निपटने से प्रारंभ होती है।

प्रधानमंत्री ने युवा प्रशासनिक अधिकारियों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक-केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आग्रह किया।

उन्होंने अधिकारियों से हमेशा यह याद रखने का आग्रह किया कि प्रशासन से संबंधित प्रत्येक फाइल के पीछे मानवीय पहलू छिपे होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक फाइल अनगिनत नागरिकों की आकांक्षाओं, चिंताओं और उनके जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। पीएम ने 'नागरिक देवो भव' के मंत्र पर बल देते हुए अधिकारियों से हर निर्णय के केंद्र में नागरिकों को रखने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि शासन सहानुभूतिपूर्ण, उत्तरदायी और समावेशी बना रहे। प्रधानमंत्री ने सभी विभागों के समग्र रूप से मिलकर काम करने के दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान करते हुए इस बात पर बल दिया कि विकास से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का समाधान अलग-थलग रहकर नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि सार्थक और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए विभागों के बीच प्रभावशाली समन्वय आवश्यक है।

> **पीएम ने 'नागरिक देवो भव' के मंत्र पर बल देते हुए अधिकारियों से हर निर्णय के केंद्र में नागरिकों को रखने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि शासन सहानुभूतिपूर्ण, उत्तरदायी और समावेशी बना रहे।**

प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत का निर्माण करना आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आज भारत की प्राथमिकताओं में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और युवाओं के लिए अवसरों का सृजन शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने पिछले दशक में शासन व्यवस्था में आए परिवर्तनों पर बल देते हुए कहा कि प्रशासन प्रक्रिया-केंद्रित मॉडल से परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हुआ है। उन्होंने सेवा वितरण में सुधार लाने और नागरिकों को सुगमता और पारदर्शिता के साथ सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में डिजिटल शासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने आंकड़ों पर आधारित शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि आंकड़ों को केवल संख्या के रूप में नहीं बल्कि लाखों लोगों के सामूहिक जीवन, चुनौतियों और आकांक्षाओं के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि नीतियां जमीनी स्तर पर प्रभावी परिणाम दे रही हैं या नहीं।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का भी उल्लेख किया और बताया कि वर्तमान बैच में 40 प्रतिशत से अधिक महिला अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने और पदों से नहीं बल्कि कामकाज से मिले ठोस परिणामों से संतुष्टि प्राप्त करने का आग्रह किया।

उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि उनकी ऊर्जा, प्रतिभा और समर्पण भारत के विकास पथ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास, मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव सुश्री रचना शाह, एलबीएसएनएए के निदेशक श्रीराम तरणिकांति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस संवाद के दौरान उपस्थित रहे।

> **विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अंतर्गत विकसित भारत का निर्माण करना आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य होना चाहिए।**

> **राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का भी उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्तमान बैच में 40 प्रतिशत से अधिक महिला अधिकारी हैं।**

> **आज भारत की प्राथमिकताओं में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा व युवाओं के लिए अवसरों का सृजन शामिल हैं।**

दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी जरूरी है योग

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम ने कोलकाता में हजारों लोगों के साथ किया योग

ब्लिट्ज विशेष

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता के रेड रोड पर 12वें अंततराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम को लीड किया। साथ ही वह वेलनेस और हेल्दी लिविंग पर केंद्रित इस ग्लोबल इवेंट को मनाने में हिस्सा लेने वालों के साथ शामिल हुए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का 12वां एडिशन पूरे देश और दुनिया भर में 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' थीम के तहत मनाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि योग जीवन की सभी अवस्थाओं में हेल्दी और एक्टिव लाइफ को बढ़ावा देने में मदद करता है। इस साल की थीम, 'योग फॉर हेल्दी एजिंग', पूरी जिंदगी हेल्दी और एक्टिव लाइफ पर बढ़ते ग्लोबल जोर को दिखाती है। जैसे-जैसे दुनिया भर में आबादी की उम्र बढ़ रही है और नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियां और लाइफस्टाइल से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, जोर सिर्फ जिंदगी में साल बढ़ाने से हटकर हेल्थ पीरियड, क्वालिटी ऑफ लाइफ और ओवरऑल वेल-बीइंग को बेहतर बनाने पर जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'जब हम हेल्दी एजिंग के लिए योग की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम यह पक्का करने के लिए काम कर सकते हैं कि उम्र इंसान की काबिलियत को कम न करे। योग इंसान की ज़िंदगी को लगातार आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। हमारा टारगेट 40 की उम्र में 20 की उम्र से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना होना चाहिए। हमारा टारगेट 50 की उम्र में 30 की उम्र से ज़्यादा एनर्जेटिक रहने का होना चाहिए। योग हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को हाई रखता है। यह हमें शांत, स्ट्रेस-फ्री ज़िंदगी जीने में भी मदद करता है। रेगुलर प्रैक्टिस से योग हमें अपने शरीर और मन को जिंदगी भर सीखने वाला बनाना सिखाता है। हम अपने बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे, उतना ही बेहतर हम खुद को मैनेज कर पाएंगे। इसीलिए हेल्दी एजिंग के लिए योग, इस थीम को सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए देखा जाना चाहिए।'

पीएम बोले,योग दिवस के मौके पर बंगाल में होना बहुत खास है। बंगाल की पवित्र धरती, जहां रामकृष्ण परमहंस जैसे संत अवतरित हुए, स्वामी विवेकानंद ने यहीं से पूरी दुनिया को योग से परिचित कराया, जहां लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने योग परंपरा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव दे रहा है।'

पूरा देश, दुनिया जुड़े हुए लग रहे हैं

पीएम मोदी ने कहा, 'पूरा देश, दुनिया, जुड़े हुए लग रहे हैं। यही योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, सबको साथ लाता है। इस मौके पर, मैं पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को, इंटरनेशनल योग डे की दिल से बधाई देता हूं। आज, योग डे पर, मैं खास तौर पर बंगाल के लोगों की सफाई अभियान के लिए तारीफ करना चाहूंगा। यह एक शानदार पहल है।

देश योग की ऊर्जा से भरा हुआ लगता है

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्व में पूर्वोत्तर और बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से भरा हुआ लगता है।'

टाइम्स स्क्वायर पर लोगों ने योग किया

न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोगों ने योग किया। इनमें भारत के महावाणिज्यदूत बिनय एस. प्रधान के अलावा अन्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल एक प्रतिभागी ने कहा, यह टाइम्स स्क्वायर पर मेरा दूसरी बार योग करने का अनुभव है, यह जादुई है, लेकिन मुख्य रूप से यह अलग-अलग बैकग्राउंड, जाति के सभी लोगों को इकट्ठा करने, न्यूयॉर्क और दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए एक साथ आने के बारे में है।

कटक में पानी के अंदर किया योग

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर ओडिशा के कटक में महानदी में अंडरवाटर योग किया गया।

अहमदाबाद में अमित शाह ने योग किया

गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योग किया।

नायडू ने बाबा रामदेव के साथ किए योगासन

विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ कई आसन किए। सीएम ने मुश्किल योग आसन भी आसानी से किए। वहीं बाबा रामदेव ने एक साथ योग के कई आसन किए। बाबा रामदेव ने मंच पर मंत्री नारा लोकेश के साथ भी योग आसन किए। उन्होंने अनुलोम और विलोम तरीकों से प्राणायाम किए। इसी तरह, वेंकटेश्वर सुप्रभातम और गोविंद नाम स्मरण के साथ किए गए योगाभ्यासों ने सभी को प्रभावित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू के अलावा मंत्री अच्चेना, दुर्गेश, सत्यकुमार और हजारों उत्साही लोग शामिल हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आध्यात्मिकता और योग से ही एक स्वस्थ, अमीर और खुशहाल आंध्र प्रदेश बन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर 190 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है

मॉस्को में योग अभ्यास का आयोजन

रूस के मॉस्को के एमएसयू यूनिवर्सिटेस्काया स्क्वायर में योगा सेशन का आयोजन किया गया। इंडियन एम्बेसी में जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर द्वारा ऑर्गनाइज किए गए और मॉस्को सिटी गवर्नमेंट के सपोर्ट वाले योगा डे सेलिब्रेशन में सैकड़ों लोग शामिल हुए।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में योग किया

देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में योग किया।

बंगाल में हाथियों की पीठ पर बैठकर महावतों का योग

पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जलदापारा नेशनल पार्क में कुनकी हाथियों की पीठ पर बैठकर महावतों ने योग किया। सुबह, फॉरेस्टर और अधिकारियों ने हालोंग नदी के किनारे छह कुनकी हाथियों के साथ योग सेशन में हिस्सा लिया। जलदापारा नेशनल पार्क के अधिकारी लोगों और हाथियों की यह फोटो लाए हैं जिसमें वे एक साथ योगा डे मना रहे हैं।

रियाद में योगाभ्यास के लिए जुटे लोग

रियाद में 12वें इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए। इस साल का सेलिब्रेशन हेल्दी एजिंग और लंबे समय तक सेहतमंद रहने में योग की भूमिका पर फोकस था। यह इवेंट रियाद में भारतीय दूतावास ने सऊदी योग कमेटी के साथ पार्टनरशिप में प्रिंस फैसल बिन फहद ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में ऑर्गनाइज किया गया।

असम में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने योग किया

आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने असम के तेजपुर में सभी सेवारत जवानों, रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों के साथ योग किया। इस अवसपर पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिकों की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सेहत को बेहतर बनाने में योग की अहम भूमिका पर जोर दिया। तेजपुर मिलिट्री स्टेशन के मेघना स्टेडियम में सेलिब्रेशन में हिस्सा लेते हुए, उन्होंने योग को ज़िंदगी जीने का एक ऐसा तरीका बताया जो शारीरिक कसरत से कहीं ज़्यादा है. इवेंट के बाद मीडिया से बात करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा के मेल को दिखाता है और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों, दूर-दराज के इलाकों और मुश्किल ऑपरेशनल माहौल में तैनात सैनिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बहुत खराब मौसम, ऊबड़-खाबड़ इलाका और अपने परिवारों से लंबे समय तक अलग रहना शामिल है। ऐसे हालात में योग उन्हें शारीरिक फिटनेस, मानसिक ताकत, इमोशनल स्थिरता और ऑपरेशनल तैयारी बनाए रखने में मदद करता है। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची सेहत तब मिलती है जब शारीरिक सेहत के साथ मन की शांति और आध्यात्मिक जागरूकता भी हो। उनके अनुसार, योग लोगों में लचीलापन, नई एनर्जी और पॉजिटिव सोच डेवलप करने में मदद करता है, जो सभी उन सैनिकों के लिए ज़रूरी हैं जिन्हें मुश्किल ज़िम्मेदारियां दी जाती हैं। भारतीय सेना की ताकतों पर जोर देते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि सैनिक इसकी सबसे कीमती संपत्ति है।

जयशंकर का योग

दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हजारों लोगों के साथ योग आसन किए।

भुवनेश्वर में मोहन चरण माझी ने योग किया

ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 12वें इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर योग किया।

भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में योग किया

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में योग किया।

राजनाथ सिंह, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने योग किया

मेघालय के शिलांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 12वें इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर योग किया।

मुंबई में फडणवीस का योग

मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस योगाभ्यास में शामिल हुए किया। बड़े जोश के साथ हुए इस इवेंट के दौरान उन्होंने योग की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि इंटरनेशनल योगा डे मनाना भारत के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इंटरनेशनल योगा डे पर सभी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि योग एक पुरानी भारतीय जीवनशैली और इलाज का एक पारंपरिक सिस्टम है। फडणवीस ने कहा कि दुनिया भर में योग के विज्ञान को लेकर बहुत उत्सुकता है, और समाज इसे बड़े पैमाने पर अपना रहा है। योग करने वाले मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत होते हैं। योग की एक खास बात यह है कि इसका सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा पर भी अच्छा असर पड़ता है। फडणवीस ने कहा कि इंसान का मन ब्रह्मांड से जुड़ा है, और योग के जरिए, हम ब्रह्मांड के साथ उस रिश्ते को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। इसका हमारे अंदर की सोच और हमारे शरीर की अंदरूनी ठीक करने की काबिलियत पर गहरा असर पड़ता है।

असम में निर्मला व बिस्वा सरमा हुए शामिल

असम के गुवाहाटी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ योगाभ्यास किया।

लोकसभा स्पीकर ने योग किया

दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया।

एक्टर अक्षय कुमार ने योग किया

दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और एक्टर अक्षय कुमार ने दिल्ली में 12वें सालाना इंटरनेशनल योग दिवस में हिस्सा लिया। इस साल के योग दिवस की थीम है 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग'।

भारत-पाकिस्तान सरहद का नया 'सुरक्षा ब्लूप्रिंट' तैयार

बाड़मेर-जैसलमेर सहित 4 जिले 'स्पेशल वॉच जोन' घोषित

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। राजस्थान से सटी भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देश की सुरक्षा को अभेद्य किला बनाने के लिए एक बहुत बड़ा रक्षात्मक और प्रशासनिक कदम उठाया गया है। सीमा पार से होने वाली नापाक हरकतों, नशीले पदार्थों की तस्करी और आधुनिक ड्रोन तकनीक के जरिए होने वाली घुसपैठ को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर धरातल पर लागू कर दिया गया है। इस नए मास्टर प्लान के तहत राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर को पूरी तरह से 'स्पेशल वॉच जोन' के रूप में चिन्हित किया गया है। अब सीमा सुरक्षा बल , जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस और केंद्रीय व राज्य की खुफिया सुरक्षा एजेंसियां एक संयुक्त कमांड के रूप में काम करेंगी। इस साझा प्रयास का मुख्य उद्देश्य बॉर्डर से सटे 50 किलोमीटर के पूरे दायरे में होने वाली हर गतिविधि को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है।

राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर स्थित पाकिस्तान की सीमा हमेशा से सामरिक रूप से अत्यंत संवेदनशील रही है। इसी संवेदनशीलता को देखते हुए अब गृह मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा को लेकर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। नए ब्लूप्रिंट के अनुसार, अब सीमा सुरक्षा केवल बॉर्डर की चौकियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बॉर्डर के अंदरूनी 50 किलोमीटर के दायरे में एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है।

इस संयुक्त अभियान के तहत सभी संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, खुफिया विभाग के अधिकारी और बीएसएफ के आला अधिकारी नियमित रूप से बैठकें करेंगे और रणनीतिक इनपुट साझा करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अब सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक और सैन्य तालमेल पहले से कहीं अधिक मजबूत और त्वरित होने वाला है।

'स्पेशल वॉच जोन'- 15 किमी के भीतर तुरंत एक्शन

इस नए सुरक्षा ब्लूप्रिंट का सबसे पहला और सीधा असर बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक रहने वाले गांवों और ढाणियों पर दिखने लगा है।

राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिलों को 'स्पेशल वॉच जोन' में शामिल कर 15 किलोमीटर की सीमा के भीतर मौजूद सभी अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को तुरंत प्रभाव से हटाने की सख्त हिदायत दी गई है।

बाड़मेर जिले की ही बात करें तो यहां सीमा के सबसे नजदीक करीब 100 गांव स्थित हैं। इन गांवों में गुरुवार को प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक बड़ा संयुक्त अभियान चलाकर भौतिक सर्वे किया गया और संदिग्ध व बिना अनुमति के बने ढांचों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रशासन का साफ कहना है कि देश की सुरक्षा से जुड़े इस दायरे में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आईएसआई के पुराने तस्करी नेटवर्क पर वार

सुरक्षा एजेंसियों के पास लंबे समय से यह इनपुट रहे हैं कि भारत-पाक बॉर्डर से महज 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारतीय गांवों के समानांतर ही पाकिस्तान की सीमा के भीतर भी 5 और 10 किलोमीटर के दायरे में कई छोटे-छोटे गांव और ढाणियां मौजूद हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई लंबे समय से इन सीमांत गांव-ढाणियों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों और नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए करती रही है।

नए कॉरिडोर से 40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के तहत तीन मुख्य प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पर काम जोरों पर जारी है। नए कॉरिडोर से 40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर।

ये हैं कोरिडोर

1 जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम मार्ग तक मैजेंटा लाइन एक्सटेंशन लगभग 29 किलोमीटर लंबा होगा। यह बाहरी और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के प्रमुख इलाकों जैसे पीरागढ़ी, मंगोलपुरी, वेस्ट एनक्लेव, मधुबन चौक, प्रशांत विहार और हैदरपुर बादली मोड़ को जोड़ते हुए मजलिस पार्क, आजादपुर होते हुए सीधे सेंट्रल दिल्ली के आरके आश्रम मार्ग तक पहुंचाएगा।

2 तुगलकाबाद से एयरोसिटी तक नई गोल्डन लाइन करीब 23 किलोमीटर लंबी होगी। यह बिल्कुल नया कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयरोसिटी क्षेत्र से सीधे जोड़ेगा। इसके प्रमुख स्टेशनों में तुगलकाबाद, साकेत जी ब्लॉक, खानपुर, छतरपुर और महरौली शामिल हैं।

3 मजलिस पार्क से मौजपुर तक पिंक लाइन एक्सटेंशन लगभग 7 किलोमीटर का छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पिंक लाइन के रिंग रोड लूप को पूरा करता है। इसके बाद उत्तर और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के इलाके जैसे बुराड़ी, झरोदा और वजीराबाद सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाते हैं।

केएमपी एक्सप्रेसवे पर दौड़ेगा विकास

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे को प्रदेश के भविष्य के विकास की धुरी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केएमपी एक्सप्रेसवे पर पांच नये शहर और तीन आइएमटी से पूरे राज्य की तस्वीर बदलने वाली है।

प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि करीब 135 किलोमीटर लंबा केएमपी एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा और आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की नई पहचान बनकर उभरेगा।

वर्ष 2041 की संभावित जनसंख्या और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार केएमपी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पांच नये आधुनिक शहर बसाने की योजना पर कार्य कर रही है।

इसके लिए पंचग्राम विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रमुखता से उठा चुके हैं।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2030 तक प्रदेश में 10 नई औद्योगिक माडल टाउनशिप (आईएमटी) स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इनमें से पांच आईएमटी को मंजूरी मिल चुकी है और उनके विकास की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

विकसित भारत के आकर्षण के केंद्र बनेंगे

प्रस्तावित 10 आईएमटी में से तीन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ विकसित किया जाएगा, जिससे यह क्षेत्र औद्योगिक निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन सकेगा।

उद्योग मंत्री ने कहा कि केएमपी के दोनों ओर विकसित होने वाले पांच नये शहर न केवल विकसित भारत के आकर्षण केंद्र बनेंगे और दिल्ली और एनसीआर पर बढ़ रहे जनसंख्या तथा यातायात दबाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे क्षेत्रीय विकास को संतुलन मिलेगा और लोगों को रोजगार, आवास तथा आधुनिक सुविधाएं अपने निकट उपलब्ध हो सकेंगी।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरित क्रांति का अग्रदूत रहा हरियाणा आज औद्योगिक और तकनीकी विकास के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गुरुग्राम ने आइटी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हुए देश और दुनिया में अलग स्थान हासिल किया है।

आने वाले समय में जब प्रदेश में 10 नई आईएमटी विकसित होंगी तो हरियाणा देश की औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वाले राज्यों में सबसे आगे खड़ा दिखाई देगा।

राजस्थान में प्रमोशन में दो साल की छूट

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तों में दो वर्ष की छूट देने को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के बयान के अनुसार, यह निर्णय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव या सेवा अवधि में दो साल की छूट प्रदान करने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा।

दिल्ली की बेटियों ने किया कमाल : 8 साल की उम्र, 18 विश्व रिकॉर्ड

रील और गेमिंग छोड़ योग में जीते अंतरराष्ट्रीय मेडल

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। चमक-दमक वाले डिजिटल युग में जब बच्चे स्मार्टफोन की चंद इंच की आभासी दुनिया में खोए रहते हैं, वहीं दिल्ली की कुछ नौनिहाल बेटियां अपनी कड़ी मेहनत और साधना के दम पर सफलता की नई कहानी लिख रही हैं। इंटरनेट मीडिया पर रील और ऑनलाइन गेमिंग के शोर के बीच दिल्ली की इन नन्ही योग साधिकाओं ने न केवल अपनी उम्र को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि योग की प्राचीन विधा को जन-जन तक पहुंचाकर स्वस्थ जीवन का एक सशक्त और जीवंत संदेश भी दे रही हैं।

दिल्ली की महज आठ वर्ष की नौनिहाल वान्या शर्मा, मिशा सैनी और निहारिका पासी ने योग जगत में अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत व कांस्य मेडल जीतकर प्रेरणादायक योग आइकनों में शुमार हो चुकी हैं। तीनों कक्षा तीन की छात्रा हैं। निहारिका स्वरूप नगर की, वान्या सेक्टर 22 रोहिणी और मीशा सैनी पीतमपुरा की रहने वाली हैं।

वान्या शर्मा ने महज आठ साल की उम्र में 18 विश्व रिकार्ड अपने नाम दर्ज कराए हैं। इंटरनेशनल योगा चैंपियन वान्या ने सितंबर 2025 में एशिया पैसिफिक

मलेशिया में तीन स्वर्ण पदक जीते तो वहीं दिसंबर 2025 में गाजियाबाद में हुए योग विश्व कप में 14 देशों के खिलाड़ियों को धूल चटाते हुए दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीते हैं। इसके अलावा वान्या ने प्रतियोगिता में चैंपियन आफ चैंपियंस का प्रतिष्ठित खिताब भी अपने नाम किया है।

इसी तरह उनकी साथी मिशा सैनी ने एशिया कप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए एक स्वर्ण और एक रजत मेडल देश की झोली में डाला, जबकि निहारिका पासी ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रजत और एक कांस्य अपने नाम किया है। इन बच्चों में योग को लेकर अद्भुत ललक है।

वान्या, निहारिका और मिशा सुबह की पहली किरण के साथ ही अष्टांग योग के सबसे कठिन और जटिल आसनों को बेहद सहजता से करती हैं। इन बाल योगियों का आधुनिक समाज के लिए एक मूक संदेश भी है जो सेहत को छोड़कर स्क्रीन की तरफ भाग रहा है। उन्हें ये बेटियां अध्यात्म, बेहतर स्वास्थ्य और अनुशासित जीवनशैली की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अब तीनों बेटियां थाइलैंड में इस वर्ष सितंबर में होने वाले एशिया कप की तैयारी में जुटी हैं।

सरकारी राहत ने दी मुंबई में रीडेवलपमेंट को रफ्तार

तीन महीने में 70 हाउसिंग सोसायटियों ने बिल्डरों से किया डेवलपमेंट एग्रीमेंट

ब्लिट्ज ब्यूरो

मुंबई। मुंबई में पुरानी और जर्जर बिल्डिंगों के रीडेवलपमेंट ने चालू वित्त वर्ष के आरंभ से ही रफ्तार पकड़ ली है। अप्रैल से अब तक 70 हाउसिंग सोसायटियों ने बिल्डरों के साथ डेवलपर एग्रीमेंट (डीए) कर लिया है। यह संख्या पूरे 2025 में हुए कुल समझौतों की तुलना में 30 प्रतिशत से अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा नियमों को आसान बनाए जाने से रीडेवलपमेंट परियोजनाओं को गति मिली है।

1094 सोसायटी में प्रक्रिया जारी

नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में वर्तमान में 1,094 सोसायटियों में रीडिवेलपमेंट की प्रक्रिया जारी है। इन परियोजनाओं के तहत 432 एकड़ क्षेत्र में नए आवास विकसित किए जा रहे है। अनुमान है कि 2031 तक रीडिवेलपमेंट के जरिए करीब 59 हजार नए घर तैयार होंगे। इन परियोजनाओं से सरकार को 9,115 करोड़ रुपये से अधिक की स्टैंप ड्यूटी मिलने की संभावना है। मुंबई में जमीन की कमी और बढ़ती आबादी के बीच रीडेवलपमेंट शहर के लिए नए घरों का सबसे बड़ा स्रोत बनता जा रहा है।

इमारतों को ऑडिट की जरूरत

मुंबई में करीब 1.6 लाख बिल्डिंग 30 साल से अधिक पुरानी हैं, जिनको स्ट्रक्चर ऑडिट कराने के लिए कहा गया है। सबसे अधिक 46 फीसदी बिल्डिंग पश्चिमी उपनगरों में है।

नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन निदेशक शिशिर बैजल के अनुसार, रीडेवलपमेंट से न केवल नए घरों की आपूर्ति बढ़ेगी, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास और आवासीय गुणवत्ता के विकास गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

सेराटेक ग्रुप के प्रबंध निदेशक आनंद अग्रवाल के अनुसार, नियमों को सरल बनाने और सोसायटी सदस्यों के लिए नए घर पर स्टैप ड्यूटी शुल्क मात्र 1,000 रुपये तय किए जाने से रीडेवलपमेंट परियोजनाओं को नई गति मिली है।

देश में पहली बार कपड़ा व्यापारियों के लिए भी थाना

सूरत। देश की टेक्सटाइल राजधानी कहे जाने वाले सूरत को जल्द ही एक नई पहचान मिलने वाली है। करोड़ों रुपये के कपड़ा कारोबार को सुरक्षा और बेहतर कानूनी संरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने शहर में देश के पहले विशेष टेक्सटाइल पुलिस स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह पुलिस स्टेशन कपड़ा उद्योग से जुड़े अपराधों, धोखाधड़ी और व्यापारिक विवादों के मामलों की जांच और कार्रवाई के लिए होगा।

जानकारी के अनुसार सलाबतपुरा, महिधरपुरा, वराछा, पूणा, सारोली, गोडादरा और उधना थाना क्षेत्रों में टेक्सटाइल व्यापार से जुड़ी सभी शिकायतें अब इसी विशेष पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाएंगी। सरकार की योजना अगले एक से दो वर्षों के भीतर इस परियोजना को पूरा करने की है।

व्यापारी लंबे समय से कर रहे थे मांग

फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन (फोस्टा) के अध्यक्ष कैलाश हाकिम और सचिव दिनेश कटारिया ने बताया कि संगठन पिछले तीन वर्षों से इस मांग को सरकार के सामने उठा रहा था। उनका कहना है कि देश के पहले टेक्सटाइल पुलिस स्टेशन की स्थापना से कपड़ा व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी और धोखाधड़ी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी।

अभी क्या है व्यवस्था?

मौजूदा समय में कपड़ा व्यापार से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की शिकायतें अलग-अलग थानों में दर्ज होती हैं, जिससे एक ही आरोपी के खिलाफ दर्ज कई मामलों का रिकॉर्ड जुटाने में कठिनाई आती है। नए टेक्सटाइल पुलिस स्टेशन में सभी शिकायतों का केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे किसी भी आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी और कार्रवाई आसान व जल्द होगी।

बटन दबाइए, पैदल यात्रियों के लिए रुक जाएंगी गाड़ियां...

ब्लिट्ज ब्यूरो

अहमदाबाद। अगर आपने कभी यूरोप, अमेरिका या सिंगापुर की सड़कों के वीडियो देखे हैं तो एक चीज जरूर नोट की होगी। वहां सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को ट्रैफिक के भरोसे नहीं छोड़ दिया जाता। एक बटन दबाते ही गाड़ियां रुक जाती हैं और लोगों को आराम से सड़क पार करने का मौका मिल जाता है। अब कुछ ऐसा ही प्रयोग भारत में भी शुरू हुआ है।

अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने शहर के व्यस्त सीजी रोड पर पहली बार पेलिकन (पुश बटन) ट्रैफिक सिग्नल लगाया है। यह सिस्टम खास तौर पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। फिलहाल इसे ट्रायल बेसिस पर शुरू किया गया है और इसकी सफलता के बाद शहर के अन्य इलाकों में भी ऐसे सिग्नल लगाए जा सकते हैं। इस परियोजना पर करीब 6 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और इसे केल्ट्रॉन कंपनी के सहयोग से डेवलप किया गया है।

WAIT
WALK
PUSH BUTTON TO CROSS

सड़क के दोनों ओर एक-एक पेलिकन सिग्नल बॉक्स लगाया गया है। जब किसी पैदल यात्री को सड़क पार करनी होती है, तो उसे सिर्फ बॉक्स पर लगा बटन दबाना होता है। बटन दबाने के बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाला 'वेट ' मैसेज 'वॉक' में बदल जाता है. इसके साथ ही सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन से रेड हो जाता है।

कैसे करता है यह सिस्टम?

इसके बाद पैदल यात्री को सड़क पार करने के लिए करीब 25 सेकेंड का समय मिलता है। समय पूरा होने से पहले हूटर बजता है, जिससे लोगों को संकेत मिल जाता है कि अब सिग्नल सामान्य स्थिति में लौटने वाला है। इसके बाद अगले 30 सेकंड तक सिस्टम दोबारा एक्टिव नहीं होगा, ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारु रूप से जारी रह सके। पेलिकन सिग्नल लगाने वाली कंपनी के मुताबिक, यह पूरी तरह पैदल यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया सिस्टम है। सड़क पार करने के दौरान सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि पैदल यात्रियों को वाहनों के बीच से निकलना पड़ता है।

हालांकि तकनीक लगाना आसान है लेकिन लोगों को उसके नियमों का पालन कराना कहीं ज्यादा मुश्किल है। कई वाहन चालक रेड सिग्नल होने के बावजूद रुक नहीं रहे थे। इसे देखते हुए नगर निगम ने ट्रैफिक पुलिस से भी सहयोग मांगा है। अधिकारियों का मानना है कि इस सिस्टम की सफलता सिर्फ मशीन पर नहीं, बल्कि लोगों की जागरूकता पर निर्भर करेगी। सीजी रोड पर लगाया गया यह पहला पेलिकन सिग्नल एक पायलट प्रोजेक्ट है। यदि लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और नियमों का पालन होता है, तो अहमदाबाद के अन्य व्यस्त इलाकों में भी ऐसे सिग्नल लगाए जाएंगे।

मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की सुरंगों में पहली बार टनल हुड का प्रयोग

508 किमी लंबा है रेल मार्ग

ब्लिट्ज ब्यूरो

मुंबई। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) की सुरंगें महत्वपूर्ण प्रगति के बाद निर्माण के अगले चरण में प्रवेश कर रही हैं, जहां इसमें भारतीय रेलवे में पहली बार पेश की जा रही एक अनूठी विशेषता को शामिल किया जाएगा।

508 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में महाराष्ट्र में सात और गुजरात में एक पहाड़ी सुरंगें शामिल हैं। प्रत्येक सुरंग के दोनों सिरों पर सुरंग के आवरण या प्रवेश द्वार के आवरण होंगे। गुजरात के वलसाड में बन रही एकमात्र सुरंग का प्रवेश द्वार का आवरण आकार ले चुका है और पूरा होने के करीब है।

“भारत में रेलवे सुरंगों के लिए इस तरह की टनल हुड तकनीक को डिजाइन और लागू किए जाने का यह पहला मौका है। इसे तेज गति वाली ट्रेनों द्वारा उत्पन्न दबाव तरंगों के कारण होने वाले टनल बूम प्रभाव को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है,” परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने कहा।

सुरंगों के लिए आवरण की आवश्यकता क्यों होती है

महाराष्ट्र की बुलेट ट्रेन की सुरंगें पालघर जिले में स्थित हैं, जहां इनका मार्ग सह्याद्री पर्वतमाला के दुर्गम भूभाग से होकर गुजरता है। यहां पुलों की जगह सुरंगों का उपयोग किया गया है, जिससे इंजीनियरिंग का स्तर और भी जटिल हो जाता है। प्रत्येक सुरंग के दोनों सिरों पर सुरंग के आवरण या प्रवेश द्वार के आवरण होंगे।

“भारत में रेलवे सुरंगों के लिए इस तरह की टनल हुड तकनीक को डिजाइन और लागू किए जाने का यह पहला मौका है। इसे तेज गति वाली ट्रेनों द्वारा उत्पन्न दबाव तरंगों के कारण होने वाले टनल बूम प्रभाव को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है,”

सुरंग के प्रवेश और निकास द्वार पर बेलनाकार संरचनाएं बनाई जाती हैं जिनमें दबाव कम करने वाले वेंट या खिड़कियां होती हैं। बुलेट ट्रेनों का संचालन करने वाले देशों में उच्च गति रेल प्रणालियों में यह एक आम विशेषता है, जहां ट्रेनें 300 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं।

टनल हुड की आवश्यकता के बारे में, एनएचएसआरसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब एक हाई-स्पीड ट्रेन सुरंग में प्रवेश करती है, तो यह अपने आगे बड़ी मात्रा में हवा को धकेलती है, जो एक सिलेंडर के अंदर चलने वाले पिस्टन के समान है। “हवा के इस अचानक संपीड़न से दबाव तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सुरंग से होकर गुजरती हैं। यदि इन्हें ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो ये दबाव तरंगें ट्रेन के सुरंग से बाहर निकलते समय विस्फोट के समान तेज आवाज पैदा कर सकती हैं,” अधिकारी ने कहा।

“सुरंग के हुड खुले वातावरण और सुरंग के बंद स्थान के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। हवा को धीरे-धीरे अंदर और बाहर जाने की अनुमति देकर, वे दबाव परिवर्तनों को नियंत्रित करने और सिस्टम के समग्र वायुगतिकीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं,” अधिकारी ने आगे कहा।

सुरंग के ऊपरी हिस्से में लगी खिड़कियां तेज गति वाली ट्रेनों द्वारा उत्पन्न वायु दाब को धीरे-धीरे कम करने में मदद करती हैं। प्रत्येक सुरंग में खिड़कियों की संख्या अलग-अलग होती है।

एनएचएसआरसीएल के अनुसार, पालघर की सुरंगों में 20 से 26 खिड़कियां होंगी। इसके अलावा, इन ऊपरी हिस्सों का आकार प्रत्येक तरफ 31 मीटर से 45 मीटर तक होता है, जिससे सुरंग की कुल लंबाई बढ़ जाती है।

ब्लिट्ज विशेष

विकास के रोडमैप से और चमकेगा पूर्वोत्तर का चेहरा

गजेन्द्र शेखावत ने पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए बताया भारत का प्रवेश द्वार

नई दिल्ली। मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन 2026 का समापन हो गया। दो दिवसीय इस सम्मेलन में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, निवेशकों, उद्यमियों और बुनियादी ढांचा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में पूर्वोत्तर भारत के विकास, निवेश और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसका आयोजन बिल्ड इंडिया द्वारा कराया गया। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

मुख्य अतिथि ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत को कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक इस क्षेत्र में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, जलमार्ग, डिजिटल नेटवर्क और ऊर्जा परियोजनाओं पर 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। शेखावत ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास केवल सड़क और पुल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों को अवसरों, सेवाओं और बाजारों से जोड़ना भी है। उन्होंने पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार बताते हुए इसके पर्यटन और निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया।

सम्मेलन के दूसरे दिन पर्यटन, औद्योगिक विकास, हरित ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और स्टार्टअप्स पर कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए. टिपरा मोथा के अध्यक्ष प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन ने कहा कि पर्यटन का लाभ सीधे स्थानीय समुदायों तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संस्कृति को बचाए रखते हुए विकास पर जोर दिया।

मेघालय के मुख्य सचिव डॉ. शकील पी. अहमद ने कहा कि पूर्वोत्तर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार तथा उद्यमिता के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने आतिथ्य, नर्सिंग और देखभाल सेवाओं से जुड़े प्रशिक्षण केंद्रों में निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई।

मिथिला की उड़ान को मिली नई ऊंचाई

ब्लिट्ज ब्यूरो

दरभंगा। पूर्वी भारत के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रीय हवाई अड्डों में शुमार दरभंगा एयरपोर्ट पर विगत दिवस यात्री सुविधा दिवस उत्साह और उल्लास के माहौल में मनाया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, यात्रियों के स्वागत, रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह के बीच एयरपोर्ट की उपलब्धियों को भी साझा किया गया।

दीप प्रज्ज्वलन से हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ

दरभंगा हवाई अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद सह एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष डा. गोपाल जी ठाकुर ने अधिकारियों एवं सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि स्थापना के बाद से दरभंगा एयरपोर्ट ने विकास की नई इबारत लिखी है।

प्रमुख शहरों से जुड़ा मिथिला का आसमान

डा. गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध करा रहा है। यह पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए गर्व की बात है।

सौर संयंत्र बड़ी उपलब्धि

उन्होंने छह मई 2026 से सीआईएसएफ की तैनाती को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। साथ ही एयरपोर्ट परिसर में 100 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को ग्रीन टैरिफ एनर्जी की दिशा में सार्थक पहल बताया।

गुलाब के फूलों से हुआ यात्रियों का स्वागत

यात्री सुविधा दिवस पर एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों का गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रियों ने एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं और सुविधाओं की सराहना भी की।

मिथिला संस्कृति की बिखरी छटा

कार्यक्रम में पारंपरिक मिथिला स्वागत गान, झिझिया नृत्य तथा अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। यात्रियों और अतिथियों ने कलाकारों की प्रस्तुति की जमकर सराहना की।

कर्मियों और कलाकारों को मिला सम्मान

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों, महिला कर्मचारियों तथा अग्रिम पंक्ति में कार्यरत कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सांसद ने उनके योगदान की सराहना की।

यात्रियों से जाना सुविधाओं का हाल

डा. गोपाल जी ठाकुर ने एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली। यात्रियों द्वारा व्यवस्था की प्रशंसा को उन्होंने मिथिला क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण बताया तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू एवं सीएम सम्राट चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया।

रक्तदान शिविर में युवाओं का उत्साह

एयरपोर्ट अथारिटी के तत्वावधान में डीएमसीएच द्वारा लगाए गए मेडिकल कैंप एवं रक्तदान शिविर में सांसद ने रक्तदाताओं और एयरपोर्ट कर्मियों का उत्साहवर्धन किया।

अब कोरियर कंपनियों की तर्ज पर डाक विभाग देगा फ्रेंचाइजी

ब्लिट्ज ब्यूरो

मुजफ्फरपुर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे या रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं के लिए डाक विभाग आत्मनिर्भर बनने का नया अवसर लेकर आया है। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी योजना के तहत युवक-युवतियां और छोटे व्यवसायी अपने क्षेत्र में डाक सेवाओं का संचालन कर स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं।

इस योजना के माध्यम से न सिर्फ युवाओं को नियमित आय का स्रोत मिलेगा, बल्कि लोगों को भी अपने आसपास ही डाक सेवाओं की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

डाक सेवाओं के विस्तार की पहल

रेल डाक सेवा (आरएमएस) 'यू' मंडल, मुजफ्फरपुर के अधीक्षक डॉ. आशुतोष आदित्य ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों तक डाक सेवाएं पहुंचाना है, जहां नियमित डाकघर नहीं हैं या सेवाओं की पहुंच सीमित है। विभाग चाहता है कि आम लोगों को उनके नजदीक ही डाक संबंधी सुविधाएं मिल सकें और युवाओं को रोजगार का नया अवसर प्राप्त हो।

इन सेवाओं का कर सकेंगे संचालन

फ्रेंचाइजी प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक और पार्सल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। इसके अलावा डाक टिकट और राजस्व टिकट की बिक्री भी कर सकेंगे। उन्हें डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) सहित विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी भी दी जाएगी।

कमीशन के रूप में होगी कमाई

डाक विभाग इन सेवाओं के संचालन के बदले निर्धारित दर पर कमीशन देगा। इससे फ्रेंचाइजी संचालकों को नियमित आय प्राप्त होगी।

ब्लिट्ज ब्यूरो

मेघालय के मौसिनराम गांव में होती है दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश

नई दिल्ली। स्कूल में जब भी बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि कहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो हमेशा जनरल नॉलेज की किताब में चेरापूंजी का नाम आता था। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश या गीली जगह चेरापूंजी नहीं है, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित एक छोटा-सा गांव है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और कुछ नया और अनोखा देखना पसंद करते हैं तो गर्मियों की छुट्टियों में आप मेघालय में स्थित दुनिया के सबसे गीले स्थान पर जा सकते हैं, इस गांव में 12 महीने औसतन करीब 11 हजार 872 मिमी बारिश होती है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है और इसलिए यह जगह अपने आप में ही एक अनोखा स्थान है।

जिन लोगों को बारिश अच्छी लगती है, वो लोग इस जगह को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको यहां बारिश के साथ-साथ एक अलग ही सुकून महसूस होगा। मेघालय बेहद सुंदर प्रदेश है और इसके छोटे-छोटे गांव किसी ना किसी खूबी के लिए जाने जाते हैं।

गांव में 12 महीने औसतन करीब 11 हजार 872 मिमी वर्षा

मेघालय में स्थित मौसिनराम भले ही एक छोटा-सा गांव है, लेकिन धरती का सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के तौर पर यह पूरी दुनिया में मशहूर है। दूर-दूर से लोग इस जगह को देखने आते हैं, हालांकि कई भारतीय आज भी इस जगह से अनजान हैं।

खूबसूरत पहाड़ों से घिरा है मौसिनराम

मौसिनराम चारों ओर से हरी-भरी पहाड़ियों, घने जंगलों और बादलों से घिरे वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां का मौसम ज्यादातर नम और ठंडा रहता है। मानसून सीजन में तो ऐसा लगता है जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। बारिश मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, प्राकृतिक सुंदरता को और भी निखारती है।

क्यों होती है इतनी ज्यादा बारिश?

मौसिनराम में 12 महीने बारिश होती है, यहां सबसे ज्यादा बारिश होने का मुख्य कारण इसकी भौगोलिक स्थिति है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से भरी हवाएं जब खासी पहाड़ियों से टकराती हैं, तो वे ऊपर उठती हैं और भारी बारिश बनकर गिरती हैं। इस प्रोसेस को ओरोग्राफिक बारिश कहा जाता है, यही कारण है कि यहां साल के ज्यादातर समय बारिश होती रहती है।

कावेरी जल विवाद पर फिर गरमाई तमिलनाडु की राजनीति

मेकेदातु बांध के खिलाफ सीएम विजय ने विधानसभा में प्रस्ताव किया पेश

ब्लिट्ज ब्यूरो

चेन्नई। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। मुख्यमंत्री विजय ने राज्य विधानसभा में कर्नाटक सरकार की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना के खिलाफ अहम प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री ने सदन के सभी दलों से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समर्थन देने की अपील की और इसे तमिलनाडु के किसानों और राज्य के जल अधिकारों का रक्षा का मुद्दा बताया। विधानसभा में इस प्रस्ताव को कांग्रेस नेता राकेश कुमार और वीसीके नेता और मंत्री वन्नियारासु ने समर्थन दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतराज्यीय नदी जल विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर तमिलनाडु को एकजुट रहना चाहिए।

कर्नाटक सरकार के कदम को बताया एकतरफा

मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट कहा कि कर्नाटक सरकार का यह कदम एकतरफा है और यह कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 2007 के अंतिम फैसले तथा सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश की भावना के खिलाफ है। प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक ने न तो अन्य संबंधित राज्यों की सहमति ली है और न ही केंद्र सरकार से जरूरी मंजूरी प्राप्त की है, इसलिए यह परियोजना स्वीकार्य नहीं हो सकती। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि मेकेदातु परियोजना को किसी भी प्रकार की तकनीकी या पर्यावरणीय मंजूरी न दी जाए। साथ ही केंद्रीय जल आयोग से भी आग्रह किया गया है कि वह कर्नाटक सरकार द्वारा जमा की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की समीक्षा या मंजूरी की प्रक्रिया आगे न बढ़ाए।

कावेरी मुद्दा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बेहद संवेदनशील है और इस पर किसी भी प्रकार का फैसला सभी राज्यों की सहमति से ही होना चाहिए।

आंध्र में दुर्लभ पृथ्वी चुंबक इकाई स्थापित करेगी जापान की कंपनी

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। उन्नत सामग्रियों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी जापान की कंपनी प्रोटीरियल, आंध्र प्रदेश में 2,250 करोड़ रुपये के निवेश से दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक निर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। इस परियोजना से जुड़े सूत्रों के अनुसार, यह भारत की स्थानीय दुर्लभ पृथ्वी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और चीनी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अनाकापल्ली जिले के अच्युतपुरम में स्थित यह परियोजना प्रति वर्ष 1.2 किलो टन (केटीपीए) सिंटर्ड नियोडिमियम-आयरन-बोरारन (एनडीएफ ईबी) स्थायी चुंबकों का उत्पादन करेगी, जो इलेक्ट्रिक वाहनों , पवन टर्बाइनों, औद्योगिक मोटरों, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों में उपयोग होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से हैं । राज्य निवेश प्रोत्साहन समिति ने पिछले सप्ताह अपनी बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी। यह प्रस्तावित निवेश ऐसे समय में हो रहा है जब भारत आयातित दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों पर निर्भरता कम करने और रणनीतिक क्षेत्रों में स्वदेशी विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में सिंटरड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित प्रोत्साहन कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जो इस क्षेत्र के राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करता है।

प्रोटीरियल, जिसका पूर्व नाम हिताची मेटल्स था, को एनडीएफईबी चुंबक प्रौद्योगिकी के वैश्विक अग्रदूतों में से एक माना जाता है और यह विश्व स्तर पर उन्नत चुंबकीय सामग्रियों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। जापानी कंपनी ने पिछले वर्ष ₹45,000 करोड़ का समेकित राजस्व अर्जित किया और यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप, चीन और एशिया में परिचालन करती है।

केरल में मिला निपाह वायरस का नया केस, 15 लोगों को किया क्वारंटाइन

ब्लिट्ज ब्यूरो

तिरुवंतपुरम। केरलम के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस का एक नया मामला सामने आया है। जिला कलेक्टर एमएस माधविकुट्टी ने इसकी पुष्टि की। जिला अधिकारी ने बताया कि वायरस से संक्रमित व्यक्ति की पहचान 43 वर्षीय रामनट्टुकारा के रूप में हुई है जो फिलहाल कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है।

जिला कलेक्टर ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति की गतिविधियों का एक विस्तृत रूट मैप तैयार कर लिया गया है। हालांकि, राहत की बात ये है कि अभी तक मरीज के संपर्क में आए 77 लोगों में से किसी में भी बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं।

अधिकारी ने बताया कि रामनट्टुकारा के संपर्क में आए कुल 77 लोगों की पहचान कर ली गई है, जिनमें 14 परिवार के सदस्य, 5 दोस्तों-सहकर्मियों और 58 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। इनमें से 15 लोगों को अति जोखिम वाली कैटेगरी में रखा गया है और इन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है।

प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार इस मरीज ने हाल ही में एक गोदाम किराए पर लेकर उसकी खुद सफाई की थी, जिसके दौरान उसके संक्रमित होने की आशंका है। प्रशासन ने स्थिति से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम की बैठकें बुलाई हैं और जिला चिकित्सा कार्यालय में एक विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है।

उन्होंने बताया कि ये बात सामने आई कि मरीज कई लोगों के संपर्क में आया था। मरीज ने सबसे पहले एक अस्पताल के आउटपेशेंट (ओपीडी) अनुभाग का दौरा किया था और बाद में अपनी एमआरआई और इकोकार्डियोग्राफी जांच भी करवाई थी।

बता दें कि केरल स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार, निपाह एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। फ्रूट बैट्स (चमगादड़) इसके प्राकृतिक भंडार हैं और ये सूअरों को भी बीमार कर सकता है। इससे दिमाग में सूजन आ जाती है। मंत्री ने जनता से पैनिक न होने की अपील करते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज में दवाइयों और पीपीई किट की पूरी व्यवस्था है। सूचना के लिए कंट्रोल रूम नंबर 0495-2373901 और 9072007767 जारी किए गए हैं।

इंडिया की 'एग सिटी' है नमक्कल, रोजाना 7 करोड़ अंडों का उत्पादन

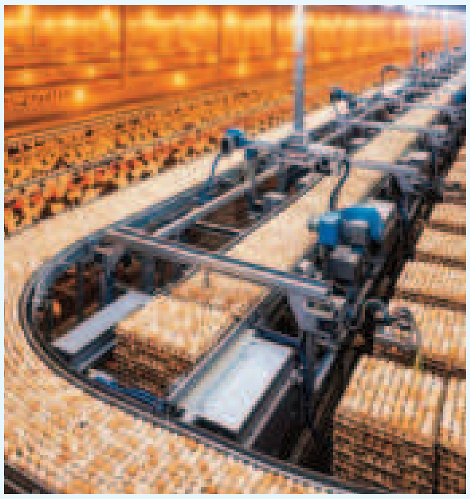

ब्लिट्ज ब्यूरो

दुबई, अफ्रीका, अमेरिका तक पहुंचते हैं अंडे

नई दिल्ली। तमिलनाडु का नमक्कल सिर्फ जिला मुख्यालय नहीं, बल्कि भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री का ऐसा केंद्र है जिसे पूरे देश में 'एग सिटी' के नाम से जाना जाता है। यहां हर दिन करोड़ों अंडों का उत्पादन होता है और यही वजह है कि नमक्कल भारत के सबसे बड़े अंडा निर्यात केंद्रों में शामिल है। देश के कई राज्यों की जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ यहां से खाड़ी देशों, अफ्रीका और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक अंडों की सप्लाई की जाती है। पोल्ट्री उद्योग ने इस शहर की अर्थव्यवस्था को नई पहचान दी है और हजारों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया है।

नमक्कल में पोल्ट्री उद्योग का आकार बेहद विशाल है। विभिन्न उद्योग संगठनों के अनुसार यहां प्रतिदिन करीब 6 से 7 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है। जिले में 1,100 से अधिक बड़े और मध्यम पोल्ट्री फार्म संचालित होते हैं, जिनमें करोड़ों लेयर मुर्गियां अंडे देती हैं। उत्पादन के इस स्तर ने नमक्कल को भारत के सबसे बड़े अंडा उत्पादन केंद्रों में शामिल कर दिया है। यही कारण है कि देश के कई हिस्सों में बिकने वाले अंडों की आपूर्ति सीधे या परोक्ष रूप से नमक्कल से जुड़ी रहती है।

हजारों करोड़ रुपये का सालाना कारोबार

यदि अंडे की औसत थोक कीमत 4.5 से 5 रुपये प्रति अंडा मानी जाए तो नमक्कल में प्रतिदिन लगभग 30 से 35 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। इस आधार पर सालाना कारोबार 10,000 करोड़ रुपये से अधिक बैठता है। इसके अलावा अंडों से जुड़े प्रोसेस्ड उत्पाद, फीड उद्योग, परिवहन, पैकेजिंग और निर्यात गतिविधियां अलग से इकोनॉमिक वैल्यू पैदा करती हैं। पोल्ट्री सेक्टर की वजह से नमक्कल की स्थानीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक अंडा उद्योग पर निर्भर हो चुकी है और यहां हजारों परिवारों की आजीविका इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है।

किन राज्यों में जाते हैं नमक्कल के अंडे ?

नमक्कल में उत्पादित अंडों की खपत केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। बड़ी मात्रा में अंडे केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में भेजे जाते हैं। तमिलनाडु की सरकारी पोषण योजनाओं और मिड-डे मील कार्यक्रमों में भी नमक्कल के अंडों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में तीसरा स्थान

ब्राजील को पछाड़कर पाया यह गौरव: प्रह्लाद जोशी

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

जोशी ने कहा कि 2025-26 (मार्च 2026 तक) के दौरान भारत का कुल विद्युत उत्पादन 1,845.921 बुशेल (बीयू) तक पहुंच गया। कुल उत्पादन में गैर-जीवाश्म ईन्धन की हिस्सेदारी 2025-26 में 29.2 प्रतिशत (538.97 बुशेल) तक पहुंच गई।

ब्लिट्ज विशेष

नई दिल्ली। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि भारत इस रैंकिंग में ब्राजील से आगे निकल गया है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने दिसंबर 2025 तक के आंकड़े जारी किए हैं।

यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 55.3 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल की है।

प्रह्लाद जोशी ने यह भी बताया कि जुलाई 2025 में भारत ने विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की अब तक की सबसे अधिक हिस्सेदारी हासिल कर ली है। नवीकरणीय ऊर्जा ने देश की कुल 203 गीगावाट बिजली मांग का 51.5 प्रतिशत पूरा किया। उन्होंने यह भी कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश में गैर-जीवाश्म ईन्धन स्त्रोतों से कुल 283.46 गीगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

जोशी ने कहा कि 2025-26 (मार्च 2026 तक) के दौरान भारत का कुल विद्युत उत्पादन 1,845.921 बुशेल (बीयू) तक पहुंच गया। कुल उत्पादन में गैर-जीवाश्म ईन्धन की हिस्सेदारी 2025-26 में 29.2 प्रतिशत (538.97 बुशेल) तक पहुंच गई। भारत ने पेरिस समझौते के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) के तहत निर्धारित 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले, जून 2025 में गैर-जीवाश्म ईन्धन स्त्रोतों से अपनी संचयी विद्युत स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत हासिल कर लिया।

उन्होंने कहा कि सीओपी26 में माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक गैर-जीवाश्म स्त्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

अब तक तक देश में गैर-जीवाश्म ईन्धन स्त्रोतों से कुल 283.46 गीगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसमें 274.68 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (150.26 गीगावाट सौर ऊर्जा, 56.09 गीगावाट पवन ऊर्जा, 11.75 गीगावाट जैव ऊर्जा, 5.17 गीगावाट लघु जल विद्युत, 51.41 गीगावाट वृहद जल विद्युत) और 8.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता शामिल है।

नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता (जीडब्ल्यू)

देश	क्षमता	देश	क्षमता
चीन	2258.02	जर्मनी	199.92
अमेरिका	467.92	जापान	134.53
भारत	250.52	कनाडा	110.51
ब्राजील	228.20	**विश्व**	**5149.28**

2025-26 में गैर-जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई है, जो किसी भी वर्ष में हुई सबसे अधिक वृद्धि है। (इससे पहले सबसे अधिक वृद्धि 2024-25 के दौरान 29.5 गीगावाट थी)।

सौर ऊर्जा से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो 2025-26 के दौरान स्थापित 44.61 गीगावाट में से 16.3 गीगावाट (36 प्रतिशत) का योगदान देती है। इसमें पीएम कुसुम के तहत 7.6 गीगावाट और रूफटॉप सौर ऊर्जा से 8.7 गीगावाट शामिल है।

- 2025-26 के दौरान, 6.05 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जो एक वर्ष में अब तक की सबसे अधिक क्षमता वृद्धि है। (पिछले वर्ष पवन क्षमता वृद्धि 4.15 गीगावाट थी)।
- नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की स्थापित क्षमता 2014 से 3.59 गुना बढ़ गई है - मार्च 2014 में 76.38 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2026 में 274.68 गीगावाट हो गई है, यानी 198.30 गीगावाट की वृद्धि हुई है।
- सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2014 से 53.28 गुना बढ़ गई है।
- मार्च 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2026 में 150.26 गीगावाट हो गई है, यानी 147.44 गीगावाट की वृद्धि हुई है।
- पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2014 से 2.66 गुना बढ़ गई है। मार्च 2014 में 21.04 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2026 में 56.09 गीगावाट हो गई है, यानी 35.05 गीगावाट की वृद्धि हुई है।
- पवन टरबाइन निर्माण क्षमता 2014 में 10 गीगावाट से बढ़कर 31.03.2026 तक लगभग 24 गीगावाट हो गई है।
- सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2014 में 2.3 गीगावाट से बढ़कर 31.03.2026 तक लगभग 172 गीगावाट हो गई ।

वित्त वर्ष 2025-26 में, अनुमानित व्यय (बीई) 26,549.38 करोड़ रुपये और पुनर्भुगतान (आरई) 25,301.22 करोड़ रुपये के मुकाबले 24,176.68 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है, जो बीई का लगभग 91.0 प्रतिशत और आरई का लगभग 95.5 प्रतिशत है।

वित्त वर्ष 2025-26 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा कार्यान्वित की गई प्रमुख नीतियां-

नवीकरणीय ऊर्जा

उपकरणों और उनके निर्माण में उपयोग होने वाले पुर्जों पर जीएसटी की दर 22.09.2025 से 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इससे घरेलू खरीदारों - परियोजना विकासकर्ताओं, डिस्कॉम, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलर और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को सौर उपकरणों की लागत कम होने से लाभ होगा।

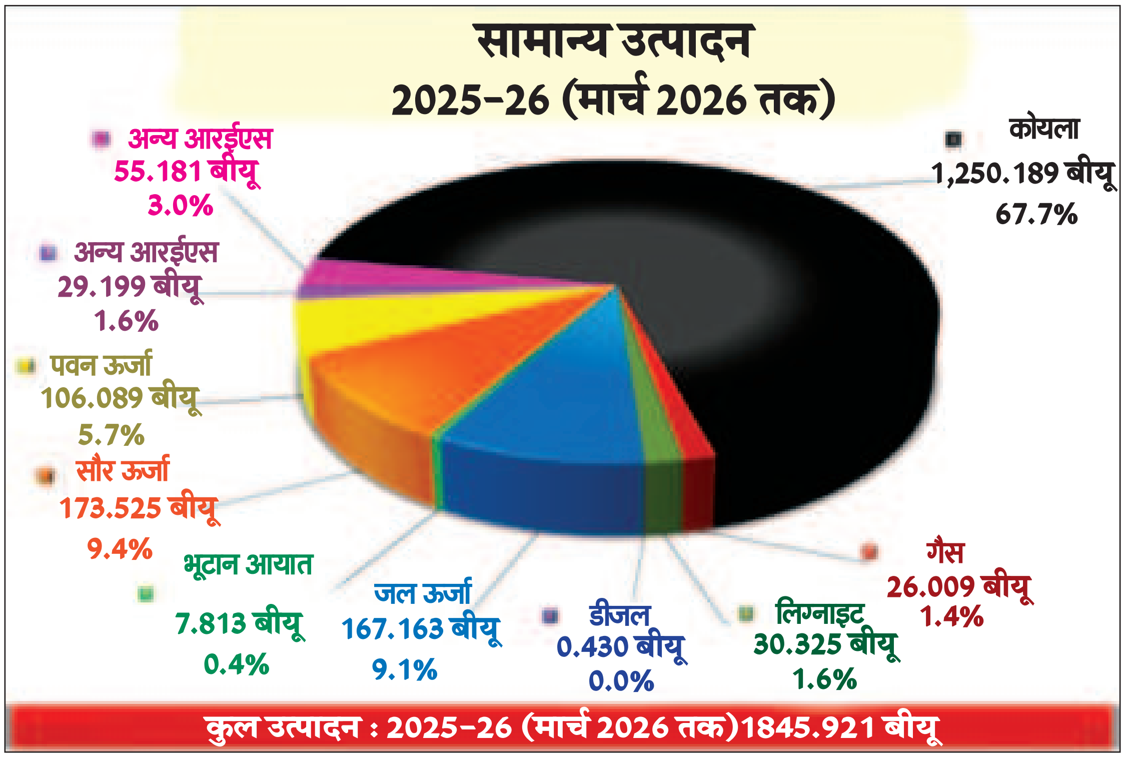

सामान्य उत्पादन
2025-26 (मार्च 2026 तक)

कुल उत्पादन : 2025-26 (मार्च 2026 तक)1845.921 बीयू

- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए लिथियम-आयन सेल निर्माण हेतु पूंजीगत वस्तुओं पर बीसीडी छूट का विस्तार किया गया है (2 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2028 तक प्रभावी)। इससे मुख्य रूप से चीन से आयातित बैटरी पैकों पर निर्भरता कम होगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर भारत लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी।
- अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण आयात निगरानी प्रणाली (आरईईआईएमएस) पोर्टल, महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के आयात पैटर्न की वास्तविक समय में ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में अधिक पारदर्शिता, नियामक अनुपालन और आयातित घटकों के दुरुपयोग की रोकथाम सुनिश्चित होती है।
- एमएनआरई की सिफारिश पर, एमओपी ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत आरसीओ अनुपालन ढांचे को संशोधित किया है, जिससे अक्टूबर 2023 की पिछली अधिसूचना निरस्त हो गई है। राज्य-स्तरीय आरपीओ लक्ष्य इस एकीकृत आरसीओ ढांचे में समाहित हैं, जिससे विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत दोहरे दायित्व समाप्त हो गए हैं।
- 26.06.2025 को जारी किए गए सीईआरसी (अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क और हानियों का बंटवारा) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा और बीईएसएस परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस छूट की प्रक्रिया प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें अप्रत्याशित घटना (जैसे कि पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता) या नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर के कारण न होने वाले कारणों से देरी होने की स्थिति में छूट के विस्तार का प्रावधान भी शामिल है।
- सीईआरसी (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 ने गैर-सौर घंटे कनेक्टिविटी ढांचा पेश किया है। इससे पारेषण नेटवर्क का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी।
- सीईआरसी द्वारा वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट (वीपीपीए) के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वीपीपीए नामित उपभोक्ताओं को उनके आरसीओ लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक अतिरिक्त साधन प्रदान करता है।
- बहुराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र (एमएनआरई) द्वारा 500 मेगावाट क्षमता वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर-आधारित अनुबंध (सीएफडी) की पायलट योजना जारी की गई है। विश्व स्तर पर सिद्ध यह सीसीएफडी तंत्र, प्रतिस्पर्धी और बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण को बनाए रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को स्थिर राजस्व की गारंटी देता है।
- भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति सितंबर 2025 में जारी की गई थी, जो देश भर में भूतापीय संसाधनों की खोज, विकास और वाणिज्यिक उपयोग में तेजी लाने के लिए एक व्यापक रणनीतिक ढांचा प्रदान करती है।

मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास (एचआरडी) ढांचे के तहत जैव-ऊर्जा मित्र कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य बायोमास एग्रीगेटर्स, फीडस्टॉक डिपो ऑपरेटर्स और कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) तकनीशियनों सहित प्रमुख हितधारकों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करके नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

मंत्रालय ने 27 जनवरी 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संशोधित सौर प्रणाली, उपकरण और घटक माल आदेश, 2025 (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) 2025) जारी किया है। यह संशोधित आदेश पूर्ववर्ती क्यूसीओ, 2017 का स्थान लेता है और इसमें सौर पीवी मॉड्यूल, स्टोरेज बैटरी और एसपीवी इनवर्टर के लिए भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण शामिल हैं। यह आदेश एसपीवी मॉड्यूल की दक्षता निर्धारण के लिए मानक भी प्रदान करता है।

जीवाश्म ईंधन उत्पादन (71 प्रतिशत) वर्ष 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन स्त्रोतों से बिजली उत्पादन 1306.951 बुशेल रहा , जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 1363.069 बुशेल था, जो 4.12 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान कोयला आधारित बिजली उत्पादन 1250.189 बुशेल रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.69 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

गैर-जीवाश्म (29 प्रतिशत) और आरई कुल ऊर्जा उत्पादन में गैर-जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्पादन की हिस्सेदारी लगभग 29.2 प्रतिशत रही है।

2025-26 के दौरान, कुल उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा (बड़े जलविद्युत संयंत्रों सहित) का हिस्सा 26.2 प्रतिशत रहा है ।

वर्ष 2025-26 के दौरान नवीकरणीय स्त्रोतों (बड़े जलविद्युत को छोड़कर) से उत्पादन 308.813 बुशेल है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 255.009 बुशेल था, जो 21.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

पवन ऊर्जा उत्पादन 106.089 बुशेल रहा है, जो 27.29 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है ।

ऊर्जा बदलाव की तैयारी में भारत आगे बढ़ा: डब्ल्यूईएफ

ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2026 में स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क शीर्ष तीन स्थानों पर बरकरार रहे, जबकि भारत दो स्थान ऊपर चढ़कर 70वें स्थान पर पहुंच गया

नई दिल्ली। बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों के बीच वैश्विक ऊर्जा बदलाव की तैयारी में एक दशक से अधिक समय में पहली बार गिरावट आई है लेकिन भारत इस क्षेत्र में सबसे मजबूत सुधार दर्ज करने वाले देशों में शामिल है। विश्व आर्थिक मंच के सूचकांक में भारत दो स्थान ऊपर चढ़कर 70वें स्थान पर पहुंच गया है।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के विगत दिवस जारी ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2026 में स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क शीर्ष तीन स्थानों पर बरकरार रहे, जबकि भारत दो स्थान ऊपर चढ़कर 70वें स्थान पर पहुंच गया है।

भारत की स्थिति

रिपोर्ट के मुताबिक, ऊर्जा बदलाव के लिए तैयारी के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेज सुधार करने वाले देशों में शामिल रहा है। इसमें बुनियादी ढांचे में तेज वृद्धि, समानता, स्थिरता और वित्तीय निवेश में सुधार का योगदान रहा।

WORLD ECONOMIC FORUM

कम कार्बन उत्सर्जन वाली नौकरियां

रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2024 में कम कार्बन उत्सर्जन वाली नौकरियों का हिस्सा 24 प्रतिशत बढ़ा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार 2023 की तुलना में 25 प्रतिशत बढ़कर 13 लाख तक पहुंच गया जिसमें जलविद्युत सबसे बड़ा रोजगार स्त्रोत रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति में नवीकरणीय क्षमता का विस्तार, बिजली ग्रिड का विस्तार और हरित हाइड्रोजन पर जोर प्रमुख कारक हैं।

ऊर्जा प्रणाली में चुनौतियां

यह रिपोर्ट कहती है कि ऊर्जा प्रणाली अधिक विखंडित एवं सुरक्षा केंद्रित होती जा रही है क्योंकि देश स्थिरता, किफायत और जुझारूपन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने ऊर्जा मांग में लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि का योगदान दिया, लेकिन उन्हें ऊंची वित्तपोषण लागत एवं बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की ऊर्जा बदलाव में कहा जा रहा है कि वह इस मामले में वैश्विक स्तर पर सबसे तेज सुधार करने वाले देशों में शामिल है।

भारत को ऊंची वित्तपोषण लागत एवं बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

पेटेंट के मामले में जियो टॉप लीग में शामिल

हुआवेई, सैमसंग, क्वालकॉम और नोकिया जैसे वर्ल्ड लीडर्स की श्रेणी में पहुंची

ब्लिट्ज विशेष

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की टेक्नोलॉजी शाखा, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (जेपीएल) ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन (विपो) द्वारा जारी लेटेस्ट पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी (पीसीटी) रैंकिंग में ग्लोबल टॉप 20 में जगह बनाई है। कंपनी ने कहा कि इस उपलब्धि के साथ वह पब्लिश हुए पीसीटी डेटा के आधार पर ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 20 आवेदकों में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय टेक्नोलॉजी इनोवेटर बन गई है।

रिलायंस जियो 2025 की रैंकिंग में 320 स्थान ऊपर चढ़ी, जिससे वह दुनिया भर में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इनोवेटर कंपनियों में से एक बन गई है। लेटेस्ट Wipo रैंकिंग में कंपनी अब हुआवेई, सैमसंग, क्वालकॉम, एलजी, पैनासोनिक, नोकिया, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ खड़ी है।

5जी, 6जी और एआई पर फोकस

रिलायंस जियो के मुताबिक, उसका पेटेंट पोर्टफोलियो अगली पीढ़ी की डिजिटल टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। इनोवेशन के क्षेत्रों में 5जी, 5जी एडवांस्ड, 6जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), एआई-नेटिव नेटवर्क, क्लाउड-नेटिव प्लेटफॉर्म, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी, कोर नेटवर्क सॉफ्टवेयर, एज इंटेलिजेंस, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, नेटवर्क स्लाइसिंग और डिजिटल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।

कंपनी ने कहा कि विपो रैंकिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में रिसर्च और डेवलपमेंट पर उसके बढ़ते फोकस को दिखाती है और संगठन के भीतर हो रहे इनोवेशन के पैमाने को उजागर करती है। खास बात यह है कि जियो का 20वें स्थान पर पहुंचना ऐसे साल में हुआ जब ग्लोबल पीसीटी फाइलिंग में एक प्रतिशत से भी कम की बढ़ोतरी हुई थी, जो कंपनी की पेटेंट गतिविधि की रफ्तार को दिखाता है।

इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश एम. अंबानी ने कहा कि यह रैंकिंग जियो को एक डीप-टेक कंपनी में बदलने की दिशा में की गई वर्षों की मेहनत को दर्शाती है। "विपो पीसीटी रैंकिंग में जियो प्लेटफॉर्म्स का दुनिया की टॉप 20 कंपनियों में शामिल होना, एक डीप-टेक कंपनी बनने की हमारी बरसों की कोशिशों को दिखाता है। यह कई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जियो में हो रहे इनोवेशन की तेज़ी को दर्शाता है, जो आने वाले सालों में और बढ़ेगा।"

अंबानी ने यह कामयाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न को समर्पित की, जिसका मकसद भारत को टेक्नोलॉजी का क्रिएटर, ओनर और एक्सपोर्टर बनाना है। उन्होंने कहा कि जियो को भारत के ग्लोबल डीप-टेक पावरहाउस बनने के सफ़र में योगदान देने पर गर्व है।

पोर्टफोलियो का विस्तार जारी

जियो प्लेटफॉर्म्स ने बताया कि 31 मार्च, 2026 तक उसने दुनिया भर में कुल 6,817 पेटेंट फाइल किए थे। इनमें से 2,393 पेटेंट भारत में फाइल किए गए, जबकि 4,424 पेटेंट अंतरराष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्रों में फाइल किए गए।

कंपनी ने यह भी बताया कि अब तक दुनिया भर में 1,009 पेटेंट मंजूर किए जा चुके हैं। इसमें भारत में मंजूर हुए 538 पेटेंट और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मंजूर हुए 471 पेटेंट शामिल हैं।

जियो ने कहा कि यह रैंकिंग उसकी आरएंडडी प्रोडक्टिविटी और उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो की गहराई को बाहरी मान्यता दिलाती है, साथ ही ग्लोबल टेक्नोलॉजी निर्माण के क्षेत्र में भारत में हुए इनोवेशन को भी उजागर करती है।

भविष्य का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना

कंपनी ने कहा कि उसके इनोवेशन के प्रयास उन टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं जिन्हें पहले ही बड़े पैमाने पर विकसित और कमर्शियलाइज़ किया जा चुका है। साथ ही, वह भविष्य की उन टेक्नोलॉजी में भी निवेश कर रही है जिनसे अगली पीढ़ी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आकार मिलने की उम्मीद है।

इनमें 5जी और 6जी रेडियो टेक्नोलॉजी, 5जी और 6जी कोर नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और जियोब्रेन के तहत एजेंटिक एआई पहल शामिल हैं। जियो का बढ़ता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो भारत के टेक्नोलॉजी परिदृश्य में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हटकर ओरिजिनल टेक्नोलॉजी बनाने की ओर एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है जो कई सेक्टर में भविष्य के कमर्शियल इस्तेमाल में सहायक हो सकें।

रिलायंस जियो के मुताबिक, उसका पेटेंट पोर्टफोलियो अगली पीढ़ी की डिजिटल टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। इनोवेशन के क्षेत्रों में 5जी, 5जी एडवांस्ड, 6जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), एआई-नेटिव नेटवर्क, क्लाउड-नेटिव प्लेटफॉर्म, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी, कोर नेटवर्क सॉफ्टवेयर, एज इंटेलिजेंस, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, नेटवर्क स्लाइसिंग और डिजिटल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।

बदलाव के लिए खेती

वर्ल्ड बैंक की पहल से पता चलता है कि खाने की चीजों की अच्छे से प्रोसेसिंग से कई फायदे हो सकते हैं

खेती में बदलाव का अगला फेज सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ाने में भी है। इन एक्टिविटीज से लाखों प्रोडक्टिव नौकरियाँ बन सकती हैं, साथ ही खाने का नुकसान कम हो सकता है और किसानों की इनकम बढ़ सकती है।

अनिमेश श्रीवास्तव

मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ (एमओएफपीआई) ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगुवाई वाली साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फ़ॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ (सैपलिंग) पहल के साथ मिलकर हाल ही में अहमदाबाद में "अनलॉकिंग वैल्यू: साउथ एशिया में रोज़गार पैदा करने और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाना" नाम से एक रीजनल हाई-लेवल पॉलिसी डायलॉग शुरू किया।

इस डायलॉग में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि साउथ एशिया की फूड इकॉनमी का भविष्य सिर्फ प्रोडक्शन से कहीं आगे है। खेत से बाज़ार तक फूड सिस्टम को बदलकर, यह इलाका लाखों नौकरियां पैदा कर सकता है, खाने का नुकसान कम कर सकता है, न्यूट्रिशन बेहतर कर सकता है, इन्वेस्टमेंट ला सकता है, एक्सपोर्ट को मज़बूत कर सकता है और आने वाले दशकों तक सबको साथ लेकर चलने वाली इकॉनमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है। दो दिन की रीजनल बातचीत में लगभग 200 लोग शामिल हुए, जिनमें पॉलिसी बनाने वाले, इंडस्ट्री लीडर, डेवलपमेंट पार्टनर, इनोवेटर, रिसर्चर, स्टार्ट-अप और दक्षिण एशियाई देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस बातचीत में इस इलाके में फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने और मजबूत, सबको साथ लेकर चलने वाले और टिकाऊ फूड सिस्टम बनाने पर चर्चा की गई।

भाग लेने वालों ने सरकारों, बिजनेस, इन्वेस्टर और डेवलपमेंट संस्थानों द्वारा मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया।

इन्वेस्टर को कोल्ड चेन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स हब, प्रोसेसिंग क्लस्टर, एग्रो-इंडस्ट्रियल पार्क और नए एग्री-एंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए बढ़ावा दिया गया। कंपनियों से इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन बनाने, ट्रेसेबिलिटी और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने और वर्कफोर्स स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने का आग्रह किया गया।

बचाने की जरूरत

दक्षिण एशिया अपनी डेवलपमेंट यात्रा में एक अहम मोड़ पर है। हर साल लाखों युवा वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं, इसलिए टिकाऊ नौकरियां बनाना इस इलाके की सबसे ज़रूरी प्राथमिकताओं में से एक बन गया है।

वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इस बात पर ज़ोर दिया कि खेत से आगे फूड सिस्टम को बदलने से रोज़गार, इन्वेस्टमेंट, आर्थिक विकास और गरीबी कम करने के बड़े मौके मिल सकते हैं।

इस इलाके का एग्रीकल्चर सेक्टर हर साल $700 बिलियन से ज़्यादा का है और इसमें लगभग 43 परसेंट वर्कफ़ोर्स को रोज़गार मिलता है। हालांकि, इतने बड़े पैमाने पर होने के बावजूद, एग्रीकल्चर इस इलाके की जीडीपी में सिर्फ लगभग 16 परसेंट का ही योगदान देता है। साउथ एशिया में हर साल पैदा होने वाला 30 परसेंट से ज़्यादा खाना बर्बाद हो जाता है— जो लगभग 300 मिलियन लोगों का पेट भरने के लिए काफी है।

एक्सपर्ट्स ने जोर दिया कि एग्रीकल्चर में बदलाव का अगला फेज सिर्फ़ प्रोडक्शन बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ाने में भी है। ये एक्टिविटीज़ लाखों प्रोडक्टिव नौकरियां पैदा कर सकती हैं, साथ ही खाने के नुकसान को कम कर सकती हैं और किसानों की इनकम बढ़ा सकती हैं।

भारत में, फूड ग्रेन प्रोडक्शन 1950-51 में 51 मिलियन टन से बढ़कर आज 330 मिलियन टन से ज़्यादा हो गया है। प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट भी पिछले दस सालों में दोगुने से ज़्यादा बढ़ गया है, जो लगभग $4.9 बिलियन से बढ़कर $10 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन में लगभग 9 परसेंट और भारत के एक्सपोर्ट में लगभग 13 परसेंट का योगदान देता है।

भारत का अनुभव दिखाता है कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी दखल से खेती की वैल्यू चेन में बदलाव आ सकता है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम का फॉर्मलाइजेशन, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम जैसी खास पहलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, एंटरप्राइजेज को मॉडर्न बनाया है, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है, और कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार किया है।

इस तरक्की के बावजूद, अभी भी बड़े मौके हैं। फूड प्रोसेसिंग कुल रोज़गार का बहुत छोटा हिस्सा है और खेती की उपज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बिना प्रोसेस किया हुआ है।

कोल्ड चेन, स्टोरेज की सुविधाएं, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और मार्केट लिंकेज को मजबूत करके इस सेक्टर में वैल्यू क्रिएशन को काफी बढ़ाया जा सकता है।

दक्षिण एशिया में स्कोप

दक्षिण एशिया के पास फूड सिस्टम में ग्लोबल लीडर बनने के लिए मजबूत बुनियादी बातें हैं। तेज़ी से शहरीकरण, बढ़ता मिडिल क्लास, अच्छी एग्रो-बायोडायवर्सिटी, और सुरक्षित और हाई-क्वालिटी प्रोसेस्ड फ़ूड की बढ़ती माँग इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के नए मौके पैदा कर रही हैं।

इस बदलाव को तेज करने के लिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप एग्रीकनेक्ट और सैपलिंग के ज़रिए एक मिला-जुला तरीका अपना रहा है। एग्रीकनेक्ट, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी रिफॉर्म और प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन के ज़रिए 300 मिलियन किसानों को मार्केट से जोड़ना है। यह पहल पहले से ही भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में प्रोजेक्ट्स और रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रही है।

सैपलिंग एक रीजनल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है जो सरकारों, इन्वेस्टर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स को एक साथ लाता है।

'गाड़ियों से ज्यादा फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का हक'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह हर नागरिक का मौलिक अधिकार

गुलशन वर्मा

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने आम नागरिकों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने अपने इस फैसले में साफ किया है कि फुटपाथ पर पैदल यात्रियों का अधिकार किसी भी मोटर वाहन से ज्यादा होगा।

सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला तब आया, जब अदालत एक बेहद दुखद सड़क हादसे में मुआवजे के मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दर्दनाक हादसे में एक पिता ने अपने महज पांच साल के मासूम बेटे को उस वक्त खो दिया था, जब वो उसे स्कूल लेकर जा रहे थे।

इस मामले में हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि को कम कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने मृतक बच्चे के पिता के लिए मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 11,44,628 रुपये कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस बढ़ी हुई राशि का भुगतान दो महीने के भीतर हर हाल में किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पैदल चलने का अधिकार संविधान के भाग-3 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ये अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 (1) (डी) के तहत मिलने वाले 'देश में कहीं भी आने-जाने के अधिकार' का एक अहम हिस्सा है।

अदालत ने इसे आर्टिकल 19 (1) (ए), 19(1) (बी), 19(1) (सी) और सबसे अहम आर्टिकल 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के साथ जोड़कर देखा है।

बेंच ने अपने आदेश में लिखा, 'पैदल चलने के इस बुनियादी अधिकार के दायरे में निर्धारित फुटपाथों का अधिकार भी शामिल है। ये अधिकार प्राथमिक है और इसे सड़कों पर चलने वाले मोटर वाहनों के मुकाबले तरजीह दी जाएगी।'

अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी

अदालत ने ये भी कहा कि अगर किसी नागरिक को मौलिक अधिकार मिला है, तो उसे पूरा करना प्रशासन का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अगर कहीं सड़क मौजूद है, तो ये प्रशासन का कर्तव्य है कि वो वहां पैदल चलने वालों के लिए एक अच्छा और साफ-सुथरा फुटपाथ भी बनाकर दे।'

अदालत के मुताबिक, इस जिम्मेदारी को निभाने वाले 'ड्यूटी बियरर्स' में शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगरपालिकाएं और यहां तक कि ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। इन सभी संस्थाओं को अपने-अपने इलाकों में फुटपाथों का निर्माण करना होगा, उनका रखरखाव करना होगा और उन्हें सुरक्षित रखना होगा।

अगर किसी जगह फुटपाथ नहीं होने या खराब होने के कारण नागरिकों के इस अधिकार का उल्लंघन होता है, तो लोग सीधे कोर्ट जा सकते हैं। नागरिक इन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक उपाय अपनाकर हर्जाना और बहाली की मांग कर सकते हैं। ये कानूनी अधिकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मिलने वाले फायदों से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र होगा।

कॉलेजियम के फैसलों की न्यायिक समीक्षा नहीं

ब्लिट्ज ब्यूरो

आरटीआई के दायरे से भी बाहर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विगत दिवस एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के चयन की प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आती। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कॉलेजियम की चयन प्रक्रिया सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी नहीं आती और इस पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की अवकाशकालीन पीठ ने हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी अरविंद मल्होत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। मल्होत्रा ने आरोप लगाया था कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के बावजूद उनके नाम पर उचित ढंग से विचार नहीं किया और हाईकोर्ट के जज पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को नजरअंदाज कर दिया।

कॉलेजियम के फैसलों में हम दखल नहीं देंगे

सुनवाई के दौरान पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि हम पैंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहते। कॉलेजियम के फैसलों में हम दखल नहीं देंगे। अदालत ने कहा कि जजों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह कॉलेजियम के सब्जेक्टिव सैटिस्फेक्शन पर आधारित होती है और इस प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

मल्होत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह ने दलील दी कि 6 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस द्वारा दो वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों, जिनमें अरविंद मल्होत्रा भी शामिल थे, की उम्मीदवारी पर एकतरफा फैसला लेने को गलत ठहराया था। उस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि चयन का निर्णय कॉलेजियम सामूहिक रूप से करेगा, न कि कोई एक व्यक्ति। इसके बावजूद कॉलेजियम ने उनकी उम्मीदवारी और उनके जवाबों पर विचार नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जूनियर वकीलों के लिए बनेगा खास फंड

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जूनियर वकीलों के हक में एक बेहद मानवीय फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से कई होनहार और युवा वकील वकालत छोड़ रहे हैं। इस 'ब्रेन ड्रेन' को रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए 'यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंस फंड' बनाया जाना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश महिला वकीलों के एक समूह की ओर से दायर याचिका पर दिया गया है। याचिका में युवा वकीलों के शुरुआती संघर्ष, पैसों की किल्लत और महिला अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित माहौल का मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट ने साफ कहा कि आर्थिक संकट किसी एक जेंडर का नहीं है।

पहली पीढ़ी के वकीलों को शुरुआत में न तो कोई ऑफिस मिलता है, न लाइब्रेरी और न ही मुवक्किल। वे सीनियर्स या स्थानीय बार एसोसिएशनों से मिलने वाले बेहद कम वजीफे पर निर्भर रहते हैं। यह राशि बुनियादी खर्चों के लिए भी पूरी नहीं पड़ती।

महिला वकीलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान

शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला वकीलों को दिन का एक बड़ा हिस्सा कोर्ट परिसर में ही बिताना पड़ता है। इसलिए उनके आराम, गोपनीयता, सुरक्षा और काम के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना बेहद जरूरी है।

बिजनेस बन गया है आरटीआई : सुप्रीम कोर्ट

राजेश दुबे

नई दिल्ली। सूचना का अधिकार कानून के जरिए सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप के आरोपों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। इसके साथ ही कोर्ट ने दो आरटीआई कार्यकर्ताओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरटीआई एक्टिविज्म अब एक बिजनेस बन गया है। इसकी आड़ में सरकारी कर्मचारियों को अपना काम करने से रोका जा रहा है।

ये मामला पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला से जुड़ा है। यहां रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश बहल और राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोनों ने दावा किया था कि वे एक सरकारी सड़क निर्माण परियोजना में कथित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहे थे। हालांकि उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।

जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कई कड़ी टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि आरटीआई एक्टिविज्म एक ऐसे व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन से रोक रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सीधे कई सवाल भी किए।

RIGHT TO
INFORMATION

दो एक्टिविस्टों को नहीं मिली बेल

अदालत ने पूछा, आप लोगों को काम नहीं करने देते। सड़क निर्माण कार्य की प्रगति पर नजर रखने वाले आप कौन होते हैं? क्या आप वहां इंजीनियर हैं? क्या आप कोई उच्च अधिकारी हैं? या फिर जनता के अधिकृत प्रतिनिधि हैं? अदालत की इन टिप्पणियों से संकेत मिला कि न्यायालय सरकारी परियोजनाओं में अनधिकृत हस्तक्षेप को गंभीरता से देख रहा है।

आरोप है कि दोनों कार्यकर्ताओं ने सरकारी सड़क निर्माण कार्य में बाधा डाली। उनके खिलाफ पर्यवेक्षक अधिकारी पर हमला करने, मजदूरों के साथ मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों की हरकतें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत अपराध हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस तरह की गतिविधियों को सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप का माध्यम बताते हुए इसे येलो जर्नलिज्म यानी पीत पत्रकारिता जैसा व्यवहार करार दिया। अदालत का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति वैधानिक अधिकारों की आड़ में सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

आरटीआई कार्यकर्ता रमेश बहल और राजीव कुमार पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन 14 मई को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दोनों ने राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

रोहित शर्मा समेत 65 हस्तियों को पद्म अवॉर्ड

अलका याग्निक ने पद्म भूषण लेने से पहले पीएम मोदी के पैर छुए

डेरा सचखंड के प्रमुख संत निरंजन दास को पद्मश्री सम्मान

जालंधर। डेरा सचखंड, बल्लां के प्रमुख संत निरंजन दास को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। संत निरंजन दास को समाज सेवा, मानवता और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उनके लंबे योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। इस सम्मान के बाद डेरा सचखंड, बल्लां से जुड़े लाखों श्रद्धालुओं और पंजाबवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

संत निरंजन दास ने डेरा सचखंड, बल्लां के माध्यम से समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान, शिक्षा, सेवा और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है।

नगालैंड के गुरु संग्युसंग पोंगनेर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

ब्लिट्ज विशेष

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म अवॉर्ड के दूसरे फेज में 65 हस्तियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री दिए गए।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केटी थॉमस को जनसेवा, सीनियर मलयालम जर्नलिस्ट पी नारायणन को साहित्य के लिए पद्म विभूषण दिया गया। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। अवॉर्ड लेने उनकी पत्नी रूपी सोरेन पहुंची।

सिंगर अलका याग्निक ने अवॉर्ड लेने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छुए। क्रिकेटर रोहित शर्मा, एक्टर आर माधवन को पद्मश्री से नवाजा गया। पुरस्कार पाने वालों में एक्टर ममूटी और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज भी शामिल रहे।

2026 के पद्म पुस्कारों के लिए कुल 131 लोगों को चुना गया था। इससे पहले 25 मई को पहले चरण में भारतीय वुमन क्रिकेट टीम कैप्टन हरमनप्रीत कौर, एक्टर धर्मेंद्र समेत 66 हस्तियों पद्म अवॉर्ड दिए गए थे।

बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण से नवाजा गया। वे 60 साल की हैं और 4 दशक तक सिंगिंग में एक्टिव रही हैं। अवॉर्ड लेने से पहले वे पीएम मोदी के पास गई और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

नगालैंड के गुरु संग्युसंग पोंगनेर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे छह दशकों से 'आओ नागा' लोक कला को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। पोंगनेर पारंपरिक पोशाक पहनकर पुरस्कार लेने पहुंचे।

राष्ट्रपति ने प्रह्लाद नाटक की परंपरा को संरक्षित और प्रोत्साहित करने वाले सीमांचल पात्र को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया।

भारतीय शास्त्रीय गायक मंगला कपूर को पद्मश्री से सम्मानित किया। ग्वालियर घराने से ट्रेनिंग लेने वालीं मंगला ने प्रदर्शन, शिक्षण और शोध से भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मैडी के नाम से मशहूर एक्टर आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। माधवन ने 1200 से ज्यादा टीवी शो, 75 फिल्में की हैं। वे फार्मिंग में भी एक्टिवली काम कर रहे हैं।

मलयाली फिल्मों के एक्टर ममूटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ममूटी 50 साल से फिल्मों में एक्टिव हैं। कई भाषाओं में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। वे चैरिटी का काम भी करते हैं।

रूस की प्रोफेसर को पद्मश्री

इंडोलॉजी की मशहूर प्रोफेसर और भाषाविद् डॉ. ल्यूडमिला खोखलोवा को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्होंने रूसी, अंग्रेजी और हिंदी में 6 किताबें और 92 रिसर्च पेपर लिखे हैं। उन्होंने ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान पर अहम रिसर्च की है, जिसमें सिख धर्म की उत्पत्ति और विकास पर किया गया अध्ययन भी शामिल है।

समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मानित लोग- झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी रूपी सोरेन को अवॉर्ड देने राष्ट्रपति डाइस से उतरकर खुद उनके पास गईं ।

छत्तीसगढ़ की समाज सुधारक बुधरी ताती को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 4 दशक से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा, आत्मनिर्भरता और उन्हें सशक्त बनाने के काम कर रही हैं।

खेल के क्षेत्र में सम्मानित हुए खिलाड़ी- टेनिस प्लेयर और कोच डॉ. विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विजय ने 16 एटीपी खिताब (एशियाई रिकॉर्ड) जीते हैं। विजय 14 साल तक एशियन रैंकिंग में नंबर 1 रहे और बाद में ब्रॉडकास्टर बने।

भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। रोहित के नाम वनडे में तीन दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड है। 2024 का टी-20 वर्ल्डकप भी भारतीय टीम ने रोहित की कप्तानी में जीता।

महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और मौजूदा गोलकीपर सविता पूनिया को पद्मश्री दिया गया। इन्हें 'द ग्रेट वॉल' कहते हैं। लगातार तीन बार एफआईएच 'गोलकीपर ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं।

असाधारण सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं पद्म पुरस्कार: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह-II में भाग लिया, जहां पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार विविध क्षेत्रों में की गई असाधारण सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया कि प्रत्येक पुरस्कार विजेता समाज के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता के सर्वोत्तम स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। पुरस्कार विजेताओं की जीवन यात्रा अनगिनत नागरिकों को प्रेरित करती है और सभी को कड़ी मेहनत और सेवा के महत्व की याद दिलाती है।

रूसी कोच व्लादिमीर को मरणोपरांत पद्मश्री

राष्ट्रपति ने खेल के क्षेत्र में व्लादिमीर मेस्तविरीशिवली (मरणोपरांत) को पद्मश्री से सम्मानित किया। वे फ्रीस्टाइल रेसलिंग के दिग्गज कोच थे और उन्होंने ग्लोबल रेसलिंग कम्युनिटी पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने भारतीय रेसलिंग टीम के कोच के तौर पर काम किया। उन्होंने सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया जैसे ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को गाइड किया और भारत को रेसलिंग में ग्लोबल पावरहाउस बनाने में मदद की।

एक्टर सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री

अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अवॉर्ड उनके भाई अरविंद ने लिया। चार दशकों के करियर में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए मशहूर सतीश शाह ने कई फिल्मों और यादगार टीवी शो में काम किया।

सीमांचल मिश्रा को पद्मश्री

सीमांचल पात्रा को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानि किया गया। इन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और ओम बिरला के पैर छुए। उम्र ज्यादा होने के कारण इनके हाथ कांप रहे थे।

पीएम मोदी से मिले दुनिया के शीर्ष सुरक्षा प्रमुख

सुरक्षित, संरक्षित और समावेशी विश्व के निर्माण में भारत सदैव योगदान देगा

वैश्विक चुनौतियों पर हुई रणनीतिक चर्चा

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात के दौरान समकालीन वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में इस समूह के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग को और गहरा करने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन

पीएम मोदी ने रेखांकित किया कि भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहेगी। उन्होंने वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि भारत एक अधिक सुरक्षित, संरक्षित और समावेशी विश्व के निर्माण में योगदान देगा। इस संबंध में पीएम मोदी ने एक्स पर भी पोस्ट किया कि ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मिलकर उन्हें प्रसन्नता हुई।

विदेश मंत्रालय ने भी जारी किया बयान

16वीं दो दिवसीय बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। विदेश मंत्रालय (एमईए) की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बैठक में गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। इनमें ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सप्लाई चेन (आपूर्ति व्यवस्था) की सुरक्षा, आतंकवादी संगठनों की ओर से इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकें, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली अस्थिरता जैसे मुद्दे शामिल थे।

आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की बैठक

एमईए के अनुसार, शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने ब्रिक्स के 'आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह' और 'सूचना एवं संचार तकनीकों के सुरक्षित इस्तेमाल' से जुड़े कार्य समूहों की गतिविधियों और नतीजों की भी समीक्षा की। आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की बैठक इस साल 21-22 मई को हुई थी जबकि सूचना और संचार तकनीक से जुड़ी बैठक इसी महीने आयोजित की गई ।

ब्रिक्स देशों ने सहयोग बढ़ाने का किया समर्थन

बयान में कहा गया कि नेताओं ने ब्रक्सि देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का समर्थन किया। खासतौर पर सदस्य देशों की क्षमताओं को मजबूत करने, जानकारी साझा करने और आतंकवाद और साइबर खतरों से मिलकर निपटने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया।

प्रतिनिधिमंडलों ने भारत की अध्यक्षता का किया समर्थन

उन्होंने आतंकवाद के हर रूप और हर तरीके के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

साथ ही, आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीकों के इस्तेमाल को रोकने की जरूरत पर भी सहमति जताई। बैठक में शामिल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का पूरा समर्थन किया।

डोभाल व वांग यी की मुलाकात में भारत-चीन संबंध स्थिर बनाने पर जोर

SECURITY ADV

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की। इस बातचीत में भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और संतुलित संबंधों पर फोकस किया गया। वांग यी ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए थे। बैठक के दौरान डोभाल और वांग यी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास की स्थिति की भी समीक्षा की।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा ?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की और संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में धीरे-धीरे प्रगति हो रही है।

डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने और एक-दूसरे को बेहतर समझने में मदद करते हैं। जायसवाल ने कहा कि डोभाल और वांग यी के बीच हुई बातचीत रचनात्मक रही और भविष्य को ध्यान में रखकर की गई।

बैठक में भारतीय पक्ष की ओर से कौन-कौन शामिल हुए ?

भारतीय पक्ष की ओर से इस बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, भारत के चीन में राजदूत विक्रम दुरईस्वामी और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

ब्रिक्स समूह की मेजबानी कर रहा भारत

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब भारत ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है और उसने राष्ट्रीय राजधानी में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की मेजबानी की। यह चर्चा इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली और बीजिंग दोनों ही पिछले कुछ वर्षों के तनाव के बाद अपने संबंधों को स्थिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सीमा पर झड़प के बाद आ गया था तनाव

साल 2020 में सीमा पर हुई झड़प के बाद भारत और चीन के संबंधों में काफी तनाव आ गया था। इसके बाद कई वर्षों तक सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर तनाव बना रहा। हालांकि, 2024 में दोनों देशों ने तनाव कम करने की दिशा में कदम बढ़ाए।

भारत-रूस ने ब्रिक्स ढांचे के तहत जारी सहयोग पर चर्चा की

डोभाल व रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव शोइगु की मुलाकात

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने विगत दिवस रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत जारी सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत-रूस के द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की।

डोभाल और शोइगु की यह मुलाकात ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) की बैठक के दौरान हुई।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा ?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। जायसवाल ने बताया कि दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत सहयोग जारी रखने पर चर्चा की, जिसमें रूस की ओर से दिए गए कुछ प्रस्ताव भी शामिल थे। उन्होंने भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की भी समीक्षा की।

ब्रिक्स समूह में कौन-कौन देश शामिल हैं ?

ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता वर्तमान में भारत के पास है, इसलिए नई दिल्ली ने इस सम्मेलन की मेजबानी की। ब्रिक्स में शुरुआत में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। वर्ष 2024 में इसका विस्तार किया गया और इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान तथा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को शामिल किया गया। इसके बाद वर्ष 2025 में इंडोनेशिया भी इस समूह का सदस्य बना।

विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत, सरकार ने खत्म किया कैपिटल गेन टैक्स

अब थमेगी रुपये की गिरावट?

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को सरकारी सिक्योरिटीज की बिक्री या उनसे मिलने वाले ब्याज से होने वाली कमाई पर कैपिटल गेन टैक्स खत्म कर दिया है। इसका मकसद ज्यादा विदेशी पूंजी आकर्षित करना और रुपये की गिरावट को थामना है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लिया गया है क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है। इसका मकसद ज्यादा विदेशी पूंजी आकर्षित करना और रुपये की गिरावट को थामना है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में बिकवाली से इस साल रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 5 प्रतिशत कमजोर हुआ है।

राष्ट्रपति द्वारा जारी इनकम-टैक्स (संशोधन) अध्यादेश, 2026 में इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 की अनुसूची चार में संशोधन किया गया है। इसके तहत सरकारी बॉन्ड में निवेश से जुड़ी टैक्स-फ्री इनकम की नई कैटेगरी जोड़ी गई हैं। इन बदलावों के तहत सरकारी सिक्योरिटीज से मिलने वाले ब्याज और उनकी बिक्री, एक्सचेंज या ट्रांसफर से होने वाले कैपिटल गेन पर कुछ खास एंटिटीज को टैक्स में छूट मिलेगी। इसमें कई तरह की शर्तें जोड़ी गई हैं जिनमें टैक्स अधिकारियों को तय जानकारी देना जरूरी होगा।

कब से लागू होगी छूट?

सरकार के बयान के मुताबिक, यह छूट 1 अप्रैल, 2026 से लागू मानी जाएगी। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक विदेशी निवेशकों को 12 महीने से ज्यादा समय तक रखे गए लिस्टेड शेयरों और बॉन्ड पर 12.5 प्रतिशत लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। इसके अलावा सरकारी बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज पर 20 प्रतिशत विदहोल्डिंग टैक्स लगता है।

जानकारों का कहना है कि इस छूट से विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाला रिटर्न बेहतर हो सकता है और भारतीय सरकारी सिक्योरिटीज में ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है। इससे निवेशकों का दायरा बढ़ाने और बाहरी दबावों से निपटने में मदद मिलेगी।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली

सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया जब इस साल अब तक विदेशी निवेशकों (एफपीआइज) ने भारतीय बाजार से कुल 2.47 लाख करोड़ रुपये निकाले हैं। यह 2025 में निकाले गए 1.04 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। इसे रोकने के लिए एक्सपर्ट्स लंबे समय से एलटीसीजी और विदहोल्डिंग टैक्स को कम करने की मांग कर रहे थे।

कैपिटल गेन टैक्स क्या है?

शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या प्रॉपर्टी जैसे एसेट्स बेचने पर होने वाले प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। अगर आप शेयर और म्यूचुअल फंड को 12 महीने से अधिक समय तक अपने पास रखने के बाद बेचते हैं, तो उस पर होने वाले प्रॉफिट पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसी तरह अगर आप किसी प्रॉपर्टी को 24 महीने से अधिक समय तक अपने पास रखने के बाद बेचते हैं तो उस पर भी यह टैक्स लगता है।

इक्विटी पर एलटीसीजी टैक्स दर 12.5% है और इसमें ₹1.25 लाख तक का मुनाफा टैक्स-फ्री होता है। प्रॉपर्टी के मामले में इंडेक्सेशन (मुद्रास्फीति/महंगाई के प्रभाव को कम करना) का लाभ भी मिलता है। अगर आप जल्दी-जल्दी शेयर बेचते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसी दर 20 फीसदी है।

क्रेड एप के फाउंडर कुणाल शाह वॉट्सएप के नए ग्लोबल हेड

नई दिल्ली। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा ने क्रेड एप के फाउंडर कुणाल शाह को वॉट्सएप का नया ग्लोबल हेड बनाया है। वे विल कैथकार्ट की जगह लेंगे, जो 7 साल से वॉट्सएप की कमान संभाल रहे थे। कैथकार्ट अब मेटा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे।

यह जानकारी मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने पोस्ट कर दी है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने यह फैसला उस डील के तहत लिया है, जिसमें मेटा यूपीआई और बिल पेमेंट एप क्रेड में करीब 8,550 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके बदले मेटा को क्रेड में 20% की हिस्सेदारी मिलेगी। इसके बाद क्रेड कंपनी की कुल वैल्यूएशन बढ़कर ₹43,239 करोड़ हो जाएगी। मेटा के मुताबिक, कुणाल शाह के बॉस बनने के बाद वॉट्सएप का पूरा ध्यान दो बड़ी चीजों पर होगा। कंपनी अब वॉट्सएप के जरिए ज्यादा पैसे कमाने की तैयारी में है। इसके लिए एप में विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं और कुछ खास फीचर्स के लिए मंथली फीस यानी सब्सक्रिप्शन भी लाया जा सकता है। वॉट्सएप के अंदर अलग-अलग तरह के 'एआई एजेंट्स' (यानी कंप्यूटर प्रोग्राम या चैटबॉट्स) जोड़े जाएंगे।

जियो लाएगी देश का सबसे बड़ा आईपीओ

ब्लिट्ज ब्यूरो

मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं सालाना एजीएम बैठक में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शेयरहोल्डर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कंपनी यूरोप और अफ्रीका के मार्केट में एंट्री कर रही है। वहीं, कंपनी जियो का आईपीओ भी लाने जा रही है।

अंबानी ने बताया कि इसके लिए सेबी के पास ड्राफ्ट दस्तावेज (डीआरएचपी) जमा कर दिए गए हैं। कंपनी 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी और आईपीओ के जरिए करीब 4 बिलियन डॉलर यानी ₹37,700 करोड़ जुटाने की योजना है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। हालांकि शेयरों की कीमत क्या रहेगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। रिलायंस फाउंडेशन मुंबई में एक बड़ी अर्बन ग्रीन सेंक्चुरी का प्रोजेक्ट 'कोस्टल गार्डन' के नाम से लाएगा। मुंबई में ही करीब 410 एकड़ में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के प्रोजेक्ट को भी महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। वनतारा यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी की जा रही है।

रिलायंस एजीएम में 5 बड़े कदमों का एलान

- **जियो का आईपीओ आएगा, सेबी में पेपर्स दाखिल:** जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड ने आईपीओ को मंजूरी दे दी है। आईपीओ के जरिए 27 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे।
- **2030 तक सभी ग्राहकों को 5जी पर लाने का टारगेट:** जियो पूरे देश में 5जी नेटवर्क का विस्तार करेगा। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक सभी ग्राहकों को 5जी सेवा से जोड़ना है। 6जी तकनीक पर भी काम किया जाएगा।
- **जियो भारतीय भाषाओं में एआई बनाएगा:** जियो भारतीय भाषाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित कर रहा है। एआई को आम लोगों के लिए आसान और सस्ता बनाया जाएगा।
- **घर-घर हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा:** जियो एयरफाइबर और ब्रॉडबैंड सेवाओं का तेजी से विस्तार करेगा। कंपनी का फोकस ज्यादा से ज्यादा घरों तक तेज इंटरनेट पहुंचाने पर है।
- **जियो की तकनीक विदेशों में जाएगी:** जियो अपनी 5जी, एआई और डिजिटल तकनीक दूसरे देशों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।

एनजीओ पर कसा शिकंजा, विदेशी चंदे के नियमों में बड़े बदलाव

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों की ओर से विदेशी अंशदान प्राप्त करने और उपयोग करने से जुड़े विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत कई अपराधों के लिए जुर्माने में संशोधन किया है। सरकार ने विगत दिवस एक गजट अधिसूचना के माध्यम से इन आदेशों को अधिसूचित किया। इन संशोधनों का उद्देश्य भारत में एनजीओ द्वारा विदेशी धन के उपयोग में जवाबदेही बढ़ाना है। नियमों को सख्त करके पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

प्रशासनिक खर्चों के लिए प्राप्त अंशदान के 20 फीसदी से अधिक विदेशी अंशदान का उपयोग करने पर एक लाख रुपये या सीमा से अधिक खर्च की गई राशि का 5 फीसदी, जो भी अधिक हो, का जुर्माना लगेगा। सट्टेबाजी गतिविधियों में विदेशी अंशदान का उपयोग करने पर एक लाख रुपये या निवेश की गई राशि का 30 फीसदी, जो भी अधिक हो, का जुर्माना लगेगा। इसके अतिरिक्त, अर्जित लाभ का 100 फीसदी वसूल किया जाएगा। यदि विदेशी अंशदान का उपयोग प्राप्त उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया, तो एक लाख रुपये या उपयोग की गई राशि का 30 फीसदी, जो भी अधिक हो, का जुर्माना लगाया जाएगा।

2035 तक 10 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य: अडाणी

एजीएम में शेयर धारकों को दी भावी योजनाओं की जानकारी

नई दिल्ली। ऊर्जा क्षेत्र में अपना दबदबा और मजबूत करते हुए अडाणी समूह ने न्यूक्लियर एनर्जी (परमाणु ऊर्जा) सेक्टर में कदम रखने का बड़ा एलान किया है। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग (एजीएम) में चेयरमैन गौतम अडाणी ने बताया कि समूह 2035 तक 10 गीगावाट (जीडब्ल्यू) न्यूक्लियर पावर क्षमता विकसित करेगा। इस कदम से समूह अब थर्मल, रिन्यूएबल, हाइड्रो और गैस के बाद परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा।

अडाणी ने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए बताया कि परमाणु ऊर्जा उद्यम, अडाणी एटॉमिक एनर्जी के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। यह बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता और बिजली की बढ़ती मांग के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। समूह का लक्ष्य स्वच्छ और चौबीसों घंटे बिजली की बढ़ती राष्ट्रीय मांग को पूरा करना है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब समूह ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में निवेश बढ़ा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा अब राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उभरी है। अरबपति उद्योगपति ने कहा कि समूह का एकीकृत बुनियादी ढांचा मॉडल विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह बाहरी निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा लचीलापन को मजबूत करेगा। समूह खनन और ईन्धन आपूर्ति से लेकर बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण तक निवेश बढ़ा रहा है।

समूह ऊर्जा क्षेत्र में कैसे कर रहा विस्तार

अडाणी पावर भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय कार्यक्रम चला रही है। इसमें दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश शामिल है। इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 45 गीगावाट उत्पादन क्षमता तक पहुंचना है। अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का पारेषण आदेश पुस्तिका 72,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसमें खावड़ा-दक्षिण ओलपाड उच्च-वोल्टेज प्रत्यक्ष धारा पारेषण लाइन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बेहद करीब

ट्रंप से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उठाया नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा

ट्रंप बोले, अगर भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका उसके साथ

ब्लिट्ज विशेष

एवियन-लेस-बेन्स। भारत और अमेरिका एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब पहुंच गए हैं। फ्रांस के एवियन में जी7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद ट्रंप ने कहा, दोनों देश समझौते के अंतिम चरण में हैं।

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और राजनयिक पहलों के जरिए स्थिरता लाने के लिए ट्रंप के प्रयासों और नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में लंबे समय तक चले संघर्ष के कारण गंभीर नुकसान हुआ।

होर्मुज खुला रहना जरूरी

पीएम मोदी ने कहा, होर्मुज का खुला रहना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। भारत समुद्री मार्गों में आवाजाही की स्वतंत्रता का समर्थन करता रहा है।

नाविकों की सुरक्षा

प्रधानमंत्री ने ट्रंप के समक्ष भारतीय पोत, नाविकों की सुरक्षा का मसला भी उठाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका-ईरान के बीच समझौते में नाविकों की सुरक्षा के प्रावधान शामिल होंगे। मोदी ने कहा, लाखों भारतीय समुद्री व्यापार क्षेत्र में काम करते हैं। उनकी सुरक्षा अहम है।

ट्रंप ने कहा कि अगर भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। एच-1बी वीजा मुद्दे के कारण भारतीय पेशेवरों को परेशानी के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि रोजगार के मामले में भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं।

भारत की बड़ी भूमिका

ट्रंप ने कहा, पश्चिम एशिया समेत कई अहम मुद्दों में भारत की बड़ी भूमिका है। उन्होंने मोदी से बेहतर रिश्तों की बात दोहराते हुए कहा, जब तक वे व्हाइट हाउस में हैं, भारत का अमेरिका में अच्छा दोस्त मौजूद है।

FRANCE
ÉVIAN
2026
G7

इन मुद्दों पर चर्चा हुई

- मोदी-ट्रंप ने टैरिफ और व्यापारिक असंतुलन से जुड़ा तनाव दूर करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
- तकनीक साझेदारीः दोनों नेताओं में एआई, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई।
- हिंद-प्रशांत में स्थिरताः हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने, रणनीतिक संबंधों को नई ऊर्जा देने पर सहमति जताई गई।

स्लोवाकिया के साथ रक्षा समेत 11 समझौते

पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने की स्लोवाकिया की यात्रा

ब्लिट्ज ब्यूरो

ब्रातिस्लावा। भारत और स्लोवाकिया विगत दिवस अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत हुए। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। दोनों देशों के बीच यह सहमति पीएम नरेन्द्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच बातचीत के बाद बनी।

दोनों देशों ने माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिफेंस जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों को अंतिम रूप दिया। मोदी यूरोप की अपनी एक हफ्ते की यात्रा के दौरान ब्रातिस्लावा आए थे। किसी भारतीय पीएम की 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद यह पहली यात्रा थी।

दोनों नेता भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते को जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमत हुए। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

पीएम ने बयान में कहा, 'हमने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है। यह हमारी साझा मान्यताओं, साझा प्राथमिकताओं और

भविष्य का प्रतीक है।' भारत और स्लोवाकिया के बीच रक्षा सहयोग दोनों पक्षों के बीच प्रगाढ़ होते आपसी भरोसे और रणनीतिक तालमेल का सबूत है।

पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत

दो दिनों के दौरे पर स्लोवाकिया पहुंचे पीएम का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी।

पीएम ने कार्यक्रम की एक सुखद झलकी शेयर की। यह 'महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट' का अंश था। 44 सेकेंड की विडियो क्लिप में प्रोजेक्ट के सदस्य 'शंभू-शंभू' का जाप करते देखे जा सकते है। पीएम का स्वागत स्लोवाकिया के पारंपरिक तरीके रोटी नमक से किया गया।

ऊर्जा-माइग्रेशन पर साथ

मोदी और फिको ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और मजबूती को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। इसके लिए परमाणु ऊर्जा और जियोथर्मल पावर सहित ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। दोनों ने स्किल्ड प्रोफेशनल्स की सुरक्षित और कानूनी आवाजाही का समर्थन किया। आवाजाही आसान बनाने के लिए समझौते का स्वागत किया।

कमजोर देशों को वित्तीय मदद से युद्ध के बोझ से बचाने की जरूरत : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी 7 शिखर सम्मेलन में कहा कि पश्चिम एशिया के संकट का ईन्धन, उर्वरक और खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ने वाला प्रभाव वैश्विक दक्षिण के देशों पर लंबे समय तक असर डालेगा।

उन्होंने कहा कि सबसे कमजोर देशों पर भू-राजनीतिक संकटों का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए वित्तीय मदद जैसी कोई व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। सभी देश सहयोग का अपना वादा पूरो करने के लिए आगे आएं।

यूक्रेन युद्ध को ट्रंप के एजेंडे में लाने की कोशिश करते दिखे सहयोगी देश

पेरिस। जी-7 में हिस्सा लेने वाले अमेरिका के सहयोगी देश यूक्रेन में चार साल से अधिक समय से जारी युद्ध को ट्रंप के एजेंडे में टॉप पर लाने की कोशिशें करते दिखे। ईरान युद्ध ने यूक्रेन-रूस वॉर से ट्रंप का ध्यान हटा दिया था। मेजबान देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि वह ट्रंप को रूस पर शांति समझौता का दबाव बढ़ाने के लिए मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, जो इस प्रयास में मदद कर रहे हैं।

ईरान में निवेश नहीं कर रहे : ट्रंप

ट्रंप ने फ्रांस में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात में कहा, हम ईरान में कोई निवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य में कभी भी वहां जाकर निवेश करने का अधिकार है।

ट्रंप ने इस्राइली पीएम नेतन्याहू को लेबनान पर ज्यादा जिम्मेदारी दिखाने की सलाह दी है। कहा, मैं न होता, तो इस्राइल नहीं होता। किसी दूसरे राष्ट्रपति ने इस्राइल के लिए उतना नहीं किया, जितना मैंने किया है।

नवाचार हमारे डीएनए में, पूरी दुनिया को समाधान देने वाला देश बना भारत

फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ पीएम ने भारत इनोवेट्स का किया उद्घाटन

ब्लिट्ज ब्यूरो

नीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाचार भारत के डीएनए में है। गणित हो या खगोल विज्ञान, चिकित्सा हो या योग, भारत हजारों वर्षों से अपने ज्ञान और नवाचार से दुनिया को नई दिशा देता रहा है। एक दशक पहले दुनिया भारत को प्रौद्योगिकी अपनाने वाले देश के तौर पर देखती थी, अब यह प्रौद्योगिकी प्रदाता के तौर पर उभर रहा है।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ नीस शहर में भारत इनीवेट्स-2026 के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, भारत अब समाधानों का उपभोक्ता नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया को समाधान देने वाला बन चुका है। समाधान का फायदा मानवता के बड़े हिस्से को मिलता है।

तीन दिवसीय यह आयोजन भारत और फ्रांस का साझा कार्यक्रम है, जो 16 जून तक चला। राष्ट्रपति मैक्रों ने नवाचार समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना की। वहीं, एंथ्रोपिक के एडवांस्ड एआई मॉडल्स तक विदेशियों की पहुंच रोकने को लेकर अमेरिका पर निशाना भी साधा। कहा, कुछ देश एआई का इस्तेमाल सीमित करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए मैक्रों ने कहा, भारत-फ्रांस खुले, बहुभाषी एवं सहयोगी एआई मॉडल के पक्षधर हैं।

पीएम मोदी ने कहा, भारत-फ्रांस का रिश्ता सिर्फ व्यापार या रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है। यह भरोसे, साझा सोच और साझा लक्ष्यों पर आधारित है। रिश्ते में नवाचार है, प्रेरणा है, साझे मूल्य व साझा दृष्टिकोण भी है। मोदी ने कहा, फरवरी में भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष की शुरुआत हुई थी। उसके साथ भारत इनोवेट्स की भी शुरुआत हो रही है। उन्होंने आयोजन को भारतीय प्रतिभा व यूरोपीय निवेश को जोड़ने का मंच बताया। कहा, भारत इनोवेट्स दुनिया के लिए निमंत्रण है कि वे भारत के साथ वैश्विक नवाचार का अंगला अध्याय लिखें। भारत के युवा नवोन्मेषक ऐसे समाधान खोज रहे हैं, जिनसे पूरी मानवता को लाभ हो सकता है।

बढ़ रही भारत की धाक

दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है, लेकिन हर चुनौती नए मौके भी लेकर आती है। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष तकनीक जैसी नई तकनीकें आने वाले समय में दुनिया का भविष्य तय करेंगी।

भारत हर साल यूरोप व अमेरिका जितने इंजीनियर अकेले तैयार कर रहा। अब सवाल यह नहीं है कि भारत नवाचार करता है या नहीं। सवाल यह है कि दुनिया में भारत किसके साथ मिलकर नवाचर करेगा।

पीएम मोदी ने कहा, आज इस कार्यक्रम में कई वेंचर कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्री लीडर्स शामिल हैं। मैं भारत से आए युवा इनोवेटर्स की तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने पुराने रास्ते पर चलने के बजाय, एक नया रास्ता चुना है। उन्होंने एक नई राह बनाई है। यहां आपको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे होंगे, लेकिन भारत में ऐसे दो लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स का एक बड़ा पूल है।

भारत की सुधार एक्सप्रेस चलती रहेगी

पीएम मोदी ने उच्च-तकनीक, रक्षा व नवाचार जैसे अहम क्षेत्रों में सरकार के सुधारों का जिक्र करने के साथ कहा, भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, चलती रहेगी।

कार्यक्रम में उद्यमियों व निवेशकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारत-फ्रांस की पहल से भारतीय स्टार्टअप्स, युवा उद्यमियों व नए विचारों को दुनिया के बड़े निवेशकों व विशेषज्ञों तक पहुंचने का मौका मिलेगा।

नई सोच के साथ आज भारत में चल रही स्टार्टअप क्रांतिः भारत

इनोवेट्स के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत बदलाव के एक बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में स्टार्टअप क्रांति चल रही है। इस क्रांति में, नई सोच के साथ भारत के युवा मानवता के हित में समस्याओं का समाधान ढूंढ़ रहे हैं। हमारे युवाओं के विश्व-स्तरीय समाधानों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का माध्यम 'भारत इनोवेट्स' हैं'।

bharat
INNOVATES
NICE, FRANCE | 14-16 JUNE, 2026

टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत बड़े पैमाने पर और तेजी से नवाचार करता है, भारत टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचार करता है और भारत पूरी दुनिया के लिए नवाचार करता है। हर तकनीकी क्रांति मानवता को एक नया अवसर देती है और हर अवसर एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आता है। आज दुनिया ऐसी तकनीकों की ओर देख रही है जो भरोसेमंद, समावेशी और मानव-केंद्रित हों और जिनका मकसद वैश्विक भलाई हो। ऐसे समय में, भारत की प्राथमिकता मानवता के लिए तकनीक और मानव-केंद्रित इनोवेशन है'।

'हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं'

इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में जी7 समिट के दौरान एक-दूसरे से हंसी-मज़ाक भरी बातचीत की। वायरल हो रहे 'मेलोडी' ट्रेंड का ज़िक्र करते हुए मेलोनी ने मज़ाक में कहा कि वे 'इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल' हैं।

एवियन-लेस-बेन्स में जी7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत ने लोगों का ध्यान खींचा।

'आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा!' मेलोनी को पीएम मोदी से यह कहते हुए सुना गया। 'हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं', मेलोनी ने पीएम मोदी से कहा।

जब दुनिया भर के नेता पारंपरिक ग्रुप फोटो के लिए इकट्ठा हुए, तो दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक-दूसरे का अभिवादन किया।

मोदी-मैक्रों द्विपक्षीय वार्ता में एआई व्यापार और बुनियादी ढांचे पर चर्चा

नीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एआई, स्टार्टअप, व्यापार, बुनियादी ढांचे, मोबिलिटी और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने द्विपक्षीय वार्ता की जानकारी देते हुए बताया, दोनों नेताओं ने अहम अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

प्रधानमंत्री 7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस पहुंचे थे और उन्होंने मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। वार्ता में भारत की ओर से पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं, राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन-नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत-फ्रांस ने साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की, जिसमें उन्होंने भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की।

'सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई छोड़ो, ट्रेड स्किल्स सीखो'

देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की यूथ को सलाह

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि दुनिया तेजी से बदल रही है और इसका सीधा असर रोजगार के अवसरों पर पड़ रहा है। लंबे समय तक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस और एमबीए जैसी डिग्रियों को बेहतर करियर की कुंजी माना जाता रहा है लेकिन अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई कई पारंपरिक कार्यों को अपने हाथ में ले रही है। ऐसे में रोजगार का स्वरूप बदल रहा है और नई तरह की क्षमताओं की मांग बढ़ रही है। उनका मानना है कि युवाओं को भविष्य की जरूरतों को समझते हुए अपने कौशल को नए क्षेत्रों के अनुसार विकसित करना होगा।

समय की जरूरत

नागेश्वरन ने इस बात पर चिंता जताई कि भारत में ट्रेड स्किल्स वाले पेशों को वह सम्मान नहीं मिलता, जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि वेल्डर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई और अन्य तकनीकी काम करने वाले लोग किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इन देशों में व्यावसायिक कौशल रखने वाले लोगों को काफी सम्मान दिया जाता है। भारत में भी इस सोच को बदलने की जरूरत है ताकि युवा इन क्षेत्रों को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित हों.

पेशे जिन्हें एआई नहीं बदल सकता

मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मानवीय संवेदनाएं और व्यक्तिगत संपर्क सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुजुर्गों की देखभाल, विशेष जरूरतों वाले बच्चों की काउंसलिंग, अस्पतालों में सहायक सेवाएं, खेल शिक्षा, खाना बनाने की कला और अन्य सेवा क्षेत्र ऐसे उदाहरण हैं जहां इंसानी उपस्थिति की जरूरत बनी रहेगी। उनका कहना है कि एआई भले ही कई तकनीकी कार्यों को आसान बना दे, लेकिन इन पेशों में मानवीय स्पर्श की जगह लेना उसके लिए आसान नहीं होगा। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित और योग्य लोगों की मांग भविष्य में बढ़ सकती है

रोजगार व योग्यता दोनों पर देना होगा ध्यान

नागेश्वरन ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश के सामने केवल बेरोजगारी की चुनौती नहीं है, बल्कि रोजगार योग्यता यानी लोगों को काम के लिए तैयार करने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। उनके अनुसार केवल नौकरियां पैदा करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि युवाओं को उन नौकरियों के लिए जरूरी कौशल भी सिखाने होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था अधिक पूंजी-आधारित होती जा रही है, जहां कई उद्योग कम लोगों को रोजगार दे पाते हैं। इसलिए श्रम-प्रधान उद्योगों और सेवाओं के विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में हैं अवसर

उन्होंने भारत को अपनी विनिर्माण क्षमता मजबूत करने की सलाह भी दी। उनका मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अब पहले की तरह खुली नहीं रह गई है और कई देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत को भी कई उत्पाद खुद बनाने होंगे। हालांकि इसके साथ-साथ श्रम-प्रधान उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में भी बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। यदि इन क्षेत्रों में सही प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए, तो लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि देश की आर्थिक प्रगति को भी गति मिलेगी। नागेश्वरन का संदेश साफ है कि आने वाले वर्षों में केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं होगा। युवाओं को व्यावहारिक कौशल, संवाद क्षमता, समस्या समाधान और मानवीय समझ जैसे गुणों पर भी काम करना होगा।

उनका मानना है कि वैश्वीकरण के दौर में सॉफ्टवेयर और एमबीए शिक्षा ने भारत को बड़ा लाभ दिया था, लेकिन अब समय बदल रहा है। एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच वही लोग अधिक अवसर हासिल कर पाएंगे, जिनके पास ऐसे कौशल होंगे जिन्हें मशीनें आसानी से नहीं दोहरा सकतीं। इसलिए ट्रेड स्किल्स व सॉफ्ट स्किल्स को अपनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत बनती जा रही है।

बीएचयू के छात्रों को 6 महीने की इंटर्नशिप देगा आईआईटी बॉम्बे

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे के 'कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम-2026' के तहत बीएचयू और अन्य संस्थानों के छात्रों को उद्यमिता एवं नेतृत्व कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बीएचयू के छात्रों को इस साल आईआईटी बॉम्बे उद्यमिता और नेतृत्व कौशल का पाठ पढ़ाएगा।

आईआईटी बॉम्बे के एंटरप्रेन्योरशिप सेल की तरफ से कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम-2026' के अंतर्गत बीएचयू के उन छात्रों के आवेदन आमंत्रित किए हैं जो युवा उद्यमी हैं या नवाचारी विचारों पर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के लिए बीएचयू के अलावा आईआईटी बीएचयू सहित अन्य संस्थानों के छात्र भी दावेदारी कर सकते हैं।

आईआईटी बॉम्बे की यह पहल छह माह की ऑनलाइन इंटर्नशिप के रूप में विद्यार्थियों में उद्यमिता, नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल और नवाचार की भावना को बढ़ावा देगी। कार्यक्रम के माध्यम से छात्र न केवल स्टार्टअप और उद्यमिता के क्षेत्र की बारीकियों को समझ सकेंगे, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर के छात्र नेटवर्क से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। चयनित प्रतिभागियों को विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों, शिक्षण संसाधनों और पेशेवर विकास गतिविधियों के जरिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इंटर्नशिप पूरी करने वाले छात्रों को प्रमाणपत्र के साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन (एलओआर) भी प्रदान किया जाएगा, जो उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक कॅरियर में उपयोगी होगा। आईआईटी बॉम्बे ने इंटर्नशिप के सफल अभ्यर्थियों को प्रतिष्ठित ई-समिट 2026 से जुड़ने और उसके आयोजन में अवसर देने का भी निर्णय लिया है।

कार्यक्रम के तहत छात्रों को विभिन्न प्रीमियम सॉफ्टवेयर टूल्स, विशेष छूट और अन्य लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे जो भविष्य में उनके स्टार्टअप्स में भी मददगार होंगे। बीएचयू में सभी संकाय और विभागों को इस इंटर्नशिप की सूचना छात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

खास बातें

- छह महीने का है ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम
- इसका उद्देश्य छात्रों में उद्यमिता, नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना
- प्रतिभागियों को देशभर के उद्यमी छात्रों के नेटवर्क से जुड़ने का अवसर दिलवाना।
- सफल प्रतिभागियों को इंटर्नशिप प्रमाणपत्र और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिए जाएंगे
- विभिन्न शिक्षण संसाधनों, प्रीमियम सॉफ्टवेयर टूल्स, डिस्काउंट और अन्य सुविधाओं का भी लाभ दिलवाना।

डेटा की दुनिया में बनाएं फ्यूचर रेडी करियर

भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में शामिल

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। हर दिन दुनिया भर में अरबों गीगाबाइट डेटा तैयार हो रहा है, जिसे समझने और उसके आधार पर बेहतर निर्णय लेने के लिए डेटा साइंस विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, शिक्षा और सरकारी सेवाओं से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर क्षेत्र में डेटा साइंस पेशेवरों के लिए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं।

भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में शामिल हो चुका है। डिजिटल ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग ने डेटा साइंस को सबसे आकर्षक करियर विकल्पों में शामिल कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल्स की मांग कई गुना बढ़ेगी, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

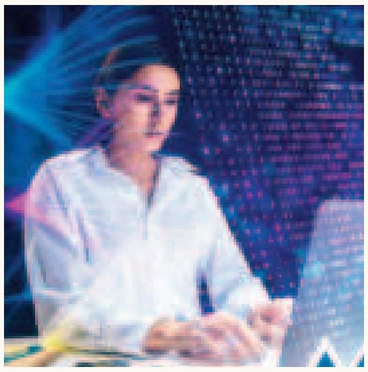

डेटा साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बड़े पैमाने पर उपलब्ध डेटा का विश्लेषण कर उपयोगी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और विजनेस समझ का उपयोग करके डेटा को व्यवस्थित किया जाता है और उससे भविष्य की रणनीतियां तैयार की जाती हैं। सरल शब्दों में कहें तो डेटा साइंस का उद्देश्य डेटा को ऐसी जानकारी में बदलना है जो किसी संगठन या व्यवसाय को बेहतर निर्णय लेने में मदद करे। आज कंपनियां ग्राहकों की पसंद, बाजार के रुझान, बिक्री के आंकड़े और उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए डेटा साइंस का व्यापक उपयोग कर रही हैं। यही कारण है कि यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है।

डेटा साइंस में करियर बनाने के लिए कई तरह के शैक्षणिक और व्यावसायिक कोर्स उपलब्ध हैं। छात्र 12वीं के बाद बीएससी डेटा साइंस, बीटेक इन डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स जैसे कोर्स चुन सकते हैं। स्नातक के बाद एमएससी डेटा साइंस, एमटेक, एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स या पीजी डिप्लोमा जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। इसके अलावा कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और संस्थान डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विग डेटा एनालिटिक्स और पाइथन प्रोग्रामिंग से जुड़े सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित कर रहे हैं। ये कोर्स विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को कम समय में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करने में मदद करते हैं।

जरूरी स्किल्स

डेटा साइंस में सफलता के लिए केवल डिग्री ही पर्याप्त नहीं होती। छात्रों को कुछ तकनीकी और विश्लेषणात्मक कौशल भी विकसित करने होते हैं। इनमें पाइथन, आर प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, सांख्यिकी और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रमुख हैं। इसके साथ ही समस्या समाधान क्षमता, तार्किक सोच, संचार कौशल और बिजनेस समझ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंपनियां ऐसे पेशेवरों को प्राथमिकता देती हैं जो डेटा का विश्लेषण करने के साथ उसके आधार पर प्रभावी सुझाव भी दे सकें।

करियर के प्रमुख अवसर

डेटा साइंस का क्षेत्र करियर के अनेक अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र में डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, विजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, एआई स्पेशलिस्ट और बिग डेटा आर्किटेक्ट जैसी भूमिकाएं लोकप्रिय हैं। आईटी कंपनियों के अलावा बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थकेयर, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, ई-कॉमर्स, मीडिया और सरकारी संस्थानों में भी डेटा विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है। स्टार्टअप्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भर्ती कर रही हैं।

आरबीआई ने यंग प्रोफेशनल्स के लिए निकाली भर्ती

1.5 लाख होगी सैलरी, 6 जुलाई तक करें आवेदन

दीपक सहगल

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय के अलग-अलग विभागों में यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 जुलाई तक ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रिस्क और सस्टेनेबल फाइनेंस, पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स, डेटा एनालिटिक्स, पॉलिसी रिसर्च और सुपरविजन जैसे स्पेशल क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा।

वेतन और कार्यकाल

इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को 1.5 लाख रुपये प्रति माह का निश्चित मानदेय (स्टाइपेंड) दिया जाएगा। नियुक्ति फुल-टाइम कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर होगी। बता दें कि शुरुआती कॉन्ट्रेक्ट की अवधि 3 साल की होगी, जिसे प्रदर्शन और आपसी सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, कुल कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं होगा।

इतना ही नहीं आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि यंग प्रोफेशनल्स को बैंक का स्थायी कर्मचारी नहीं माना जाएगा और उन्हें नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते या अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी।

कितने पद भरे जाएंगे

आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कई पद भरे जाएंगे। ये पद हैं-

- पॉलिसी एनालिटिक्स
- जलवायु परिवर्तन जोखिम और सतत वित्त
- क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स एवं रेगुलेटरी पॉलिसी
- पेमेंट इकोसिस्टम
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में नीति एवं अनुसंधान
- पॉलिसी एवं रिसर्च
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- क्वांटम टेक्नोलॉजी
- डेटा एनालिसिस
- फाइनेंशियल मार्केट्स
- डेटा एनालिटिक्स एवं पॉलिसी रिसर्च

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री, प्रोफेशनल योग्यता, इंजीनियरिंग डिग्री या रिसर्च अनुभव रखने वाले उम्मीदवार अलग-अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

चयनित सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति मुंबई में की जाएगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

आवेदन कैसे करें ?

उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन फॉर्म की स्कैन कॉपी और जरूरी दस्तावेजों को ईमेल के जरिए yphrmdco@rbi.org.in पर भेजना होगा। आवेदन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होंगे।

- बायोडाटा
- शैक्षणिक प्रमाणपत्र और योग्यता संबंधी दस्तावेज
- रुचि विवरण
- शैक्षणिक या नीतिगत लेखन का नमूना
- किसी पेशेवर रेफरी का सिफारिश या संदर्भ पत्र
- यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन भेजना होगा।
- चयन प्रक्रिया
- प्रारंभिक स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग
- दस्तावेजों का सत्यापन
- व्यक्तिगत साक्षात्कार (इंटरव्यू)

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर केवल ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा।

योग्यता : आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा, 6 जुलाई तक उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख भी 6 जुलाई ही तय की गई है। सफल उम्मीदवारों को मुंबई में पोस्टिंग दी जाएगी और उनकी जॉइनिंग अगस्त से अक्टूबर के बीच होगी।

भारतीय छात्रा को ऑक्सफोर्ड विवि में पीएचडी के लिए मिली 2 करोड़ की स्कॉलरशिप

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। बड़ी कामयाबी की शुरुआत असफलताओं से ही होती है। अगर आप किसी मुश्किल लक्ष्य को पाने के लिए बार बार प्रयास करते हैं तो यह पक्का है कि एक दिन उसे आप पा ही लेंगे। वैष्णवी रामालिंगम की कहानी युवाओं को यही सीख देती है। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में पीएचडी करने के लिए लगभग 2 करोड़ (157000 पाउंड) की प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप मिलने पर भारतीय छात्रा वैष्णवी रामालिंगम ने खुशी जाहिर की है। वैष्णवी रामलिंगम ने बताया कि यह कामयाबी उन्हें कई महीनों तक रिजेक्शन झेलने के बाद मिली है। कई बार रिजेक्ट होने के बाद वह इस बार फॉर्म नहीं भरने वाली थी। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइम और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में रैंक 1 पर है जबकि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में यह चौथे पायदान पर है।

इंस्टाग्राम पर वैष्णवी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप मिलने की खबर सुनकर उनकी खुशी और भावनाएं दिखाई दे रही हैं। क्लिप पर लिखा था, 'फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट होने के नाते अपनी पीएचडी के लिए लगभग 2 करोड़ की ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप मिलना बेहद सुखद पल है।'

कैप्शन में वैष्णवी ने अपने सफर और उस पल के बारे में बताया जब उन्हें यह खबर मिली। उन्होंने लिखा, 'सोचिए, मैंने जो भी कोशिश की उसमें 8 महीने तक सिर्फ रिजेक्शन ही मिला और जिस एक चीज की मुझे सबसे कम उम्मीद थी (लेकिन जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती थी), जिसके लिए मैंने लगभग अप्लाई भी नहीं किया था, वही मेरे लिए सच हो गई? मुझे नहीं लगता कि उस ईमेल को पढ़कर मुझे जो महसूस हुआ, उसे मैं कभी शब्दों में बयां कर पाऊंगी।'

फार्म नहीं भरना चाहती थीं वैष्णवी रामालिंगम

उन्होंने आगे कहा, 'कायनात ही आपके लिए रास्ते बनाती है।' बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैष्णवी को ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ में पूरी तरह से फंडेड डीफिल (पीएचडी) करने के लिए क्लेरेंडन स्कॉलरशिप दी गई है। गौरतलब है कि लगभग 2 करोड़ की क्लेरेंडन स्कॉलरशिप दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में से एक है। यह असाधारण एकेडमिक उपलब्धि और रिसर्च की क्षमता के आधार पर दी जाती है।

पब्लिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि वैष्णवी लॉ में डीफिल के लिए क्लेरेंडन स्कॉलरशिप पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इससे पहले यह स्कॉलरशिप पाने वाले भारतीयों में गौतम भाटिया (2018), निरंजन वेंकटेशन (2014) और शिवप्रसाद स्वामीनाथन (2008) शामिल हैं।

कहां से पढ़ी हैं वैष्णवी

रिपोर्ट के अनुसार वैष्णवी ने सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे से बीए एलएलबी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की। बाद में उन्होंने नीदरलैंड्स की लीडेन यूनिवर्सिटी में 'लीडेन यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप' पर इंटरनेशनल चिल्ड्रन्स राइट्स में एडवांस्ड एलएलएम किया। पहली पीढ़ी की ग्रेजुएट के तौर पर अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सफर अक्सर अकेलेपन से भरा होता है। उन्होंने कहा, बिना किसी साफ रोडमैप या गाइड के परिवार में पहली बार ऐसी नई जगहों पर आगे बढ़ना बहुत अकेलापन भरा हो सकता है, अक्सर ऐसा लगता है कि दूसरों के पास ऐसी जानकारी और गाइडेंस है जो आपके लिए बिल्कुल नई है, और जो चीजें आपको अनजान या पहुंच से बाहर लगती हैं, वे किसी और के लिए रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा होती हैं।'

प्रोफेसरों को दिया श्रेय

वैष्णवी ने ऑक्सफोर्ड में अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित करने का श्रेय लीडेन यूनिवर्सिटी के अपने प्रोफेसरों को दिया। उन्होंने कहा, 'उन्होंने मुझमें मुझसे कहीं पहले ही काबिलियत देख ली थी और इस तरह का भरोसा बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, खासकर पहली पीढ़ी के छात्रों के लिए।

उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका, 2 जुलाई आवेदन की आखिरी तारीख

देहरादून। उत्तराखंड में नर्सिंग में करियर बनाने वालों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा ने राज्य में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती अभियान के तहत राज्य में कुल 196 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

सिंधु घाटी सभ्यता की मशहूर प्रतिमा पर बदला एनसीईआरटी का रुख

नई दिल्ली। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मशहूर ऐतिहासिक धरोहरों में से एक- 'डांसिंग गर्ल' की मूर्ति को लेकर छिड़े विवाद के बीच अब यह तय किया गया है कि एनसीईआरटी की किताब में मूर्ति का मूल स्वरूप ही प्रकाशित किया जाएगा। एनसीईआरटी ने अपनी क्लास 9 की नई किताब में मोहनजोदड़ो की मशहूर 'डांसिंग गर्ल' (नर्तकी की मूर्ति) की तस्वीर में किए गए बदलाव को वापस लेने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में किताब की सॉफ्ट कापी में यह बदलाव हो जाएगा। डिजिटल रूप में किताब में डांसिंग गर्ल का मूल स्वरूप ही नजर आएगा।

प्रतिमा का धड़ ढकने पर उठे थे सवाल

'डांसिंग गर्ल' प्रतिमा करीब चार हजार वर्ष पुरानी मानी जाती है। इतिहास और पुरातत्व से जुड़ी किताबों में इसे अक्सर मूल स्वरूप में प्रकाशित किया जाता है। हालांकि एनसीईआरटी की नई किताब में प्रकाशित तस्वीर में प्रतिमा के धड़ (टॉर्सो) वाले हिस्से को छायांकित या ढका हुआ दिखाया गया है, जिसको लेकर सवाल उठाए गए।

ब्रिटेन में पीएम स्टार्मर ने 16 साल से छोटे बच्चों के लिए किया सोशल मीडिया बैन

लंदन। ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया एप के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। पीएम कीर द स्टार्मर ने कहा कि बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक पीएम के तौर पर और छोटे बच्चों के पिता के तौर पर उनका यह फैसला उचित है। स्टार्मर ने माना कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक्नॉलॉजी कंपनियों पर इस तरह की रोक लगाना आसान नहीं होगा लेकिन बच्चों की सेहत और भलाई सबसे ज्यादा जरूरी है।

पैरेंट्स करेंगे स्वागत

ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने कहा, आज हमारे देश के लिए एक बड़ा पल है। यह हमारे बच्चों और हमारे भविष्य के लिए एक बड़ा कदम और असल बदलाव है, क्योंकि आज मैं यह घोषणा कर सकता हूं कि सरकार 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाएगी। ब्रिटिश पीएम ने विश्वास जताया कि माता-पिता इस फैसले का स्वागत करेंगे, क्योंकि तकनीक में बदलाव के साथ सरकार के दृष्टिकोण को भी बदलना महत्वपूर्ण है।

नर्सिंग ऑफिसर के 5989 पद , 92 हजार तक सैलरी

आवेदन प्रक्रिया शुरू, 6 जुलाई अंतिम तिथि

ब्लिट्ज ब्यूरो

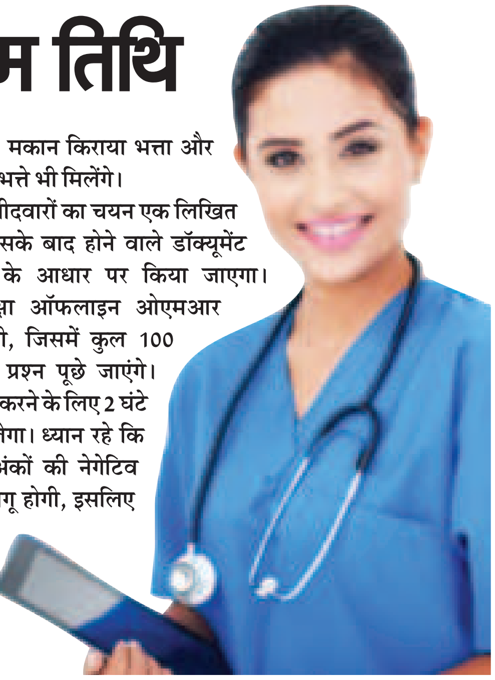

भुवनेश्वर। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ा अवसर सामने आया है। ओडिशा सब-ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (ओएसएसएससी) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत नर्सिंग ऑफिसर (ग्रुप-सी) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस मेगा भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य के सभी 30 जिलों में कुल 5,989 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण तारीखें

- ओडिशा नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 13 जून से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई तय की गई है।
- रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपने भरे हुए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को 13 जुलाई तक फाइनल सब्मिट कर सकते हैं।
- परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि के बारे में आयोग द्वारा बाद में सूचित किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उनके पास जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए।

काउंसिल रजिस्ट्रेशन

उम्मीदवारों के पास ओडिशा नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।

भाषा की समझः यह जिला कैडर की नौकरी है, इसलिए आवेदक ने कक्षा 7 या उससे ऊपर की परीक्षा उड़िया भाषा के विषय के साथ पास की हो।

आयु सीमाः सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित श्रेणियों और महिला उम्मीदवारों) को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

पैकेज और चयन प्रक्रिया

चयनित होने वाले उम्मीदवारों को ओडिशा संशोधित वेतनमान (ओआरएसपी नियम 2017) के पे-मैट्रिक्स लेवल-8 के तहत वेतन दिया जाएगा। इसमें न्यूनतम बेसिक पे 29,200 रुपये से लेकर अधिकतम 92,300 रुपये प्रति माह तक का वेतनमान शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन्हें महंगाई भत्ता , मकान किराया भत्ता और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलेंगे।

योग्य उम्मीदवारों का चयन एक लिखित परीक्षा और उसके बाद होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर आधारित होगी, जिसमें कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा को पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। ध्यान रहे कि इसमें 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, इसलिए छात्रों को बेहद सावधानी से उत्तर देने होंगे।

BHARATIYA
ANTARIKSH
HACKATHON
2026

भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2026 का इसरो ने किया शुभारंभ

अंतरिक्ष व जलवायु संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए भारतीय छात्र आमंत्रित

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। इसरो ने तीसरे भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन का शुभारंभ करते हुए भारतीय छात्रों को नवोन्मेषी विचारों के माध्यम से अंतरिक्ष और जलवायु संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए आमंत्रित किया है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) ने भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन (बीएएच) 2026 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया है, जिसमें छात्र नवप्रवर्तकों को भारत के बढ़ते अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विचारों का योगदान करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

'हैक2स्किल' नामक नवाचार मंच द्वारा संचालित, इस राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य भारत की कुछ सबसे जटिल खगोलीय और जलवायु संबंधी चुनौतियों के लिए सामूहिक रूप से समाधान जुटाना है।

यह प्रतियोगिता केवल उन स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी शोधार्थियों के लिए खुली है जो वर्तमान में मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थानों में नामांकित हैं। कार्यरत पेशेवर इसमें भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

टीमों में तीन से चार सदस्य होने चाहिए। विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र अंतर-कॉलेज और अंतर-विश्वविद्यालय सहयोग के माध्यम से एक ही टीम बना सकते हैं।

यह प्रतियोगिता केवल उन स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी शोधार्थियों के लिए खुली है जो वर्तमान में मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थानों में नामांकित हैं। कार्यरत पेशेवर इसमें भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

टीमों में तीन से चार सदस्य होने चाहिए। विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र अंतर-कॉलेज और अंतर-विश्वविद्यालय सहयोग के माध्यम से एक ही टीम बना सकते हैं।

20 जुलाई को चयनित टीमों की होगी घोषणा

हैकाथॉन के लिए पंजीकरण और विचार प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 10 जून से शुरू हो गई है। इसरो प्रतिभागियों को चुनौतियों के तकनीकी दायरे को समझने में मदद करने के लिए को दो समस्या विवरण स्पष्टीकरण सत्र आयोजित करेगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 1 जुलाई है।

मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद, इसरो 20 जुलाई, 2026 को चयनित टीमों की घोषणा करेगा। 21 जुलाई को एक प्रेरण सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद 6 और 7 अगस्त, 2026 को 30 घंटे का लाइव ग्रैंड फिनाले होगा।

हैकथॉन में भाग लेना निःशुल्क है। इच्छुक टीमें हैक2स्किल के आधिकारिक इवेंट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। पंजीकरण के दौरान टीमों को कोई भौतिक प्रोटोटाइप बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, उन्हें 1 जुलाई की समय सीमा से पहले प्लेटफ़ॉर्म पर दिए गए टेम्पलेट्स का उपयोग करके एक विस्तृत वैचारिक समाधान प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

चयनित फाइनलिस्टों को विकास प्रक्रिया के दौरान आईएसआरओ के वैज्ञानिकों और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। राष्ट्रीय मान्यता के साथ-साथ, प्रतिभागियों को आईएसआरओ में वास्तविक अंतरिक्ष परियोजनाओं पर काम करने के लिए आधिकारिक इंटर्नशिप के अवसर भी मिल सकते हैं। अंतिम समारोह के आयोजन के लिए आयोजक सभी चयनित फाइनलिस्टों के लिए द्वितीय श्रेणी की एसी यात्रा का किराया वहन करेंगे।

आईपी विश्वविद्यालय फायर सेफ्टी में कॅरिअर बनाने का दे रहा मौका

नई दिल्ली। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ (आईपी) विश्वविद्यालय छात्रों को आग और औद्योगिक सुरक्षा (फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी) में कॅरिअर बनाने का अवसर दे रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने अलग-अलग कोर्स में दाखिला लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें सप्ताहांत एक्जीक्यूटिव एमबीए, एमबीए और पीजी डिप्लोमा (फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी) कोर्स शामिल हैं।

इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 2500 रुपये के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. नलिनी रंजन के अनुसार तीनों कोर्स रोजगारोन्मुखी है। बाजार में इनकी अच्छी मांग है। तीन कोर्स विश्वविद्यालय के द्वारका परिसर के विभिन्न स्कूलों में उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। वे यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की लास्ट डेट 27 जुलाई निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवार 03 अगस्त तक अपने फॉर्म में करेक्शन पर सकते हैं।

एम्स में बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी

1400 से ज्यादा वैकेंसी, परीक्षा अगले महीने

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने युवाओं के लिए शानदार अवसर उपलब्ध करवाया है। एम्स दिल्ली ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम (सीआरई-5) के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके तहत ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के नॉन-फैकल्टी श्रेणी में बंपर भर्तियां निकाली गई हैं। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1484 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं।

3 जुलाई तक खुला रहेगा पोर्टल

एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम (सीआरई-5) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की खिड़की खुल चुकी है। उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, इसका कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) आगामी 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। छात्रों के पास तैयारी के लिए बेहद सीमित समय है, इसलिए उन्हें अभी से अपनी रणनीति मजबूत कर लेनी चाहिए।

इन पदों पर निकली भर्तियां

असिस्टेंट डाइटीशियन, डाइटीशियन, वार्डन, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एलडीसी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यूडीसी, जूनियर इंजीनियर सिविल / इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल एसी आर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट (ईएनटी), इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन (इलेक्ट्रिकल), मैनिफोल्ड टेक्निशियन, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, टेक्निशियन ओटी/ एनेस्थीसिया / ऑपरेशन थियेटर, फार्मासिस्ट, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, स्टोर कीपर, कैशियर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर, जूनियन स्टोर ऑफिसर, सीएसएसएसडी टेक्निशियन, लिफ्ट ऑपरेटर, मॉर्चुअरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी इंफो असिस्टेंट, लाइब्रेरियन ग्रेड 1, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, कोडिंग क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर स्केल स्टेनो, प्राइवेट सेक्रेटरी, मेडिकल सोशल वेलफेयर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिस असिस्टेंट फायर ऑफिसर, एम्ब्रोयोलॉजिस्ट, फायर टेक्निशियन, ड्राइवर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, मल्टी पर्पस वर्कर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ट्रांसप्लांट कोर्डिनेटर, योगा इंस्ट्रक्टर, प्रोग्रामर, टेलर ग्रेड 3, लॉन्ड्री मैकेनिक, जूनियर इंजीनियर सेफ्टी, पीएसीएस एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्च असिस्टेंट, मेडिकल फोटोग्राफर, जूनियर फोटोग्राफर, आर्टिस्ट आदि।

श्रेणी के आधार पर एप्लीकेशन फीस

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को उनकी श्रेणियों के आधार पर रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करना होगा।

- जनरल और ओबीसी उम्मीदवार 3,000 रुपये
- एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारः 2,400 रुपये
- दिव्यांग उम्मीदवारः इस वर्ग के आवेदकों को रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट दी गई है, यानी उनके लिए आवेदन बिल्कुल निशुल्क है।

गलत उत्तर पर कटेगा एक अंक

इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए उम्मीदवारों को इसके एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह समझना होगा। परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर जैसे विभिन्न विषयों से जुड़े 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।

पूरी परीक्षा 400 अंकों की होगी, यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 4 अंक मिलेंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। हर एक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक (1) अंक) काट लिया जाएगा। परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक भी तय किए गए हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस को न्यूनतम 40 प्रतिशत, ओबीसी को 35 प्रतिशत और एससी व एसटी उम्मीदवारों को पास होने के लिए कम से कम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।

आईआईटी दिल्ली क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स 2027 में फिर अव्वल

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटी, दिल्ली) ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में भारत के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। आईआईटी दिल्ली को इस बार वैश्विक स्तर पर 118वां स्थान मिला है, जो किसी भी भारतीय संस्थान द्वारा हासिल की गई संयुक्त रूप से सबसे अच्छी रैंकिंग में शामिल है। यह उपलब्धि दिखाती है कि भारतीय संस्थान अब दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

वहीं, भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था की वैश्विक पहचान भी लगातार बढ़ रही है। क्यूएस रैंकिंग्स 2027 में इस बार 52 भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह मिली है, जिससे भारत दुनिया का पांचवां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। वर्ष 2017 में जहां केवल 14 भारतीय संस्थान इस रैंकिंग में शामिल थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 52 हो गई है। यह वृद्धि जी20 देशों में सबसे तेज मानी जा रही है।

रैंकिंग के अनुसार, 26 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी स्थिति में सुधार किया, नौ ने अपनी रैंकिंग बरकरार रखी, 15 की रैंकिंग में गिरावट आई, जबकि दो संस्थान पहली बार रैंकिंग में शामिल हुए। भारत के पूर्व में रैंकिंग में शामिल आधे से अधिक विश्वविद्यालयों ने इस वर्ष अपने प्रदर्शन में सुधार किया है।

प्रदर्शन का स्वागत करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परिणाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत शुरू किए गए सुधारों के प्रभाव को दर्शाते हैं।

प्रधान ने कहा, नवीनतम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत का सशक्त प्रदर्शन एनईपी 2020 के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है। अब 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 52 विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल हैं और आधे से अधिक विश्वविद्यालयों ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थानों की रिकॉर्ड-उच्च रैंकिंग के साथ, भारत अनुसंधान, नवाचार और अपने युवाओं की प्रतिभा के बल पर एक अग्रणी वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में उभर रहा है।

QS
WORLD
UNIVERSITY
RANKINGS
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों ने भी रचा इतिहास

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली लगातार मजबूत हो रही है। उनके अनुसार, सरकारी और निजी दोनों तरह के संस्थानों में सुधार देखने को मिल रहा है, जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह बदलाव देश में शिक्षा की गुणवत्ता, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों का परिणाम है।

आईआईटी बॉम्बे को 134वां, आईआईटी मद्रास को 170वां, आईआईटी खडगपुर को 205वां और आईआईटी कानपुर को 221वां स्थान मिला। वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय की रैंकिंग सुधरकर 322वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया को 686वां स्थान मिला। रैंकिंग से यह भी पता चलता है कि भारत की सफलता अब सिर्फ आईआईटी संस्थानों तक सीमित नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत 18 भारतीय संस्थानों ने अपनी अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग हासिल की है। इनमें से अधिकांश गैर आईआईटी संस्थान हैं।

विदेशी छात्रों को आकर्षित करना अब भी चुनौती

भारत के विश्वविद्यालयों ने रिसर्च और रोजगार क्षमता के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। प्रति संकाय उद्धरण के मामले में 11 भारतीय विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हो गए हैं, जबकि नियोक्ता प्रतिष्ठा के आधार पर 6 भारतीय संस्थानों ने वैश्विक टॉप-100 में जगह बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शोध उत्पादन वाला देश बन चुका है।

रैंकिंग में कई भारतीय संस्थानों ने बड़ी छलांग लगाई है। वीआईटी ने 94 स्थानों की बढ़त के साथ 597वीं रैंक हासिल की, बिट्स पिलानी 93 स्थान ऊपर चढ़कर 575वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने भी 75 से अधिक स्थानों का सुधार दर्ज किया।

हो जाएं तैयार! यूपी में 60000 शिक्षकों की होनी है भर्ती

ब्लिट्ज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीएसएससी) राज्य में शिक्षकों की सबसे बड़ी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब 60,000 रिक्त शिक्षक पदों को भरा जा सकता है। बताया जा रहा है कि हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा है। प्रदेश के युवाओं को इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार भी था।

आधिकारिक सूचना के मुताबिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तैयारियां चल रही हैं। इस भर्ती अभियान से सरकारी स्कूलों में लंबे समय से बनी हुई शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक शहरी क्षेत्रों के रिक्त पदों का ब्यौरा पहले ही आयोग को भेजा जा चुका है। अब अधिकारी ग्रामीण जिलों से भी इसी तरह की जानकारी एकत्र कर रहे हैं, जिसके बाद अंतिम आंकड़े आयोग को सौंपे जाएंगे।

कितने पद हैं खाली

वहीं, पिछली रिक्तियों को मिलाकर प्रदेश के स्कूलों में 60 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं। इनमें से शहरी स्कूलों में 11,508 शिक्षकों के पद भी शामिल हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में 48,000 से अधिक शिक्षक पद खाली हैं, जो कुल रिक्तियों का बड़ा हिस्सा है। इसकी जानकारी भी विभाग को भेजी जा रही है।

कब शुरू होगी प्रक्रिया?

बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की आखिरी भर्ती साल 2018 में हुई थी। वहीं, शहरी क्षेत्रों में कई वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। अब सरकार इन रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है। बेसिक शिक्षा परिषद ने शहरी क्षेत्रों में खाली पदों का विवरण आयोग को भेज दिया है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया तब आगे बढ़ेगी, जब संबंधित अधियाचन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होंगे। इसके बाद सभी रिक्तियों का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन आयोग को भेजा जाएगा। आवश्यक जानकारी अपलोड होते ही भर्ती की अगली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

कब जारी होगा नोटिफिकेशन

हालांकि अभी तक भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन चल रही तैयारियों को देखते हुए माना जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता, आवेदन तिथि और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणाओं पर नजर बनाए रखें।

कॉटन पर कार्बन का साया

अगर भारत को अपने टेक्सटाइल सेक्टर को बनाए रखना है, तो उसे मैनमेड फाइबर पर ध्यान देना होगा।

भारत के एक्सपोर्ट बास्केट में कॉटन का दबदबा बना हुआ है, लगभग 80 प्रतिशत, जबकि ग्लोबल डिमांड मैन-मेड फाइबर, एथलीजर और ब्लेंडेड कैटेगरी की ओर तेजी से बढ़ी है, जो अब दुनिया के टेक्सटाइल ट्रेड का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं।

ब्लिट्ज विशेष

तिरुपुर में, जो दक्षिणी क्लस्टर तीन दशकों से पश्चिमी दुनिया के बड़े हिस्से को कपड़े सप्लाई कर रहा है, उसके फैक्ट्री मैनेजरों ने 2025 की शरद ऋतु अपने फोन को पास रखकर बिताई। न्यूयॉर्क, बोस्टन और अटलांटा के खरीदार ऑर्डर देने के लिए नहीं, बल्कि ऑर्डर कैंसिल करने के लिए फ़ोन कर रहे थे। कन्फर्म शिपमेंट रोक दिए गए। नए ऑर्डर बिल्कुल नहीं आए। जब 2026 का साल शुरू हुआ, तो भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट, अमेरिका, अनिश्चितता का सबसे बड़ा स्रोत बन गया था।

यह वह साल था जब दुनिया ने यह दिखावा करना बंद कर दिया कि भारत की टेक्सटाइल इकॉनमी चुपचाप ऑटो-पायलट पर चल रही है। वाशिंगटन से टैरिफ पांच महीनों में 10 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गए। सरकार के पॉलिसी थिंक टैंक, नीति आयोग ने सालों में अपना सबसे कड़ा आकलन जारी किया: भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को तत्काल और व्यापक ₹ की जरूरत है, वरना ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ खोने का खतरा है।

टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अपने आंतरिक दस्तावेज़ों में माना कि हाल के वर्षों में कॉम्पिटिटिवनेस कम हुई है क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम आगे निकल गए हैं।

बचाव

और फिर भी यह सेक्टर बच गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर में, भारत का कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2.1 प्रतिशत बढ़कर ₹3.16 लाख करोड़ हो गया, यह एक मामूली आंकड़ा है, लेकिन बहुत कुछ बताने वाला है।

यह ग्रोथ अमेरिका से नहीं, बल्कि 120 से ज़्यादा अन्य जगहों से आई: यूएई को शिपमेंट में 22.3 प्रतिशत, जापान को 20.6 प्रतिशत, मिस्र को 38.3 प्रतिशत और सूडान को 205.6 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। पता चला कि भारत का टेक्सटाइल बास्केट भौगोलिक रूप से आलोचकों की सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन भौगोलिक विविधता का मतलब स्ट्रक्चरल मजबूती नहीं है।

ज्यादातर पैमानों पर, भारतीय टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। लगभग 179 अरब अमेरिकी डॉलर की कीमत वाला यह सेक्टर भारत की जीडीपी में करीब 2 प्रतिशत का योगदान देता है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड में 11 प्रतिशत और कुल सामान के एक्सपोर्ट में 8.63 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है।

यह सीधे तौर पर 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है, खेती के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है। इसकी लगभग 80 प्रतिशत क्षमता एमएसएमई क्लस्टर में है, जो इस सेक्टर को एक ऐसे देश में विकास के लिहाज से खास अहमियत देता है जहां छोटे उद्योगों में रोजगार हमेशा से एक अहम राजनीतिक मुद्दा रहा है।

और फिर भी, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, जिसकी ग्लोबल मार्केट में हिस्सेदारी सिर्फ 4 प्रतिशत है। मार्च 2025 में जारी नीति आयोग की 'ट्रेड वॉच दूसरी तिमाही वित्त वर्ष 2025' रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत कॉटन और कालीन में तो बहुत अच्छा है, लेकिन कपड़ों में पीछे है और हाई-वैल्यू टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट में बहुत पीछे है, जिस पर अब चीन, जर्मनी और दक्षिण कोरिया का दबदबा है।

रुके हुए आंकड़े

दिल्ली के टेक्सटाइल मंत्रालय में हर बातचीत में ये आंकड़े चर्चा का विषय होते हैं: 2023–24 में भारत का गारमेंट एक्सपोर्ट 14.5 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो एक दशक पहले के 15 अरब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग उतना ही रहा। इसी दौरान, वियतनाम का एक्सपोर्ट बढ़कर 33.4 अरब अमेरिकी डॉलर और बांग्लादेश का 43.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। जहां भारत वहीं का वहीं रहा, वहीं उसके दो सबसे करीबी प्रतिस्पर्धियों ने अपना प्रोडक्शन लगभग दोगुना कर लिया।

इसके कारण बताना मुश्किल नहीं है। भारत के एक्सपोर्ट बास्केट में अभी भी कॉटन का दबदबा है, लगभग 80 प्रतिशत, जबकि ग्लोबल डिमांड तेज़ी से मैन-मेड फाइबर, एथलीजर और ब्लेंडेड कैटेगरी की ओर बढ़ी है, जो अब दुनिया के टेक्सटाइल व्यापार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं।

भारतीय फैक्टरियां वियतनाम की फैक्टरियों की तुलना में छोटे पैमाने पर काम करती हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी कम है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) तो साइन किए गए हैं, लेकिन उनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है: नीति आयोग ने उसी रिपोर्ट में बताया कि एफटीए देशों के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट साल-दर-साल 23 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि एफटीए पार्टनर देशों को होने वाला एक्सपोर्ट असल में 4 प्रतिशत घटा है।

टैरिफ वाले साल का इंसानी असर एक जैसा नहीं था। मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने बताया कि इसका सबसे बुरा असर एमएसएमई और ज्यादा मज़दूरों वाले उद्योगों पर पड़ा, ये वही सेक्टर हैं जो झटके झेलने में सबसे कमजोर हैं और जिनमें महिलाएं और ग्रामीण मजदूर सबसे ज्यादा काम करते हैं।

टेक्सटाइल की 80% क्षमता एमएसएमई क्लस्टर में होने की वजह से, मुनाफ़े में लगातार कमी का असर मजदूरी, नौकरियों और उन छोटे शहरों पर भी पड़ता है जहाँ टेक्सटाइल फैक्टरियां ही औपचारिक रोज़गार का मुख्य जरिया होती हैं। अकेले तिरुपुर क्लस्टर में कई लाख मजदूर काम करते हैं; और सूरत के पावर-लूम बेल्ट में भी कई लाख मजदूर जुड़े हैं। जब अमेरिका से ऑर्डर रुकते हैं, तो इसका असर सबसे पहले बोर्डरूम में महसूस नहीं होता।

पॉलिसी का सपोर्ट मौजूद है

सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। ₹10,683 करोड़ की 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (पीएलआई) स्कीम का मकसद मैन-मेड फाइबर (एमएमएफ) के कपड़े, एमएमएफ फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल के दस सेगमेंट को बढ़ावा देना है। 'पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल' (पीएम मित्रा) पार्क्स स्कीम के तहत अब सात जगहों– तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को फाइनल कर लिया गया है। इनसे ₹70,000 करोड़ का निवेश आने और 20 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

दिसंबर 2025 तक कॉटन (कपास) पर इंपोर्ट ड्यूटी को सस्पेंड कर दिया गया था। नवंबर 2025 में लेबर कोड में बदलाव करके महिलाओं को रेडीमेड गारमेंट यूनिट्स में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी गई, यह बांग्लादेश से मिल रही क्षमता बढ़ाने की चुनौती का सीधा जवाब था, भले ही इसे आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया।

सबसे अहम बात यह है कि भारत के एफटीए ढांचे को बहुत तेजी से फिर से तैयार किया गया। जुलाई 2025 में भारत-यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए गए। अक्टूबर में भारत-ईएफटीए टीईपीए लागू हुआ। दिसंबर में भारत-ओमान सीईपीए पर साइन हुए। 27 जनवरी 2026 को भारत-ईयू एफटीए को अंतिम रूप दिया गया, यह एक पीढ़ी से भी ज़्यादा समय में भारतीय टेक्सटाइल के लिए मार्केट तक पहुंच के मामले में सबसे अहम घटना थी।

नीति आयोग की छह जरूरी बातें

सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम के नेतृत्व में मार्च 2025 में जारी नीति आयोग की 'ट्रेड वॉच दूसरी तिमाही वित्त वर्ष 2025' रिपोर्ट में भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सुधार की छह जरूरी बातें बताई गईं , जो कई सालों में सबसे साफ-सुथरा आधिकारिक विश्लेषण था।

पहली, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन: फाइबर से लेकर फैशन तक बिखरी हुई वैल्यू चेन को एक साथ लाना।

दूसरी, कॉस्ट एफिशिएंसी: वियतनामी और बांग्लादेशी स्ट्रक्चर से मुकाबला करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाना और बड़े पैमाने पर उत्पादन करना।

तीसरी, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स: उत्पादन को पर्यावरण से जुड़े नियमों के साथ जोड़ना, जो अब ईयू मार्केट में ज़रूरी हैं, जिसमें 'एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी' (ईपीआर) नियम भी शामिल हैं।

चौथी, इनोवेशन: पॉलिसी का फोकस हाई-वैल्यू टेक्निकल टेक्सटाइल और मैन-मेड फाइबर कपड़ों की ओर ले जाना।

पांचवीं, FTA का असरदार इस्तेमाल: मार्केट तक पहुंच को मार्केट में मौजूदगी में बदलना।

छठी, पॉलिसी-आधारित कॉम्पिटिटिवनेस: भारत के सेक्टर से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए छूट, इंसेंटिव और स्किलिंग को और बेहतर बनाना। सुब्रह्मण्यम ने हमेशा की तरह साफ-साफ कहा, "नेचुरल फाइबर वाले टेक्सटाइल में मजबूत मौजूदगी के बावजूद, ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी कम है। इससे इनोवेशन, आधुनिकीकरण और पॉलिसी आधारित कॉम्पिटिटिवनेस की जरूरत साफ पता चलती है।"

इसका मुख्य संदेश यह है, इस सेक्टर की ढांचागत समस्याओं को सिर्फ टैरिफ में छूट या छूट वाली स्कीमों से हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैन-मेड फाइबर, बड़े पैमाने पर उत्पादन और ज्यादा कीमत वाली कैटेगरी की ओर पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है, जिनमें भारत की क्षमता कम है।

बड़े लक्ष्य

मोदी सरकार का लक्ष्य 2030 तक टेक्सटाइल मार्केट को लगभग 176 अरब डॉलर से बढ़ाकर 350 अरब डॉलर करना और इसी दौरान एक्सपोर्ट को 3 लाख करोड़ रुपये से तीन गुना बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपये करना है। यूनियन बजट 2026–27 में टेक्सटाइल को एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क में रखा गया, जिसमें फाइबर से लेकर फैशन और ग्रामीण उद्योगों से लेकर ग्लोबल मार्केट तक सब शामिल हैं।

टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के बजट एलोकेशन को पिछले साल के मुकाबले 19 प्रतिशत बढ़ाकर 5,272 करोड़ रुपये कर दिया गया, साथ ही जूट सेक्टर को फिर से खड़ा करने के लिए 12,000 करोड़ रुपये का अलग फंड तय किया गया। मिनिस्ट्री का अनुमान है कि अकेले हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट चेन से एक करोड़ कारीगर जुड़े हुए हैं।

यह एक बड़ा गणित है। क्या यह असल में मुमकिन भी है, यह एक ही सवाल पर निर्भर करता है, क्या भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इस दशक के बचे हुए चार सालों में कॉटन इकॉनमी से मैन-मेड फाइबर इकॉनमी, छोटे पैमाने से बड़े पैमाने, एफटीए साइन करने वालों से एफटीए इस्तेमाल करने वालों और कम-वैल्यू वाले प्रोडक्शन से टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्शन की ओर बढ़ सकता है ?

अब इसके लिए साधन मौजूद हैं। समस्या की पहचान कर ली गई है। नीति आयोग ने सुधार का एजेंडा ऐसी भाषा में बताया है जो किसी सरकारी संस्था के लिए आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। वर्किंग डॉक्यूमेंट्स में बांग्लादेश से तुलना करने से अब शालीनता के नाम पर बचा नहीं जाता।

पीएम मित्रा पार्क असल रूप ले रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में धार साइट 14,600 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, जिससे तीन लाख नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। और एफटीए, जिनका सालों तक कम इस्तेमाल हुआ, उनके लिए आखिरकार ऐसे खरीदार मिल सकते हैं जो भारत से बड़ी मात्रा में सामान खरीदना चाहें।

कार्बन फाइबर का सवाल

भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका कॉटन या कपड़ों में नहीं, बल्कि टेक्निकल टेक्सटाइल में है और ठीक यहीं भारत सबसे ज़्यादा कमजोर स्थिति में है। भारतीय टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट की वैल्यू 2024 में 29 अरब डॉलर थी और इसके 2026 तक 45 अरब डॉलर, 2035 तक 123 अरब डॉलर और 2047 तक 309 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस सेगमेंट में भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा मार्केट है। अकेले भारत का कम्पोजिट्स मार्केट इस साल 16.3% की सालाना कंपाउंडेड दर से बढ़कर 1.9 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

फिर भी, भारत में कार्बन फाइबर का घरेलू उत्पादन नहीं होता है। इस मटीरियल का हर किलोग्राम, जिसका इस्तेमाल एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, विंड एनर्जी, डिफेंस और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में होता है, अमेरिका, फ्रांस, जापान और जर्मनी से इम्पोर्ट किया जाता है। यही बात एरामिड्स और अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन के बारे में भी सच है, जो आगरोधी कपड़ों, बुलेटप्रूफ जैकेट और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले खास फाइबर हैं।

फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 2025-26 के लिए 1,480 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किए गए 'नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन' ने इस समस्या पर काम करना शुरू कर दिया है।

लेकिन यह अंतर रणनीतिक और कमर्शियल, दोनों तरह का है। जब तक कार्बन फाइबर का सवाल अनसुलझा रहेगा, भारत की टेक्सटाइल आत्मनिर्भरता अधूरी रहेगी और इस सेक्टर में ग्लोबल ग्रोथ का अगला 280 अरब डॉलर का हिस्सा कहीं और चला जाएगा।

तिरुपुर में फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि वे अपनी क्षमता के 80 से 90 प्रतिशत पर काम कर रहे हैं जो पिछले तीन सालों की तुलना में एक शांत सुधार है। टैरिफ सेटलमेंट के बाद नए ऑर्डर धीरे-धीरे वापस आ रहे हैं। लूम्स (करघे) बंद नहीं हुए हैं। लेकिन आगे क्या बुना जाएगा, कॉटन या कार्बन फाइबर, कपड़े या जियो-टेक्सटाइल्स, तिरुपुर या धार, यही तय करेगा कि क्या भारत 2030 में दुनिया को कपड़े पहनाएगा, या सिर्फ दुनिया को यह याद दिलाएगा कि उसने कभी ऐसा किया था।

रिकॉर्ड : 1.78 लाख करोड़ पहुंचा भारत का रक्षा उत्पादन

2025-26 में इस क्षेत्र में 15.6% की बढ़ोतरी हुई

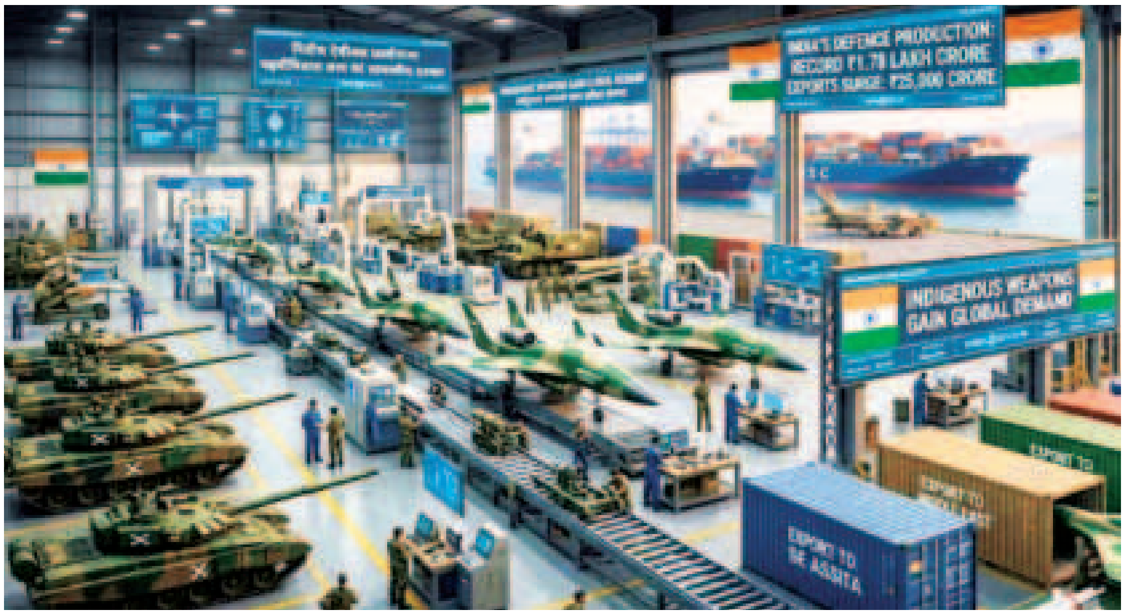
INDIA'S DEFENCE PRODUCTION:
RECORD ₹1.78 LAKH CRORE
EXPORTS SURGE: ₹25,000 CRORE
INDIGENOUS WEAPONS GAIN GLOBAL DEMAND

ब्लिट्ज विशेष

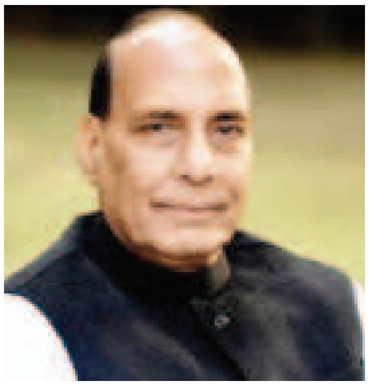

नई दिल्ली। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए सार्वजनिक रक्षा कंपनियों और निजी क्षेत्र के प्रयासों की सराहना की। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 2025-26 में रक्षा उत्पादन में 15.6% की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2024-25 में रक्षा उत्पादन 1.54 लाख करोड़ था। 2020-21 के बाद इसमें 110% की बढ़ोतरी हुई, तब यह 84643 करोड़ रुपये था। 2013-14 से तुलना करें तो इसमें चार गुना की बढ़ोतरी हुई है।

रक्षा उत्पादन में और तेजी से बढ़ोतरी होगी

रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के रक्षा औद्योगिक आधार की मजबूती का स्पष्ट संकेत है। लगातार नीतिगत समर्थन, कई नई पहल, निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी और निर्यात की बढ़ती क्षमताओं के साथ आने वाले दिनों में रक्षा उत्पादन और तेजी से बढ़ेगा।

रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा, भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025-26 में नया रिकॉर्ड बनाया है। देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। इसके लिए रक्षा उत्पादन विभाग तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सामूहिक प्रयास बधाई के पात्र हैं।

रक्षा मंत्रालय का बयान रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कुल 1.78 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन में सरकारी कंपनियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी 76 फीसदी है, जबकि निजी क्षेत्र की 24 फीसदी रही है लेकिन, इसमें भी एक रुझान देखा गया है कि वर्ष 2024-25 में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 22 फीसदी थी जो एक साल में दो फीसदी बढ़ी है। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र का उत्पादन भी अब तक का सर्वाधिक 42 हजार करोड़ दर्ज किया गया है। इससे जाहिर होता है कि देश में रक्षा उत्पादन की स्थितियां तेजी से अनुकूल हो रही हैं।

भारत ने जल, थल और नभ में अपनी ताकत बढ़ाई : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के विजन, नई तकनीक और स्वदेशी निर्माण ने भारत को मजबूती दी है। प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों के सफर का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे भारत ने जल, थल और नभ में अपनी ताकत बढ़ाई है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत नींव करार दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 'विकसित भारत' के लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार की श्रेष्ठ प्रशासनिक और सुशासन संबंधी पहलों को अपनाना चाहिए।

> **भारत के 65 फीसदी रक्षा उपकरण अब घरेलू स्तर पर ही निर्मित किए जा रहे हैं। इस स्वदेशीकरण के पीछे 16 हजार से अधिक एमएसएमई नेटवर्क और 1,000 से अधिक रक्षा स्टार्टअप्स है।**

रक्षा बाजार में बड़े निर्यातक के रूप में स्थापित हो रहा देश

sipri REPORTS

नई दिल्ली। हाल में जारी रुबिक्स डेटा साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार, भारत तेजी से वैश्विक रक्षा बाजार में एक बड़े निर्यातक के रूप में स्थापित हो रहा है। भारत 80 से अधिक देशों को सैन्य सामान निर्यात कर रहा है।

निर्भरता घटाई, सप्लायर बदले

सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है, लेकिन उसने रूस पर अपनी निर्भरता को 70 फीसदी (2011-15) से घटाकर 40 फीसदी (2021-25) कर दिया है। अब भारत फ्रांस (29 फीसदी) और इजरायल (15 फीसदी) जैसे देशों से रक्षा आयात कर रहा है।

घरेलू हिस्सेदारी पर जोर

डिफेंस इंडस्ट्री इनसाइट्स नाम से जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लगभग 65 फीसदी रक्षा उपकरण अब घरेलू स्तर पर ही निर्मित किए जा रहे हैं। इस स्वदेशीकरण के पीछे 16 हजार से अधिक एमएसएमई नेटवर्क और 1,000 से अधिक रक्षा स्टार्टअप्स है, जिन्होंने 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का फंड जुटाया है। यह मजबूत ढांचा भारतीय कंपनियों को कीमतों में लचीलापन और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की ताकत देता है।

नेवी को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत

आत्मनिर्भरता में है हमारी शक्ति की पहचान: मोदी

ब्लिट्ज ब्यूरो

कोलकाता। तीन स्वदेशी वॉरशिप्स आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और एंटी-सबमरीन आईएनएस अग्रय विगत दिवस भारतीय नौसेना में शामिल हुए।

आईएनएस संशोधक एक बार में लगातार 12 हजार किलोमीटर तक जा सकता है। आईएनएस दूनागिरी 8 ब्रह्मोस मिसाइल्स से लैस है। वहीं, आईएनएस अग्रय भारतीय तटरेखा के पास मौजूद दुश्मन पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है।

इस दौरान कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी शक्ति की पहचान विश्व का बाजार बनने में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता में है। कार्यक्रम के दौरान नौसेना के जवानों ने परेड और फ्लैग होस्टिंग की।

कमीशंड वॉरशिप्स अब अपने निर्धारित कमांड में तैनात कर दिए जाएंगे।

भारतीय नौसेना में 140 से 145 वॉरशिप्स

भारतीय नौसेना के पास इस समय लगभग 140 से 145 सक्रिय वॉरशिप्स हैं। नौसेना का मुख्य लक्ष्य साल 2030 तक अपने जहाजों की कुल संख्या को 150 से 160 तक पहुंचाना है।

RI - COMMISSIONI
INS DUNAGIRI, INS SANSHO... INS
ON 21 JUNE

भारत अपने इन युद्धपोतों को मुख्य रूप से तीन नौसैनिक कमांड्स और एक रणनीतिक द्वीप कमान में तैनात करता है। विशाखापट्टनम (पूर्वी कमान) के जहाज बंगाल की खाड़ी और मलक्का में चीन की घेराबंदी करते हैं।

मुंबई और कारवाड़ (पश्चिमी कमान) के युद्धपोत अरब सागर में पाकिस्तान पर नजर रखने और समुद्री लुटेरों से व्यापारिक जहाजों को बचाने के लिए चौबीसों घंटे तैनात रहते हैं। इसके अलावा, समंदर के बीचों-बीच अंडमान और निकोबार कमान में तैनात जहाज दुश्मन के प्रवेश मार्ग को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। आधुनिक नौसैनिक युद्ध में युद्धपोतों की भूमिका सबसे अहम हो चुकी है, क्योंकि दुनिया का 90% व्यापार समुद्री रास्तों से ही होता है। आज के युद्धपोत केवल जहाज नहीं, बल्कि समंदर में तैरते मिलिट्री बेस हैं।

समुद्र में बढ़ी परमाणु ताकत

रिपोर्ट में भारत की समुद्री परमाणु क्षमता को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। भारत की परमाणु पनडुब्बियां, खासकर आईएनएस अरिहंत, अब देश की 'सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी' का बड़ा आधार बन रही हैं। सिपरी का अनुमान है कि भारत अब शांति काल में भी सीमित संख्या में परमाणु हथियारों को बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर तैनात करने लगा है। इससे दुश्मन के पहले हमले के बाद भी जवाबी कार्रवाई की क्षमता बनी रहती है। आईएनएस अरिघात पनडुब्बी पानी के अंदर से परमाणु हथियार लॉन्च कर सकती है।

तीनों वॉरशिप की खासियतें

आईएनएस दूनागिरी- ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस

आईएनएस दूनागिरी प्रोजेक्ट-17ए का 5वां स्टील्थ फ्रिगेट वॉरशिप है। इसे नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। प्रोडक्शन कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर (डिजाइनेट) कैप्टन दिव्य आलोक ने कहा कि दूनागिरी ईस्ट नेवल कमान और ईस्टर्न फ्लीट का हिस्सा बनेगा।

आईएनएस संशोधक- समुद्र का नक्शा और सर्वे करेगा

आईएनएस संशोधक सर्वे वेसल (लार्ज) सीरीज का चौथा जहाज है। इसका काम युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि समुद्र का सर्वे करना है। इसे तट और गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे, समुद्री डेटा कलेक्शन और डिफेंस-सिविल यूज के लिए बनाया गया है। बंदरगाहों और समंदर के रास्तों का सर्वे करना भी इसके मुख्य काम में शामिल है।

आईएनएस अग्रय- दुश्मन की सबमरीन खोजकर नष्ट करेगा

आईएनएस अग्रय अर्नाला क्लास का चौथा एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट यानी उथले पानी का वॉरशिप है। इसे हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और एडवांस्ड सोनार सिस्टम से लैस किया गया है जिससे यह तटों पर तैनात दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें निशाना बना सकता है।

ब्रह्मोस, आकाश व 'नेत्र' की दुनिया में बढ़ रही मांग

डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत का दबदबा, 4 देशों से 21000 करोड़ के सौदे

नई दिल्ली। भारतीय रक्षा उद्योग वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। 'ऑपरेशन सिंदूर' में ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, लॉयटरिंग म्यूनिशन और 'नेत्र' जैसे स्वदेशी हथियारों के शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया भर में भारतीय 'वार' मशीनरी की मांग में भारी उछाल आया है। चार देशों ने इनकी खरीद के लिए भारत से समझौते किए हैं।

रक्षा मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में ₹38,424 करोड़ का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62% अधिक है। भारत ने अब 2029-30 तक ₹50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ी मांग

भारत की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलीपींस, वियतनाम और दो अन्य देशों के साथ करीब ₹12,500 करोड़ के सौदे हो चुके हैं। फिलीपींस के साथ करीब ₹3,200 करोड़ की डील पूरी हो चुकी है। वियतनाम से ₹5,800 करोड़ की डील पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्द होने वाली है।

इंडोनेशिया में लगभग ₹3,600 करोड़ की डील अंतिम चरण में है, जबकि मलेशिया और थाईलैंड ने भी इसमें गहरी रुचि दिखाई है।

आकाश-1एस एयर डिफेंस सिस्टम

आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए आर्मेनिया के साथ ₹6,100 करोड़ का अनुबंध पहले ही हो चुका है और इसकी डिलीवरी वर्तमान में जारी है, जिसे हाल ही में आर्मेनिया की सालाना परेड में भी दिखाया गया था। इसके अलावा, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों ने भी आकाश-1एस में रुचि दिखाई है, जबकि 'आकाश-एनजी' को लेकर नई बातचीत चल रही है।

पिनाका रॉकेट सिस्टम

दूसरी ओर, भारत की पिनाका बहु-बैरल रॉकेट प्रणाली की डिलीवरी आर्मेनिया को की जा चुकी है, जहां इसे 'शांत' नाम से सेना में शामिल किया गया है। गाइडेड पिनाका की मारक क्षमता 75 किलोमीटर है और अब इसे खरीदने के लिए फ्रांस की रुचि की खबरें भी सामने आ रही हैं।

लॉयटरिंग म्यूनिशन और 'नेत्र' सिस्टम

भारतीय लॉयटरिंग म्यूनिशन (नागास्त्र-1 और स्काईस्ट्राइकर) की विदेशों में मांग तेजी से बढ़ी है। साइप्रस ने अपने 2026-31 के रक्षा रोडमैप में इसे खरीदने की इच्छा जताई है।

दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों से भी लगातार पूछताछ आ रही है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एचएएल और अडाणी डिफेंस जैसी कंपनियां अपना उत्पादन तेजी से बढ़ा रही हैं।

100 से अधिक देशों को निर्यात

भारत वर्तमान में दुनिया के 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया प्रमुख हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार है, जहां बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए $2.8 अरब के भारतीय रक्षा उपकरण और कल्पुर्जे भेजे जाते हैं।

मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कामयाब

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। डीआरडीओ का मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कामयाब रहा है। इसकी बदौलत 5000 कमी से आ रही दुश्मन मिसाइल को मार गिराया जाएगा।

यह तकनीक हासिल करने वाला भारत 5वां देश बन गया है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर रेंज में किया गया। इस टेस्ट के लिए यहां 11 गांव खाली कराए गए थे।

भारत अब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, यहां तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों का भी मुकाबला कर सकता है। डीआरडीओ ने पिछले सप्ताह लगातार 3 फ्लाइट टेस्ट किए, जिनमें मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) क्लास तक के खतरों को रोकने और बेअसर करने की क्षमता भी शामिल है।

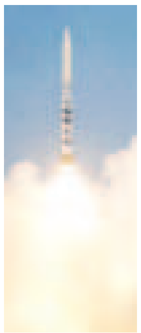

यह स्वदेशी तकनीक दुश्मन की मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हवा में ही नष्ट कर देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टेस्टिंग की तस्वीरें X अकाउंट पर शेयर भी की हैं। इसके साथ-साथ नेवल एंटी शिप मिसाइल-मीडियम रेंज का भी टेस्ट किया गया। इसे भारत की समुद्री स्ट्राइक और डिफेंस स्किल को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। भारत अब उन खास देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है, जिनके पास ऑपरेशनल-लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता है। भारत से पहले यह तकनीक अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन के पास थी।

क्या होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल

आसान भाषा में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बहुत लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल कहा जा सकता है। यह ऐसी मिसाइल होती है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच सकती है। आमतौर पर 5,500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है।

तुषार मेहता फिर बने सॉलिसिटर जनरल

लगातार तीसरी बार तीन साल का कार्यकाल मिला

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तीन साल के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है।

आदेश में कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तीन साल के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। मेहता को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में सेवा देने के बाद अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार ने बाद में उन्हें 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी तीन साल के कार्यकाल के लिए और फिर 2023 में पुनः नियुक्त किया।

नवीनतम कार्यकाल विस्तार के साथ,

पांच एएसजी की पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी

मेहता सॉलिसिटर जनरल के रूप में लगभग आठ वर्ष पूरे कर चुके हैं और नए कार्यकाल के अंत तक इस पद पर 11 वर्ष पूरे करने वाले हैं, जिससे वे देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले विधि अधिकारियों में से एक बन जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल के रूप में, मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई महत्वपूर्ण संवैधानिक, नीतिगत और आपराधिक मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया है। एसीसी ने सर्वोच्च न्यायालय के लिए पांच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों (एएसजी) की तीन साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है।

विक्रमजीत बनर्जी और केएम नटराज को 1 जुलाई, 2026 से पुनः नियुक्त किया गया है, जबकि एसवी राजू, एन वेंकटरामन और ऐश्वर्या भाटी को 30 जून, 2026 से पुनः नियुक्त किया गया है।

बिनॉय जॉर्ज उरुग्वे में भारत के अगले राजदूत नियुक्त

नई दिल्ली। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित देश उरुग्वे में भारत के नए राजदूत बिनॉय जॉर्ज होंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि 2006 बैच के आईएफएस जॉर्ज वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और उन्हें ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे में बतौर राजदूत नियुक्त किया गया है। वो जल्द ही अपना नया कार्यभार संभालेंगे।

नियुक्ति से पहले तक, अर्जेंटीना में भारत के राजदूत अजनीश कुमार ही राजदूत के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी (समवर्ती मान्यता) निभा रहे थे। एमईए के ऑफिशियल साइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, डॉ. बिनॉय जॉर्ज भारतीय विदेश सेवा के एक अनुभवी राजनयिक हैं।

सीनियर आईपीएस महेश दीक्षित को खुफिया एजेंसी आईबी की कमान

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख घरेलू खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की कमान अब एक अनुभवी और जांबाज अधिकारी के हाथों में सौंप दी गई है। केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने 1993 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश कैडर के अधिकारी महेश दीक्षित देश की आंतरिक सुरक्षा की कमान ऐसे समय में संभाल रहे हैं, जब वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं।

दीक्षित ने श्रीनगर में आईबी के सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो (एसआईबी) के प्रमुख के तौर पर अहम साल बिताए हैं, जहां उनके अधिकार क्षेत्र में जम्मू, कश्मीर और लेह आते थे। अधिकारियों का कहना है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद के

समय में आंतरिक स्थिरता बनाए रखने और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों पर नजर रखने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई।

जमीनी स्तर पर इंटेलिजेंस नेटवर्क और आतंकवाद रोधी मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए पहचाने जाने वाले दीक्षित ने आईबी में कई संवेदनशील जिम्मेदारियां संभाली हैं, जिनमें नक्सलवाद और सीमा पार से घुसपैठ जैसे मामले शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में उनके अनुभव से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, कट्टरपंथ और नार्को-टेरर नेटवर्क से निपटने के लिए एजेंसी की रणनीति तय होने की उम्मीद है।

यूपी भाजपा में राजनाथ के बेटे को बनाया उपाध्यक्ष

ब्लिट्ज ब्यूरो

लखनऊ। यूपी भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले नई टीम का एलान कर दिया है। भाजपा की नई टीम में ओबीसी को तरजीह दी गई है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को भाजपा उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा पूजा पाल और सुरेश राणा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई लिस्ट में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री शामिल हैं। इसी तरह पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए हैं।

नीरज सिंह

सरोज कुशवाह को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देवेंद्र सिंह किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। अशोक रावत अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रकाश पाल पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त

पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए

किए गए हैं। दिनेश प्रताप सिंह मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। रोहित मिश्रा भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं।

इनको प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया

रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल,राजेश चौधरी

इन नेताओं को क्षेत्रीय अध्यक्ष पद दिया गया

नवाब सिंह नागर - क्षेत्रीय अध्यक्ष (पश्चिम)
पूरन लाल लोधी - क्षेत्रीय अध्यक्ष (ब्रज)
राम किशोर साहू - क्षेत्रीय अध्यक्ष (कानपुर)
अवधेश द्विवेदी - क्षेत्रीय अध्यक्ष (अवध)
अशोक चौरसिया - क्षेत्रीय अध्यक्ष (काशी)
विनोद राय - क्षेत्रीय अध्यक्ष (गोरखपुर)।

इन नेताओं को मिली प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी

नीरज सिंह, सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर डॉ धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दुर्विजय शाक्य, रमेश सिंह,नीरज सिंह,अर्चना मिश्रा,पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह, कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी, आलोक गुप्ता

भारत सरकार में सचिव विवेक अग्रवाल बने एफएटीएफ उपाध्यक्ष

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार के सचिव विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का उपाध्यक्ष चुना गया है। एफएटीएफ दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग पर नजर रखने वाली सबसे अहम संस्थाओं में से एक है।

विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। मंत्रालय का कहना है कि यह नियुक्ति आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति और वैश्विक स्तर पर आतंकियों की फंडिंग रोकने के प्रयासों को और मजबूती देगी।

1994 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल फिलहाल संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। उन्हें प्रशासनिक सेवा में तीन दशक से अधिक का अनुभव है। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, विवेक अग्रवाल का चुनाव इस बात का संकेत है कि वैश्विक वित्तीय सुरक्षा और अवैध धन के खिलाफ कार्रवाई में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। एफएटीएफ दुनिया के देशों के लिए ऐसे नियम और मानक तय करती है, जिनका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाना है।

एफएटीएफ में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं अग्रवाल

विवेक अग्रवाल पहले एफएटीएफ में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। वह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया के निदेशक भी रह चुके हैं।

इस दौरान उन्होंने आर्थिक अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय खुफिया से जुड़े मामलों पर काम किया।

भारत की बढ़ती विश्वसनीयता का संकेत

संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि एफएटीएफ में यह जिम्मेदारी मिलना दुनिया के 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के बीच भारत की बढ़ती विश्वसनीयता का प्रमाण है। मंत्रालय के अनुसार, डिजिटल पेमेंट, वर्चुअल एसेट्स और नए वित्तीय जोखिमों से जुड़े वैश्विक नियम बनाने में भी भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

एफएटीएफ ने पहलगाम हमले की निंदा की थी

जून 2025 में एफएटीएफ ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी और सभी देशों से आतंक की फंडिंग रोकने की अपील की थी।

इसके बाद, भारत ने एफएटीएफ को पाकिस्तान को दोबारा 'ग्रे लिस्ट' में डालने का औपचारिक अनुरोध दिया था। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान से हो रही फंडिंग के कारण ही सीमा पार से आतंकी गतिविधियां चल रही हैं।

मुंबई में 130 एकड़ में होगा कोस्टल रोड गार्डन्स का निर्माण

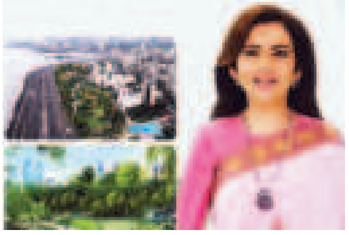

- 60 हजार पेड़, वॉकिंग ट्रेल्स, बच्चों के लिए प्ले एरिया की मिलेगी सुविधा
- नीता अंबानी ने किया प्रोजेक्ट का एलान

मुंबई। मुंबई को एक नई हरी-भरी जगह मिलने वाली है जो आम लोगों के लिए होगी। इसके लिए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान कोस्टल रोड गार्डन्स प्रोजेक्ट की घोषणा की है।

इस प्रोजेक्ट का विजन शेयर करते हुए नीता अंबानी ने कहा कि ये गार्डन 130 एकड़ में फैला होगा। इसमें 60 हजार से ज्यादा पेड़ होंगे, जो इसे शहर की सबसे बड़ी हरी-भरी जगहों में से एक बनाएंगे।

एजीएम में दी गई जानकारी के अनुसार, कोस्टल रोड गार्डन्स में टहलने के लिए वॉकिंग ट्रेल्स, बच्चों के लिए प्ले एरिया, परिवारों के लिए आकर्षण और खेल की आधुनिक सुविधाएं होंगी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कोस्टल रोड कॉरिडोर के किनारे रहने वाले लोगों के लिए एक जगह बनाना जो मनोरंजन और प्रकृति दोनों का केंद्र हो।

इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए डिजाइन की गई जगह बताते हुए नीता अंबानी ने कहा कि यह गार्डन शहर के पर्यावरण और लोगों की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक निवेश के रूप में तैयार किया जा रहा है।

इस एलान के साथ प्रोजेक्ट की पहली झलक भी दिखाई गई, जिसका लक्ष्य है शहर में हरियाली बढ़ाना और मुंबईवासियों के लिए नई और खुली सार्वजनिक जगह उपलब्ध कराना।

नमो भारत का नया रिकॉर्ड, एक दिन में सवा लाख ने किया सफर

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर 8 जून को अब तक की सबसे अधिक डेली राइडरशिप रिकॉर्ड की गई। लगभग 1,25,500 यात्रियों के साथ यह पूरे कॉरिडोर पर एक दिन में अब तक दर्ज की गई यात्रियों की सबसे अधिक संख्या है। आम दिनों में औसतन लगभग 1 लाख यात्री रोज नमो भारत सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।

बड़े बदलाव का संकेत

यह उपलब्धि एनसीआर में लोगों के यात्रा करने के तरीके में आ रहे बड़े बदलाव को दिखाती है जहां यात्री अब तेज, समयबद्ध और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन के रूप में नमो भारत को चुन रहे हैं। नमो भारत की ओर से यात्रा समय में होने वाली उल्लेखनीय कमी इसकी बढ़ती लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। रोजाना कार्यालय आने-जाने वाले, विद्यार्थी और अन्य नियमित यात्री, जिनके लिए समय पर पहुंचना और विश्वसनीयता एक जरूरत है, अपनी दैनिक यात्रा के लिए नमो भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। ट्रेनों के संचालन में लगभग 99% समयबद्धता के कारण यात्री अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए इस प्रणाली पर भरोसा कर रहे हैं और उन्हें सड़कों पर लगने वाले जाम और यात्रा की अनिश्चितता से राहत भी मिल रही है।

मिल रही है जबरदस्त कनेक्टिविटी

दिल्ली में सराय काले खां, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार व उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और बेगमपुल कॉरिडोर पर सबसे व्यस्त स्टेशनों की सूची में लगातार बने हुए हैं।

ये सभी स्टेशन सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों जिनमें मेट्रो, भारतीय रेलवे, आईएसबीटी और सिटी बसें शामिल हैं, के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। ये स्टेशन सम्मिलित रूप से कॉरिडोर की कुल राइडरशिप में लगभग 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहे हैं।

आसान हुआ सफर

वहीं, मेरठ में नमो भारत के इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर परिचालित हो रही स्थानीय मेरठ मेट्रो सेवाओं ने शहर के भीतर यात्रा को भी अधिक सुगम बना दिया है। इससे यात्रियों को एक ही कॉरिडोर पर रीजनल और स्थानीय, दोनों प्रकार की निर्बाध यात्रा सुविधा उपलब्ध हो रही है, जो इस परियोजना की एक खास खूबी है।

ईन्धन की बढ़ती कीमतों के बीच किफायती विकल्प

दिल्ली-एनसीआर में वर्तमान में 40-45 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी के बीच पूरी तरह वातानुकूलित नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव भी प्रदान कर रही हैं। ईन्धन की बढ़ती कीमतों के बीच यह प्रणाली न केवल एक किफायती विकल्प के रूप में उभर रही है, बल्कि निजी वाहनों के स्थान पर अधिक कुशल एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित कर रही है।

बढ़ाई गई ट्रिप्स

यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए एनसीआरटीसी ने हाल ही में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर पीक आवर्स के दौरान 18 अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स शुरू की हैं। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और शाम 5 बजे से 8:30 बजे तक सराय काले खां से मेरठ साउथ स्टेशन के बीच ये अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सार्वजनिक परिवहन के अधिक इस्तेमाल की अपील की गई थी। यह पहल उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राइडरशिप में लगातार हो रही बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि नमो भारत अब केवल एक परिवहन विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि बड़ी संख्या में यात्रियों के दैनिक जीवन का एक भरोसेमंद हिस्सा बनता जा रहा है।

भारतीय रेल की बड़ी तैयारी, राख ढो कर भी कमाएगा करोड़ों रुपये

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। थर्मल पावर प्लांट से निकली राख (फ्लाई एश) कभी पावर प्लांट के लिए सिर दर्द का सबब थी लेकिन जबसे इसका उपयोग सड़क बनाने, सीमेंट या ईंट बनाने में हो रहा है, इसे लेने के लिए बिजली घर के बाहर ट्रकों की लाइन लगी रहती है। अब रेलवे नबिजली घर की इसी राख या छाई से करोड़ों रुपये की कमाई की पुख्ता योजना बना रहा है।

बेहद गंभीर है रेलवे

राख या छाई की ढुलाई के प्रति रेलवे कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद रुचि ले रहे हैं। इसी सप्ताह रेलवे बोर्ड में इस बारे में जब एक उच्च स्तरीय बैठक हुई तो खुद रेल मंत्री उसमें शामिल थे।

डेडिकेटेड लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाने की योजना

रेलवे बोर्ड के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि रेल मंत्री ने जो एक उच्च स्तरीय बैठक की, उसमें कई बातों पर चर्चा हुई। इस दौरान बिजली घर से निकली राख की ढुलाई में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है, उसके विकल्पों पर भी विचार किया गया। सूत्र बताते हैं कि इस छाई की ढुलाई के लिए रेलवे एक डेडिकेटेड लॉजिस्टिक नेटवर्क भी बना सकता है। थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली छाई की ढुलाई अभी ज्यादातर ट्रकों से ही होती है।

बीएस-6 वाहन मालिकों को मिल सकती है बड़ी राहत

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में बीएस-VI वाहनों के मालिकों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ऐसे निजी बीएस6 वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी पीयूसीसी की वैधता बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिनकी उम्र छह साल से कम है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो वाहन मालिकों को हर साल अपने वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें लंबे समय तक वैधता का लाभ मिलेगा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार निजी वाहनों के लिए पीयूसी नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है।

प्रस्तावित ढांचे के तहत:

- 6 साल से कम पुराने बीएस6 निजी वाहनों के लिए पीयूसी की वैधता 3 साल तक हो सकती है।
- इससे वाहन मालिकों को हर साल दस्तावेज नवीनीकरण की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
- सरकार का यह फैसला प्रदूषण प्रमाण पत्र व्यवस्था में किए जा रहे एक बड़े सुधार का हिस्सा है।
- प्रस्तावित नियमों के अनुसार, गाड़ियों की उम्र और उनकी श्रेणी के आधार पर पीयूसीसी की वैधता तय की जाएगी-
- 6 से 10 साल पुरानी निजी गाड़ियां: मालिकों को पहले की तरह ही हर साल अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा।

आंध्र की प्राकृतिक खेती को मिला विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में कम्युनिटी के स्तर पर चलाई जा रही प्राकृतिक खेती (एपीसीएनएफ) को दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार का नाम '2026 फूड प्लैनेट प्राइज़' है। 15 लाख अमेरिकी डॉलर (1.5 मिलियन डॉलर) का यह पुरस्कार स्वीडन के बास्ताद में दिया गया।

साल 2026 के 'फूड प्लैनेट प्राइज' के लिए दुनिया भर से 1,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स और नामांकन भेजे गए थे। कमेटी ने इनमें से 6 महाद्वीपों और 19 देशों के 35 बेहतरीन प्रयासों को शॉर्टलिस्ट किया। कड़ी स्क्रीनिंग के बाद, आखिरी पड़ाव में केवल 4 फाइनलिस्ट चुने गए, जिनमें से आंध्र प्रदेश की प्राकृतिक खेती के इस मॉडल ने दुनिया में पहला स्थान हासिल किया।

आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग की संस्था 'रैतु साधिकारा संस्था' द्वारा 2016 में शुरू किए गए एपीसीएनएफ की परिकल्पना किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने और उन्हें सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। वर्षों के दौरान, इस आंदोलन ने यह प्रदर्शित किया है कि महिलाओं के नेतृत्व वाली संस्थाओं, किसान-से-किसान सीखने की प्रक्रिया, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों और सरकार की मजबूत भागीदारी के माध्यम से प्राकृतिक खेती का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा सकता है।

एपीसीएनएफ के अनुभव को अब भारत के 22 राज्यों और दो देशों श्रीलंका और ज़ाम्बिया में साझा किया जा रहा है। यह प्राकृतिक खेती को समर्थन देने वाले एक विस्तार योग्य मॉडल के रूप में इसकी बढ़ती राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर सशक्त हुई ग्रामीण महिलाओं ने अपने परिवारों में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बदलाव की मजबूत नींव रखी है।

इस महा-अभियान की असली ताकत ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले 'किसान गुरु' हैं। राज्य के 10,000 से अधिक अनुभवी किसान खुद गुरु बनकर 18 लाख अन्य किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखा रहे हैं।

साथ ही, 1,000 से अधिक सक्रिय मार्गदर्शक और 700 से ज्यादा किसान शोधकर्ता इसके वैज्ञानिक आधार को मजबूत करने में जुटे हैं, जिन्हें राज्य सरकार के कृषि विभाग का पूरा सहयोग मिल रहा है।

वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, हजारों के मरने की आशंका

पीएम मोदी ने कहा- भारत हर संभव मदद के लिए तैयार

ब्लिट्ज ब्यूरो

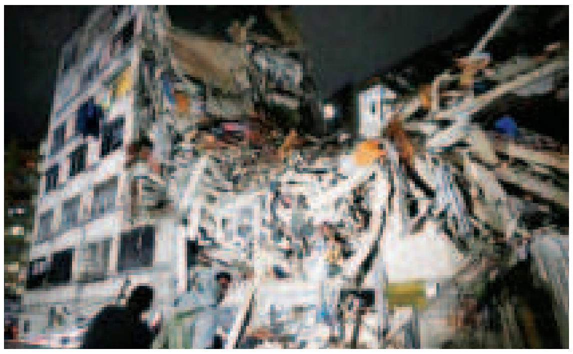

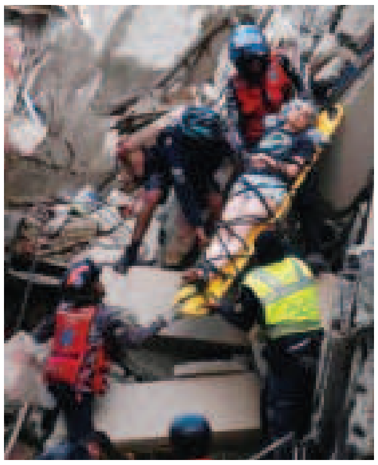

काराकास। वेनेजुएला में बुधवार को आए भयावह भूकंप में हजारों लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हजारों लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है।

इस दक्षिण अमेरिकी देश में आए दो भूकंप में अब तक 235 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी जबकि 4300 से ज्यादा लोग घायल हैं। वेनेजुएला में 25 जून को साल 1821 के काराबोबो युद्ध की याद में राष्ट्रीय अवकाश था। इसलिए ज्यादातर लोग घरों में थे और फीफा वर्ल्ड कप मैच देख रहे थे। इससे मलबे में दबने वालों की संख्या ज्यादा होने की आशंका है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मलबे के अंदर से आवाजें आ रही हैं। सरकार ने देर रात बताया कि 39 हजार से ज्यादा लोग लापता हैं। भूकंप की भयावहता की असल तस्वीर अभी आनी बाकी है। दोनों भूकंप राजधानी कराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए। इससे कई शहरों में इमारतें गिर गईं या खतरनाक तरीके से झुक गईं। कराकस एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। इससे धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। कई देशों से रेस्क्यू टीमें वेनेजुएला भेजी गई हैं। इनमें अल सल्वाडोर, चिली, इक्वाडोर और अमेरिका की टीमें मुख्य रूप से शामिल हैं।

अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10 हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। वहीं, एक लाख लोगों के जान गंवाने की भी 30% आशंका है।

इस आपदा से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को 9.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने आपातकाल लगा दिया है।

पीएम मोदी ने कहा कि वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप से हुई तबाही से बहुत दुख हुआ है। भारत के लोगों की तरफ से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति, और खासकर उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है।

ट्रंप ने भी किया मदद का वादा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विनाशकारी भूकंप के तुरंत बाद अमेरिकी मदद की पेशकश की। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, ₹वेनेजुएला में शक्तिशाली भूकंप का झटका आया है। इससे बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। अमेरिका मदद के लिए तैयार और इच्छुक है। मैंने अपनी सरकार की सभी एजेंसियों को तेजी से काम करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। हम अपने नए और महान दोस्तों के साथ खड़े रहेंगे। शुरुआती रिपोर्ट अच्छी नहीं हैं।

अमेरिका ने शुरू किया मदद का काम

अमेरिका ने वेनेजुएला के लिए आपातकालीन मदद जुटाना शुरू कर दिया है। विदेशी सहायता के लिए अंडर सेक्रेटरी जेरेमी लेविन ने कहा वेनेजुएला के लोगों तक जरूरी मदद पहुंचाने और उसका तालमेल बिठाने के लिए पहले ही एक आपदा सहायता टीम और टास्क फोर्स को काम पर लगा दिया है।

वेनेजुएला की अंतरिम सरकार में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, अमेरिका इस दुखद प्राकृतिक आपदा के बाद शुरुआती अहम दिनों में खोज और बचाव दल, चिकित्सा और मानवीय सहायता का सामान और अन्य संसाधन भेजेगा।

खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए पीएम मोदी को न्योता

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। ईरान में 4 जुलाई से पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार समारोह शुरू होंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा है।

अयातुल्ला खामेनेई की 28 फरवरी को इजराइल-अमेरिका के हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद 4 मार्च को उनका अंतिम संस्कार होना था लेकिन जंग की वजह से इसे टाल दिया गया था।

अब इसकी शुरुआत 4 जुलाई से होगी। उनके शव को तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में दफन किया जाएगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि तेहरान, कुम और मशहद में होने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। तेहरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यालय के पास उनकी कुर्सी और एक तस्वीर प्रदर्शित की गई है।

मोदी का ईरान जाने पर सस्पेंस

ईरान ने अंतिम संस्कार समारोह के लिए दुनिया के कई देशों को निमंत्रण भेजा है। खास तौर पर पड़ोसी और मित्र देशों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

फिलहाल यह साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं।

यूएस में एआई सप्लाई चेन पर समझौता भारत समेत 35 देशों ने किए हस्ताक्षर

वाशिंगटन। भारत समेत 35 देशों ने एआई प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए विश्वसनीय और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित करने के लिए अमेरिकी पहल का समर्थन करते हुए 'एआई अवसर' संबंधी संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

द्वितीय पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में 35 देशों ने इस संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर विकासोन्मुखी और नवाचार समर्थक नियामकीय दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।

कनाडा ने माना, एअर इंडिया फ्लाइट ब्लास्ट खालिस्तानियों ने किया

ओटावा। कनाडा ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना है कि 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 'कनिष्क' में हुए बम धमाके के पीछे कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों का हाथ था। कनाडा की खुफिया एजेंसी कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने इस घटना को 'जघन्य आतंकवादी काम' बताया है।

23 जून को इस घटना के 41 साल पूरे होने पर सीएसआईएस ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एजेंसी ने लिखा,

आतंकवाद के पीड़ितों की राष्ट्रीय स्मृति दिवस पर हम एयर इंडिया फ्लाइट 182 के उन 329 लोगों को याद करते हैं, जिन्होंने एक जघन्य आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई।

इस हादसे में विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 268 कनाडाई नागरिक थे, जिनमें ज्यादातर भारतीय मूल के थे। 24 लोग भारत के नागरिक थे।

23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 'कनिष्क' मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए नई दिल्ली आ रही थी। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचने से करीब 45 मिनट पहले आयरलैंड के तट के पास अटलांटिक महासागर के ऊपर विमान में जोरदार विस्फोट हुआ और विमान हवा में ही टूटकर समुद्र में गिर गया। इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। विस्फोटक एक सूटकेस में छिपाकर विमान के चेक-इन बैगेज में रखा गया था। यह सूटकेस जिस यात्री के नाम से चेक-इन हुआ था, वह खुद विमान में सवार ही नहीं हुआ। जांच में निष्कर्ष निकला था कि हमला 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के जवाब में किया गया था।

बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फिर शुरू होगी टूरिस्ट वीजा सेवा

ब्लिट्ज ब्यूरो

ढाका। भारत ने लगभग दो साल बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को घोषणा की कि 28 जून से बांग्लादेश के पांच वीजा आवेदन केंद्रों के जरिए सामान्य टूरिस्ट वीजा आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इससे पहले सुरक्षा कारणों के चलते भारतीय उच्चायोग ने वीजा संबंधी गतिविधियों को सीमित कर दिया था।

भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (आईवीएसी) में घोषणा करते हुए दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि टूरिस्ट वीजा के लिए सामान्य आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा रही है। इसके तहत रविवार 28 जून से आवेदन जमा किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मानवीय आधार पर मेडिकल वीजा की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।

पांच केंद्रों से शुरू होगी सेवा

उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में ढाका, राजशाही, चटगांव, सिलहट और खुलना स्थित पांच वीजा केंद्रों से टूरिस्ट वीजा जारी किए जाएंगे। भविष्य में इस व्यवस्था का और विस्तार किया जाएगा। इस कदम से दोनों संप्रभु देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध और मजबूत होंगे।

राष्ट्रपति को सौंपा परिचय पत्र

ढाका में नियुक्त भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को बंगभवन में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय पत्र सौंपा इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि वे अपने कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। इसके बाद त्रिवेदी ने जमुना फ्यूचर पार्क स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन संेटर का दौरा किया और वहीं से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा सेवा बहाल करने की घोषणा की।

सीमित करनी पड़ी थीं सेवाएं

5 अगस्त 2024 को धनमंडी स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई थी। इसके अलावा बांग्लादेश के विभिन्न शहरों में पांच इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर हमले हुए थे। विकास परियोजनाओं पर काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों को भी हमले की धमकियां मिली थीं। सुरक्षा खतरों और भारतीय उच्चायोग परिसर पर हमलों के कारण भारत को बांग्लादेश में वीजा संबंधी गतिविधियां सीमित करनी पड़ी थीं।

हालांकि, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत आने वाले लोगों की मानवीय जरूरतों को देखते हुए भारतीय उच्चायोग ने ढाका, चटगांव, खुलना, सिलहट और राजशाही में वीजा केंद्रों का संचालन जारी रखा। भारत टूरिस्ट वीजा को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों में प्रतिदिन 1,500 से अधिक वीजा जारी करता रहा।

9वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाएगी 'इमरजेंसी'

6 से 10वीं तक की नई किताबें जारी कर रही एनसीईआरटी

ब्लिट्ज ब्यूरो

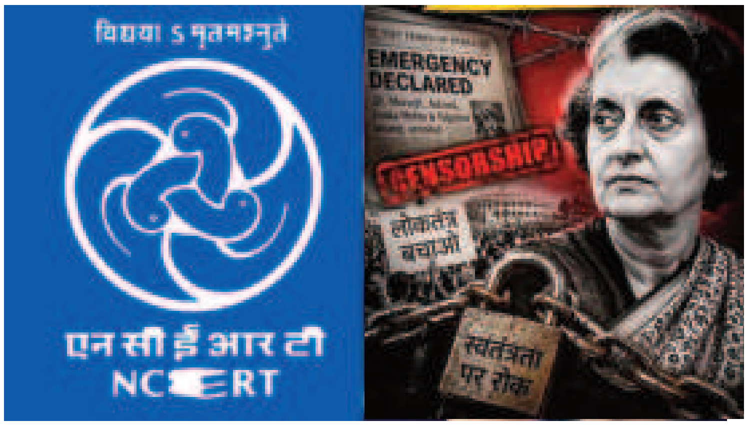

नई दिल्ली। एनसीईआरटी ने पहली बार 1975-77 की इमरजेंसी को 9वीं क्लास की बुक में शामिल किया है। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 9वीं की सोशल साइंस की नई बुक 'अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड' में पहली बार सेकेंडरी स्कूल के सिलेबस में इमरजेंसी का जिक्र किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि क्लास 9 की पिछली किताब में इमरजेंसी को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बदले हुए सिलेबस में इसके लिए एक अलग सेक्शन जोड़ा गया है। आपातकाल पर चैप्टर शामिल किए जाने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'यह सही है। एनसीईआरटी ने बिल्कुल सही किया है। आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के काले कारनामों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने। इसीलिए ऐसा किया जा रहा है।

9वीं की सोशल साइंस बुक में क्या-क्या

बताया गया है कि 'अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड' के चैप्टर में इमरजेंसी को लोकतांत्रिक ताकतों और कमजोरियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। बुक में 1970 के दशक की शुरुआत के राजनीतिक असंतोष-जिसमें आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार से बढ़ती निराशा और उसके बाद हुई घटनाओं की की जानकारी दी जाएगी।

इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान फेक न्यूज, गलत जानकारी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, गरीबी, क्षेत्रवाद, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों को जोड़ा गया है।

'इंदिरा गांधी की इमरजेंसी' पर क्या बताया गया है?

बुक में इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर बताया कि 1970 के दशक की शुरुआत में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार से लोग खुश नहीं थे। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और कई खराब नीतियों के आरोपों की वजह से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। भारत में लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक तब आई जब 1975-77 में इमरजेंसी लागू की गई।

इमरजेंसी काल में सरकार ने क्या किया?

9वीं की बुक में आगे कहा गया है, 'जून 1975 में, सरकार ने आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लागू की। इस दौरान, ज्यादातर मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भारी दबाव पड़ा और नागरिकों की आजादी सीमित कर दी गई।'

जेपी नारायण को बताया लोक नायक

नई बुक में जयप्रकाश नारायण को लोक नायक बताया गया है। नए चैप्टर में उन्हें अहमियत देते हुए एक वरिष्ठ समाजवादी नेता और 'लोक नायक' के नाम से मशहूर बताया गया है।

किताब में कहा गया है, 'लोक नायक के नाम से मशहूर राजनीतिक नेता और समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले जन-आंदोलनों ने छात्रों और नागरिकों, खासकर बिहार और गुजरात में, लोगों को एकजुट किया।

1977 में इमरजेंसी हटाई गई और आम चुनाव हुए, जिससे लोगों को वोट के जरिए अपनी राय जाहिर करने का मौका मिला। सत्ताधारी सरकार की हार ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत दिखाई और लोकतंत्र के महत्व को उजागर किया।'

नए सेक्शन भी जोड़े गए

नई बुक, इमरजेंसी से आगे बढ़कर भारत में लोकतांत्रिक प्रथाओं की जड़ों को प्राचीन काल से जोड़कर देखती है और संवैधानिक संस्थाओं के विकास का खाका खींचती है। इसमें दो नए सेक्शन 'लोकतंत्र और आप' व 'लोकतंत्र का चौथा स्तंभ' जोड़े गए हैं। 'लोकतंत्र और आप' से छात्र क्लास में सीखी गई बातों को अपने नागरिक कर्तव्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका से जोड़कर समझ सकें।

इसके अलावा 'लोकतंत्र का चौथा स्तंभ', सत्ता को जवाबदेह ठहराने और जनता की शिकायतों को लोकतांत्रिक चर्चा का हिस्सा बनाने में मीडिया की भूमिका को समझ सकें।

पुरोहितों को प्रशिक्षण देकर पूजा पद्धति को लिपिबद्ध कराएगी विहिप

प्रयागराज। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने धर्म प्रसार के कार्यों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। पुजारियों को प्रशिक्षण देने की योजना को विस्तार दिया जाएगा। अभी अयोध्या और काशी में इस तरह की सीमित गतिविधियां चल रही हैं। अब प्रखंड स्तर पर पुजारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा।

उनकी पूजा पद्धति उन्हीं की भाषा में लिपिबद्ध कराने की तैयारी है जिससे वह विलुप्त न होने पाए। ऐसे मंत्र या विधियां जो पूर्व में प्रचलित थीं, उन्हें भी सर्वसुलभ बनाने की दिशा में प्रयास होगा। खास बात यह भी है कि विभिन्न मंदिरों के लिए सभी जातियों के पुजारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। संगठन की प्रांत कार्य समिति का प्रत्येक कार्यकर्ता एक जाति को गोद लेकर उनके बीच संपर्क बनाएगा।

पासपोर्ट केवल यात्रा का दस्तावेज नागरिकता का सबूत नहीं : विदेश मंत्रालय

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट केवल यात्रा और पहचान संबंधी दस्तावेज है, न कि भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण। पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर मंत्रालय ने यह भी कहा कि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन नागरिकता के निर्धारण संबंधित कानूनों और अन्य वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है।

नागरिकता पर मंत्रालय की सफाई

मंत्रालय की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब विभिन्न मंचों पर पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के रूप में लेकर भ्रम की स्थिति देखी जाती रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला दस्तावेज है।

1.5 करोड़ लोगों को मिली सेवाएं

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और विदेशों में भारतीय मिशनों ने मिलकर करीब 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान कीं। सरकार लगातार पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सरल, तेज और सुलभ बनाने पर काम कर रही है।

545 केंद्रों तक पहुंचा नेटवर्क

देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की संख्या बढ़कर 545 हो गई है। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र शुरू किए जाने की योजना है।

कई मामलों में पांच दिन में पासपोर्ट

अधिकारियों ने बताया कि पासपोर्ट सेवा प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। कई मामलों में पासपोर्ट जारी होने का समय घटकर पांच कार्यदिवस तक पहुंच गया है। वहीं, पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर आवेदकों को 45 मिनट से कम समय में प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा मिल रही है।

भारतीय पासपोर्ट की बढ़ी पहुंच

मंत्रालय के अनुसार भारतीय नागरिकों को फिलहाल 27 देशों में वीजा-फ्री प्रवेश, 47 देशों में वीजा ऑन अराइवल और 66 देशों में ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध है।

केवल 10 प्रतिशत भारतीयों के पास पासपोर्ट

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि देश की कुल आबादी की तुलना में अभी लगभग 10 प्रतिशत भारतीयों के पास ही पासपोर्ट हैं।

मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1.47 करोड़ चिप-युक्त ई-पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक चिप और उन्नत बायोमेट्रिक सुरक्षा तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे दस्तावेजों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ी है।

सेना ने हटाए गुलामी के निशान, परेड में तलवार रखना जरूरी नहीं

आर्मी यूनिफॉर्म्स-2026 मैनुअल बदला

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने औपनिवेशिक दौर की परंपराओं से दूरी बनाते हुए अपनी वर्दी और ड्रेस नियमों में व्यापक बदलाव किए हैं। नए मैनुअल आर्मी यूनिफॉर्म्स-2026 में बंदी जैकेट को औपचारिक नागरिक परिधान का हिस्सा बनाया गया है। कई पुराने प्रतीकों और शब्दों को हटाया गया है।

सेना ने ड्रेस नंबर-5 और ड्रेस नंबर-6 से पाउच बेल्ट हटाने का फैसला किया है। परेड के दौरान रिव्यूइंग अधिकारी के लिए तलवार साथ रखना अब अनिवार्य नहीं होगा। रॉयल जैसे औपनिवेशिक शब्दों का इस्तेमाल भी बंद कर दिया गया है। मैनुअल में कहा गया है कि ये बदलाव भारत की बदलती संप्रभु पहचान और राष्ट्रीय भावना के अनुरूप किए गए हैं। महिला कर्मियों के लिए लिपस्टिक, रंगीन नाखूनी, बिंदी और नोज पिन पर रोक लगाई गई है। सिंदूर लगाया जा सकता है, लेकिन वह बेरेट या पीक कैप के बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए। गौरतलब है कि 2023 में भी सेना ने घोड़ा-गाड़ी, सेवानिवृत्ति समारोहों की कुछ पुरानी परंपराओं और पाइप बैंड जैसी औपनिवेशिक प्रथाओं को समाप्त किया था।

बंदी जैकेट को मिली आधिकारिक मंजूरी

नियमों के तहत अधिकारियों को अब पूरी आस्तीन की शर्ट के ऊपर बंद गले वाली बंदी जैकेट पहनने की अनुमति होगी। इसके साथ सादे रंग की फॉर्मल पैंट और बंद जूते पहनने होंगे। सेना का कहना है कि यह भारतीय पहचान को औपचारिक परिधान में शामिल करने की दिशा में कदम है।

सेना ने सभी रैंकों के लिए नई सर्दियों की वर्दी भी शुरू की है। इसमें बैटल जैकेट को मानक विंटर आउटरवियर बनाया गया है। यह मौजूदा जर्सी आधारित ड्रेस उए की जगह लेगी।

टैटू, मूंछ और मेकअप पर सख्त नियम

मैनुअल में व्यक्तिगत साज-सज्जा को लेकर भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। टैटू, बॉडी पियर्सिंग, बिना अनुमति दाढ़ी, असामान्य हेयरस्टाइल और यूनिफॉर्म में दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर रोक लगाई गई है। मूंछें 12 सेंटीमीटर से अधिक लंबी नहीं हो सकतीं। यूनिफॉर्म में डिओडोरेंट और परफ्यूम के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।

वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंद में फिफ्टी लगाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

50 रन पूरे करने तक उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी ने वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी लगा दी है। उन्होंने ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ 11 गेंद में पचास रन पूरे किए। 50 रन पूरे करने तक उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 5 छक्के लगाए। वैभव अब तक ट्राई सीरीज में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए थे, लेकिन फाइनल में श्रीलंकाई बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। वैभव सूर्यवंशी ने पारी के चौथे ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।

गजब की बात यह रही कि वैभव ने बाउंड्री से ही अपना अर्धशतक पूरा किए और पहली 11 गेंदों में उन्होंने सिर्फ एक बॉल डॉट खेली। इससे पहले लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी 12 बॉल में आई थी। रिकॉर्ड श्रीलंका के बल्लेबाज कौशल्या वीररत्ने के नाम पर था जिन्होंने 12 गेंदों में अर्धशतक लगाया था।

हालांकि सूर्यवंशी शतक लगाने से चूक गए। वैभव (94) की इस तूफानी शुरुआत के चलते इंडिया ए टीम ने ट्राई सीरीज के फाइनल में 9 विकेट खोकर 377 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ए टीम 47.1 ओवर में

वैभव ने श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल में 29 गेंद खेलकर 94 रन बनाए

311 रन ही बना सकी। तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल मैच 66 रन से जीता। इस सीरीज में सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर थी। खासतौर पर इसलिए, क्योंकि उन्हें इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में चुना गया है। मगर पहले चार मैचों में उनके स्कोर 14, 44, 21, 38 रहे। वो चार मुकाबलों में केवल 117 रन बना पाए थे, लेकिन फाइनल में उन्होंने धुआंधार बैटिंग करते हुए सभी आलोचकों का मुंह बंद करने का काम किया।

वैभव सूर्यवंशी को अलग चेंजिंग रूम मिलेगा, परिवार भी होटल में साथ रहेगा

15 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर अलग चेंजिंग रूम मिलेगा। ईसीबी के अधिकारी ने ब्रिटिश अखबार द गार्डियन को बताया कि उनकी फैमिली भी टीम होटल में उनके साथ ही रहेगी। हालांकि, वैभव मैचों के दौरान टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ रह सकेंगे। वे टीम मीटिंग्स में हिस्सा भी लेंगे। यह फैसला आईसीसी की चाइल्ड सेफगार्डिंग पॉलिसी के कारण लिया है।

रोनाल्डो 6 वर्ल्डकप में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने

पुर्तगाल के लिए टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड बनाया

ब्लिट्ज ब्यूरो

ह्यूस्टन। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 फुटबॉल वर्ल्डकप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 41 साल के रोनाल्डो ने ह्यूस्टन स्टेडियम में उज्बेकिस्तान के खिलाफ छठे मिनट में गोल दागकर यह रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद उन्होंने 39वें मिनट में दूसरा गोल भी किया। इन्हीं गोल की मदद से पुर्तगाल ने 5-0 की जीत हासिल की।

रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर भी बने। उनके नाम 10 गोल हैं। उन्होंने पुर्तगाल के स्ट्राइकर यूसेबियो के 9 गोल को पीछे छोड़ा।

रोनाल्डो ने 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और अब 2026 वर्ल्डकप में गोल किया है।

मेसी ने नौ गोल किए

रोनाल्डो के बाद अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी का नाम अपने देश के लिए विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वालों में दर्ज है। उन्होंने 2010 को छोड़कर 2006, 2014, 2018, 2022 और 2026 वर्ल्ड कप में गोल किए हैं।

पुर्तगाल का श्रेष्ठ प्रदर्शन

पुर्तगाल के लिए रोनाल्डो के अलावा नूनो मेंडेस (17वें मिनट) और राफेल लेओ (87वें मिनट) ने गोल किया। 59वें मिनट में उज्बेकिस्तान के गोलकीपर अब्दुवोहिद नेमातोव से बॉल टकराकर गोल में चली गई। इसे ओन गोल माना गया।

चंपारण के सारांश ने विश्व योगासन चैम्पियनशिप में जीता स्वर्ण

ब्लिट्ज ब्यूरो

चंपारण। पश्चिम चंपारण के सारांश कुमार ने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैम्पियनशिप में रिदमिक पेयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जिले और बिहार का नाम रोशन किया है।

मजदूर परिवार से विश्व मंच तक

सारांश कुमार योगापट्टी अंचल के भवानीपुर गांव निवासी जितेंद्र राम और रुना देवी के पुत्र हैं। उनके पिता मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। सारांश वर्तमान में बेतिया स्थित लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में नौवीं कक्षा के छात्र हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर विश्व स्तर की प्रतियोगिता में सफलता हासिल की है।

तमिलनाडु के सर्वेश के साथ बनाई स्वर्णिम जोड़ी

योगासन स्पोर्ट्स एकेडमी के संचालक, राष्ट्रीय योगासन रेफरी और सारांश के प्रशिक्षक पवन कुमार चौधरी ने बताया कि भारतीय टीम में शामिल सारांश कुमार ने तमिलनाडु के खिलाड़ी सर्वेश के साथ रिदमिक पेयर स्पर्धा में भाग लिया।

दोनों खिलाड़ियों की शानदार प्रस्तुति ने निर्णायकों को प्रभावित किया और भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि के बाद लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल और योगासन स्पोर्ट्स एकेडमी में खुशी का माहौल है।

78 देशों के खिलाड़ियों के बीच चमका भारत

प्रथम विश्व योगासन चैम्पियनशिप 2026 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। प्रतियोगिता में विश्व के 78 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

प्रतियोगिता में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 114 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया।

स्कूल और एकेडमी में जश्न का माहौल

सारांश की इस उपलब्धि के बाद उनके स्कूल, प्रशिक्षकों और परिजनों में खुशी की लहर है। शिक्षकों और सहपाठियों ने उनकी सफलता पर बधाई दी है।

प्रशिक्षक पवन कुमार चौधरी ने कहा कि सारांश की मेहनत, अनुशासन और लगातार अभ्यास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में सारांश और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे।

घास काटने वाली पहाड़ की बेटी टी-20 वर्ल्ड कप में

ब्लिट्ज ब्यूरो

देहरादून। कपकोट के दूरस्थ सुमटी गांव की पहाड़ियों पर दौड़ती एक छोटी-सी बच्ची भारतीय महिला टी-20 टीम में शामिल हो गई हैं। कभी भाइयों के साथ खेतों, आंगन और गली-मोहल्लों में क्रिकेट खेलने वाली प्रेमा रावत अब विश्व कप में भारत की जर्सी पहनकर उतरेंगी।

24 वर्षीय प्रेमा का भारतीय टीम में चयन सिर्फ एक खिलाड़ी की उपलब्धि नहीं, बल्कि पहाड़ के उस सपने की कहानी है, जो सीमित संसाधनों के बीच भी बड़ा होने का साहस रखता है। प्रेमा रावत बचपन में घास काटने और खेतों के काम में परिवार का हाथ बंटाती थीं।

भाइयों के साथ खेलते-खेलते सीखा क्रिकेट

प्रेमा ने कक्षा दो तक की पढ़ाई गांव के प्राथमिक विद्यालय में की। बाद में परिवार बरेली चला गया। बचपन में वह अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेलती थीं। घर के आंगन, खेतों और खाली मैदानों में शुरू हुआ खेल धीरे-धीरे उनका जुनून बन गया। परिवार ने कभी यह नहीं कहा कि क्रिकेट लड़कियों का खेल नहीं है। पिता केदार सिंह रावत, जो एयरफोर्स में कार्यरत हैं और मां बसंती देवी ने हर कदम पर उनका साथ दिया।

डांट भी सुनी, लेकिन नहीं छोड़ा बल्ला

गांव में जब अधिकांश लड़कियां पारंपरिक कामों तक सीमित रहती थीं, तब प्रेमा के हाथों में बल्ला और गेंद हुआ करती थी। कई बार गेंद खेतों में चली जाती, पड़ोसियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ती, लेकिन उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। मई-जून की तेज गर्मी में भी बरेली के मैदानों में घंटों अभ्यास करना उनकी दिनचर्या बन गया। छुट्टियों में गांव आने पर भी वह मालूखेत मिनी स्टेडियम में युवाओं के साथ अभ्यास करना नहीं भूलती थीं।

क्रिकेटर भी, घास काटने वाली भी

मां बसंती देवी बताती हैं कि क्रिकेट में नाम कमाने के बाद भी प्रेमा गांव की बेटी ही बनी हुई हैं। उन्हें घास काटना, खेतों की निराई-गुड़ाई करना और मवेशियों की देखभाल करना भी आता है। यही सादगी और जमीन से जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रेमा ने अपनी अलग पहचान बनाई और एक-एक सीढ़ी चढ़ते हुए राष्ट्रीय टीम तक पहुंचीं।

ऑपरेशन सिंदूर में बलिदान हुए थे 6 वीर सपूत

ब्लिट्ज ब्यूरो

केंद्र सरकार ने पहली बार सार्वजनिक किए जांबाजों के नाम

नई दिल्ली। सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना के उन 6 वीर सैनिकों के नामों का खुलासा किया है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए बलिदान हो गए थे। पिछले साल मई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए यह सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया गया था।

इन छह बलिदानियों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की वेबसाइट पर रोल ऑफ ऑनर खंड में प्रकाशित किए गए हैं, और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में भी इन्हें अंकित किया गया है। यह पहली बार है जब सरकार ने इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों को हुए नुकसान को सार्वजनिक और आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित हुए नाम

नेशनल वॉर मेमोरियल वेबसाइट के मुताबिक, बलिदानों के नाम स्मारक की वॉल 3डी पर साल 2025 के खंड में उकेरे गए हैं, जो उन सैन्य कर्मियों को समर्पित है जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी।

OPERATION
SINDOOR

पहलगाम हमले के बाद शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर

ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 7 मई, 2025 की सुबह तड़के हुई थी। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले के कुछ हफ्तों बाद की गई थी, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे।

इस अभियान के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। इन हमलों में मुख्य रूप से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। इसके बाद, दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों के बीच हुई बातचीत के बाद 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी थी।

थलसेना और वायुसेना के जांबाज शामिल

सामने आए नामों से साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थलसेना और भारतीय वायुसेना दोनों के जवानों ने शहादत दी थी। यह इस सैन्य अभियान की बहु-सेवा समन्वय और संयुक्त प्रकृति को दर्शाता है।

बलिदान देने वालों में राइफलमैन सुनील कुमार शामिल हैं, जिन्हें वीरता के लिए वीर चक्र से नवाजा गया था और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार वायु सेना पदक के प्राप्तकर्ता थे। यह इस पूरे ऑपरेशन में वीरता पुरस्कार से सम्मानित जांबाजों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

इंडिया गेट के पास 2019 में उद्घाटित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सैन्य अभियानों और संघर्षों में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों की स्मृति को संजोए रखता है।

इन छह नामों के जुड़ने के साथ ही अब ऑपरेशन सिंदूर को भी स्मारक पर आधिकारिक तौर पर उन ऐतिहासिक सैन्य अभियानों में स्थान मिल गया है जिन्हें देश हमेशा याद रखेगा।

देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जांबाज

मुख्यालय 10 इन्फैंट्री ब्रिगेड सूबेदार मेजर पवन कुमार, 4 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री राइफलमैन सुनील कुमार, 5 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार, 851 लाइट रेजिमेंट के एविएशन टेक्निशियन मुरलीनायक, 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, वायु सेना पदक (39 विंग) शामिल हैं।

पेज 1 के शेष

सिर्फ दो साल में ही कैसे गंवा दी इंग्लैंड की सत्ता?

जीवन-यापन महंगा था। कारोबारियों का भरोसा कमजोर था। सरकारी खजाने पर दबाव था। विकास की बातें हो रही थीं लेकिन उसका असर आम परिवारों तक नहीं पहुंच रहा था।

स्टार्मर ने वादा किया था कि वे अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं को सुधारने की भी बात कही थी लेकिन कई वोटरों को लगा कि देश अब भी वहीं अटका हुआ है।

इमिग्रेशन भी उनकी सरकार के लिए बड़ा मुद्दा बन गया। सरकारी आंकड़ों में नेट माइग्रेशन पहले से कम दिख रहा था लेकिन जनता की चिंता अलग थी।

लोग छोटी नावों से आने वाले अवैध प्रवासियों, असायलम होटलों और बॉर्डर कंट्रोल को लेकर परेशान थे। रिफॉर्म यूके ने इस मुद्दे को बहुत आक्रामक तरीके से उठाया। लेबर पार्टी लोगों को भरोसा नहीं दिला पाई कि उसने सीमाओं पर नियंत्रण वापस पा लिया है। इमिग्रेशन पर स्टार्मर की भाषा ने दोनों तरफ नाराजगी पैदा की। कुछ लेबर समर्थक नाराज हुए। वहीं सख्त कार्रवाई चाहने वाले वोटर भी संतुष्ट नहीं हुए। इस तरह स्टार्मर दो तरफा दबाव में फंस गए। रिफॉर्म यूके उन्हें सीमाओं पर कमजोर बता रही थी। वह कह रही थी कि स्टार्मर कामकाजी वर्ग की चिंताओं से कट गए हैं।

दूसरी ओर लेबर पार्टी के अंदर भी नाराजगी बढ़ रही थी। सेंटर-लेफ्ट और लेफ्ट के नेता उन्हें कमजोर और कम भावनात्मक नेता मानने लगे थे। आलोचकों का कहना था कि उनके पास देश के लिए कोई साफ और मजबूत मिशन नहीं दिख रहा।

एंडी बर्नहम के उभार ने यह स्थिति और गंभीर कर दी। ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर के रूप में उनकी छवि जनता से सीधे जुड़े नेता की रही है। वे क्षेत्रीय राजनीति को समझते हैं। वे आम लोगों की भाषा बोलते हैं। इसलिए कई लेबर सांसद उन्हें रिफॉर्म यूके का बेहतर जवाब मानने लगे।

स्टार्मर का इस्तीफा सिर्फ एक नेता की हार नहीं है। यह ब्रिटेन की राजनीतिक अस्थिरता को भी दिखाता है। देश में बार-बार प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। जनता अधीर है। अर्थव्यवस्था पर दबाव है। इमिग्रेशन पर बहस और तेज हो गई है।

स्टार्मर का पतन यह बताता है कि आज के ब्रिटेन में भारी बहुमत भी सत्ता में बने रहने की गारंटी नहीं है। उनके इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह थी लेबर पार्टी के भीतर विश्वास का खत्म होना, लेकिन इस विश्वास के टूटने के पीछे कई कारण थे। इनमें आर्थिक निराशा, इमिग्रेशन का दबाव और यह धारणा भी बढ़ गई थी कि बदलाव का वादा लोगों तक तेजी से नहीं पहुंचा।

स्टार्मर के जाने से भारत-ब्रिटेन संबंधों पर असर

ब्रिटेन सरकार के अनुसार यह एफटीए 15 जुलाई 2026 से लागू होगा।

- इस समझौते से लंबे समय में दोनों देशों के व्यापार में हर साल 25.5 अरब पाउंड तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसका मकसद टैरिफ कम करना है। कस्टम प्रक्रिया को आसान बनाना और भारत-ब्रिटेन के कारोबारियों को ज्यादा सुविधा देना है।
- भारत के लिए ब्रिटेन में नेतृत्व बदलाव तीन क्षेत्रों में अहम होगा। पहला, व्यापार समझौते को कैसे लागू किया जाता है। दूसरा, इमिग्रेशन नीति किस दिशा में जाती है। तीसरा, रणनीतिक सहयोग कितना मजबूत रहता है।
- अगर एंडी बर्नहम या कोई और लेबर नेता प्रधानमंत्री बनता है, तो भारत यह देखेगा कि नई सरकार स्टार्मर की भारत-नीति को आगे बढ़ाती है या नहीं।
- अगर ब्रिटेन इमिग्रेशन पर ज्यादा सख्त रुख अपनाता है तो भारतीय छात्रों, कामगारों और पेशेवरों पर असर पड़ सकता है। हालांकि व्यापार समझौते के तहत बिजनेस मोबिलिटी से जुड़े प्रावधान सुरक्षित रह सकते हैं।
- रक्षा, टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, हेल्थकेयर और शिक्षा के क्षेत्र में रिश्ते जारी रहने की उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि ये संबंध किसी एक नेता पर निर्भर नहीं हैं। ये दोनों देशों के लंबे समय के राष्ट्रीय हितों से जुड़े हैं।
- कुल मिलाकर स्टार्मर का जाना थोड़ी अनिश्चितता जरूर पैदा कर सकता है। लेकिन भारत-ब्रिटेन साझेदारी स्थिर रहने की संभावना है। यह रिश्ता आगे भी व्यावहारिक, व्यापार-केंद्रित और रणनीतिक बना रहेगा।
- एफटीए से जुड़े आंकड़े ब्रिटेन सरकार के ट्रेड-डील सारांश पर आधारित हैं। वहीं रॉयटर्स के अनुसार कीर स्टार्मर के पद छोड़ने के बाद की प्रक्रिया को वास्तव में एक व्यवस्थित सत्ता हस्तांतरण (ऑर्डर्ली ट्रांसफर) के रूप में ही संभाला जा रहा है।

नए भारत का रोडमैप

क्योंकि उनका काम केवल हर काम का विरोध करना ही है।

नक्सलवाद ले रहा अंतिम सांसें

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा; "जिन नक्सल प्रभावित इलाकों में जाने से दिन में भी लोग डरते थे, वहां हम 'नेशन फर्स्ट' की स्पिरिट के साथ विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं। इसी का परिणाम है कि आज देश में माओवादी आतंक अंतिम सांसें गिन रहा है। यहां यह याद दिलाना भी जरूरी है कि जो लोग आज संविधान की प्रति हाथ में लेकर चलते और उसकी दुहाई देते फिरते हैं पर जब उनकी सरकार वहां थी और लोगों की जान नक्सली हिंसा में जा रही थी; तब उन्हें संविधान याद कभी नहीं आया।

सरकार के 12 वर्षों के कामकाज पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों के अभियान जैसी बड़ी राष्ट्रीय पहल इसलिए सफल हुई क्योंकि नागरिकों ने 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को अपनाया और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में वे अब अभूतपूर्व प्रगति देख रहे हैं।

एक उम्मीदों से भरे भारत के उदय पर जोर देते हुए पीएम ने कहा कि देश निराशा के दौर से निकलकर आत्मविश्वास और अवसरों के दौर में आ गया है। पीएम मोदी ने बताया, 'आकांक्षी जिले' (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स) और आकांक्षी विकासखंड (एस्पिरेशनल ब्लॉक्स) कार्यक्रम ने देश के कुछ सबसे पिछड़े इलाकों को विकास का इंजन बना दिया है। हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने और एक बड़े नए मध्यम वर्ग के उभरने से आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिली है और अलग-अलग क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं।

उन्होंने कहा कि जहां नागरिक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और मौकों की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ समूह विकास की पहलों का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं, उद्यमियों, इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स से इन अवसरों का लाभ उठाने और देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों और आकांक्षाओं से 'विकसित भारत' का सपना साकार होगा।

यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सहायक सचिव के रूप में नियुक्त 2024 बैच के आईएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं से विचार साझा करते हुए सरकार के दृष्टिकोण से भी उन्हें अवगत कराया कि वे 'नागरिक देवो भव' के मंत्र पर कार्य करें। विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अंतर्गत विकसित भारत का निर्माण करना आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि आज भारत की प्राथमिकताओं में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और युवाओं के लिए अवसरों का सृजन शामिल हैं।

ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की 16वीं बैठक के बाद प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भारत एक अधिक सुरक्षित, संरक्षित और समावेशी विश्व के निर्माण में योगदान देगा रहेगा।

विकास की पत्रकारिता का अग्रदूत
ब्लिट्ज
इंडिया

पश्चिम एशिया संकट ने चुपचाप बदल दिया भारत के व्यापार का नक्शा

ओमान उछलकर टॉप 10 में पहुंचा

आस्था भट्टाचार्य

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया के संघर्ष ने बड़ा बदलाव कर दिया है। इसने चुपचाप भारत के व्यापार के नक्शे को चेंज किया है। इस उलटफेर में ओमान बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) नीचे फिसला है। हाल में भारत ने ओमान के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) किया है।

अप्रैल-मई 2025 के दौरान ओमान भारत के लिए आयात का 30वां सबसे बड़ा सोर्स था। चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में एनर्जी की वजह से ओमान 10वें स्थान पर आ गया। कारण है कि आयात 3.8 गुना बढ़कर 3.4 अरब डॉलर हो गया।

यूएई चौथे पायदान पर खिसका

इसके उलट, अप्रैल-मई के दौरान यूएई चौथे स्थान पर खिसक गया, जबकि रूस दूसरे स्थान पर लौट आया और उसके बाद अमेरिका का स्थान रहा।

अमेरिका के ऊपर आने के पीछे भारत की एलपीजी या खाना पकाने वाली गैस की जरूरत है। वहीं, एनर्जी ने इस दौरान ब्राजील से आयात को भी 2.8 गुना बढ़ाकर 2.7 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद की।

पेरू से शिपमेंट में 3.7 गुना की बढ़ोतरी

वाणिज्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पेरू से शिपमेंट भी 3.7 गुना ज्यादा यानी 2 अरब डॉलर से अधिक रहे। दक्षिण अमेरिकी देश अब आयात का 20वां सबसे बड़ा सोर्स है। वहीं, अप्रैल-मई 2025 में यह 35वें स्थान पर था।

निर्यात के मोर्चे पर भी व्यापार के क्रम में बदलाव आया है। अप्रैल-मई के दौरान सिंगापुर ने चीन और नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जगह बनाई। यह दूसरे स्थान पर मौजूद यूएई से 18 करोड़ डॉलर पीछे रहा।

कुछ और बदलाव भी हुए हैं:

- तंजानिया निर्यात के लिए आठवां सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया जबकि अप्रैल और मई 2025 में यह 25वें स्थान पर था।
- दक्षिण अफ्रीका 10वें स्थान पर रहा और एक साल में दो स्थान ऊपर चढ़ गया।
- वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि तेल और रत्न व आभूषण तंजानिया को निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले साल अप्रैल-मई में यह 80 करोड़ डॉलर से बढ़कर इस साल अब तक 2.2 अरब डॉलर हो गया है।
- पड़ोसी श्रीलंका अब 12वें स्थान पर है। वहां एक्सपोर्ट लगभग तीन गुना बढ़कर 1.8 अरब डॉलर हो गया है।

सिंगापुर को एक्सपोर्ट में भारी बढ़ोतरी

सिंगापुर को निर्यात में 2.2 गुना की बढ़ोतरी (5.1 अरब डॉलर तक) मुख्य रूप से इस द्वीप देश को तेल उत्पादों के निर्यात में उछाल के कारण हुई। यह पश्चिम एशिया में युद्ध से बुरी तरह प्रभावित हुआ। इससे उसे चीन से आगे निकलने में मदद मिली।

चीन के साथ व्यापार में भारत का एक्सपोर्ट 25% से ज्यादा बढ़ा, जो कम्युनिस्ट देश की सख्त पाबंदियों को देखते हुए कोई मामूली बात नहीं है।

ओमान इसलिए बन गया है खास

फारस की खाड़ी के लिए अहम कड़ी होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी का मतलब यह हुआ है कि ओमान इस इलाके के लिए एक तरह का गेटवे बन गया है।

मिडिल ईस्ट का नया बादशाह बना ईरान

अग्रवाल ने कहा कि खाड़ी देश ईरान ने अपने तीन बंदरगाहों को भारतीय सामानों के लिए खोल दिया है ताकि उन्हें यूएई समेत दूसरे देशों तक भेजा जा सके। इनमें सोहर, सलालाह और डुक्म शामिल हैं।

ओमान के साथ भारत ने इस महीने की शुरुआत में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) किया था।

भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश, पाकिस्तान टॉप टेन की सूची से बाहर

ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026 जारी, यूएस पहले, रूस दूसरे व चीन तीसरे स्थान पर

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। हर साल दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी होती है। इसमें 60 से अधिक पैमानों पर देशों की शक्तियों को आंका जाता है। इसके बाद एक रैंकिंग जारी की जाती है। इस साल 2026 की रैंकिंग में अमेरिका एक बार फिर शीर्ष पर काबिज है। इस साल की दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पाकिस्तान शामिल नहीं है। वहीं, भारत हर बार की तरह इस सूची में बना हुआ है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026 जारी हो गया है।

दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश

अमेरिका : दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। उसकी सैन्य और आर्थिक रूप से किसी भी दूसरे देश से तुलना नहीं की जा सकती है। अमेरिका का सैन्य बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिकी सेना की फायर पावर की बराबरी भी नहीं है।

रूस : दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड हैं। हालांकि, उसने अमेरिका से कम संख्या में न्यूक्लियर वारहेड को मिसाइलों पर तैनात किया है। उसे यूक्रेन युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

चीन: तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। वह आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है। संख्या के हिसाब से चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। इसके अलावा उसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना भी है।

भारत: भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। भारत की थलसेना दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में शुमार है। इसके अलावा भारत की वायु और नौसैनिक शक्ति भी तेजी से बढ़ रही है। भारत मिसाइलों पर भी तेजी से काम कर है और कई अलग-अलग तरीकों के हथियारों को ऑपरेट भी करता है। इसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं। भारत ने हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया था।

दक्षिण कोरिया: पांचवां सबसे शक्तिशाली देश है। दक्षिण कोरिया परमाणु शक्ति संपन्न न होते हुए भी गैर परमाणु क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है।

फ्रांस : छठा सबसे शक्तिशाली देश है। फ्रांस एविएशन और मिसाइलों के क्षेत्र में काफी आगे है। हथियारों में राफेल लड़ाकू विमान, एम-51 परमाणु मिसाइल, एएसएमपी-ए परमाणु क्रूज मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, मेटियोर मिसाइल प्रमुख हैं।

जापान : सातवां सबसे शक्तिशाली देश है। वह चीन और रूस के खतरों का सामना कर रहा है। वह टैंक, युद्धपोतों और रडार निर्माण जैसे क्षेत्रों में काफी आगे है।

यूनाइटेड किंगडम : आठवां सबसे शक्तिशाली देश है। वह परमाणु शक्ति संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां संचालित करता है।

तुर्की : नौवां सबसे शक्तिशाली देश है। उसकी सैन्य शक्ति में हाल के कुछ वर्षों में काफी इजाफा हुआ है। तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री काफी एडवांस मानी जाती है।

इटली : इटली दसवां सबसे शक्तिशाली देश है। इटली भी परमाणु शक्ति संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करता है।

'21वीं सदी की अहम और निर्णायक साझेदारी है भारत-अमेरिका रिश्ता'

ललित दुबे

वाशिंगटन। भारत और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। अमेरिका में भारत की उप प्रमुख मिशन नमग्या सी. खम्पा ने कहा है कि भारत-अमेरिका संबंध 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक साझेदारियों में से एक बन चुके हैं। कैपिटल हिल में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खम्पा ने कहा कि नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच बढ़ते रिश्तों की नींव साझा हितों, मजबूत आर्थिक सहयोग, तकनीकी साझेदारी, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर आधारित है।

उन्होंने कहा, "भारत-अमेरिका साझेदारी को 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारियों में से एक बताया जाता है और यह बात पूरी तरह सही है। इसका कारण यह नहीं है कि हम हर मुद्दे पर 100 प्रतिशत सहमत हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ मुद्दों पर मतभेद होते हैं, लेकिन इस रिश्ते के पीछे जो रणनीतिक सोच है, वह हर साल मजबूत होती जा रही है।"

खम्पा की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने, तकनीकी सहयोग को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा समन्वय को गहरा करने को लेकर बातचीत जारी है। सी. खम्पा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी भरे संबंध और मजबूत विश्वास का रिश्ता है।

भारतीय राजनयिक ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की हालिया भारत यात्रा का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय बैठकों के अलावा क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया था। सी. खम्पा ने कहा कि व्यापार दोनों देशों के रिश्तों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। दोनों पक्षों के वार्ताकार द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

RNI No. DELHIN/2022/85477 । संपादित, मुद्रित एवं प्रकाशित द्वारा दीपक द्विवेदी : द इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा- 201301 (उ.प्र.)। संपादकीय, विज्ञापन और प्रशासनिक कार्यालय : 8-बी, वंदना बिल्डिंग, 11 टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन नं.- 43502031, 43502032, ई-मेल: info@blitzindiamedia.com, **मुंबई ऑफिस** : 311-बी, आईएनएस टावर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051, बोर्ड चेयरमैन : अनिल वोहरा, मुख्य सलाहकार : ए.के. शर्मा, संपादक : विनोद शील, **निदेशक संपादकीय बोर्ड : राकेश शर्मा (समाचार व सभी संपादकीय निर्णयों के लिए पीआरबी एक्ट के अनुसार उत्तरदायी), चेयरमैन एवं प्रधान संपादक : दीपक द्विवेदी** (सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा)